संसेक्स	~ 82,000.71
निफ्टी	~ 25,083.75
सोना	~ 1,00,750
चांदी	~ 1,16,000
डॉलर	~ 87.32

बालाघाट एक्सप्रेस

हिन्दी दैनिक

बालाघाट
शुक्रवार 22 अगस्त 2025
भाद्रपद कृष्ण 14 विक्रम सम्वत 2082
वर्ष 16, अंक 328
पृष्ठ 12
मूल्य ₹ 7.00

E-mail: balaghatexpress@gmail.com
/padmeshmedia /padmeshmedia
epaper.balaghatexpress.in

खास खबर

दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर सतीश गोलचा बने

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर सतीश गोलचा होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। फिलहाल गोलचा तिहाड़ जेल के डीजी का पद संभाल रहे हैं। वे 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आईपीएस गोलचा दिल्ली पुलिस में स्पेशल सीपी (इंटेलिजेंस) के तौर पर भी काम किया है। वे डीसीपी, ज्वाइंट सीपी और स्पेशल सीपी जैसे पदों पर भी रह चुके हैं। गोलचा सीनियर आईपीएस अधिकारी एसबीके सिंह की जगह लेंगे। उनके पास 31 जुलाई से दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार था।

गणेश पंडाल का 474 करोड रुपए का बीमा

मुंबई। मुंबई में एक गणेश पंडाल का बीमा 474 करोड रुपए का कराया गया है। जीएसबी सेवा मंडल ने यह बीमा कराया है। पिछले वर्ष इसी सेवा मंडल द्वारा 400 करोड रुपए का बीमा कराया गया था। गणेश उत्सव में यह भारी भरकम पंडाल तैयार किया जाता है। इसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात के महंगे आभूषण गणेश प्रतिमा के साथ पंडाल में रहते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार सोने चांदी और हीरे जवाहरात की कीमतें बढ़ जाने के कारण बीमा की राशि बढ़ गई है। भारत का सबसे अमीर, गणेश पंडाल के रूप में इसकी पहचान है। यहां के गणेश जी के पास सबसे ज्यादा कीमती आभूषण हैं लाखों लोगों की भीड़ गणेश जी के दर्शन के लिए उमड़ती है।

दिल्ली के पांच स्कूलों को मिली बम की धमकियां

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। गुरुवार को प्रसाद नगर और द्वारका सेक्टर-5 सहित पांच स्कूलों को ईमेल के माध्यम से बम धमकी मिली, जिससे अभिभावकों और छात्रों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और स्कूल परिसरों में सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया। यह इस सप्ताह का तीसरा मामला है जब दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकियाँ मिली हैं। इससे पहले बुधवार को करीब 50 से अधिक स्कूलों को इसी तरह के धमकी भरे ईमेल मिले थे। इन स्कूलों में मालवीय नगर स्थित एसकेवी हौज रानी और करोल बाग का आंध्र स्कूल भी शामिल था। वहीं सोमवार को सुबह 7:30 से दोपहर 12:25 तक 32 स्कूलों को धमकी मिली थी, जिनमें से अधिकांश द्वारका इलाके में स्थित थे। प्रभावित स्कूलों में दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस), द्वारका, बीजीएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, श्री वेंकटेश्वर स्कूल और ग्लोबल स्कूल प्रमुख हैं।

कुछ ना कहना

संसद का मानसून सत्र : लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित...

लोकसभा ने 12 और राज्यसभा ने 15 विधेयक पास किए

120 घंटे में से लोकसभा 37 घंटे और राज्यसभा 41 घंटे ही चली

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र का गुरुवार को आखिरी दिन था। सत्र की शुरुआत 21 जुलाई से हुई थी। दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को छोड़कर इस सत्र में बहुत कम कामकाज हुआ है। एक महीने लंबे सत्र के दौरान लोकसभा ने 12 और राज्यसभा ने 15 विधेयक पास किए, लेकिन बार-बार व्यवधान, स्थगन और बायकॉट जारी रहा। आखिरी दिन की कार्यवाही के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि सदन में 120 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया गया था सिर्फ 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। इसके साथ लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।वहीं राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सत्र के अंत में अपनी टिप्पणी में कहा कि हंगामे के कारण सदन में केवल 41 घंटे 15 मिनट कामकाज हो पाया और सदन का कामकाज केवल 38.88 प्रतिशत रहा जो बहुत निराशाजनक है।

संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजनीतिक दलों से अपने बर्ताव पर नियंत्रण रखने का आह्वान किया। बिरला ने कहा कि संसद के अंदर और बाहर सांसदों की भाषा गरिमामय होनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर ने सांसदों को लताड़ लगाते हुए कहा कि सदन में विपक्ष का आचरण लोकतंत्र के मूल्यों के अनुरूप नहीं रहा। ये संसद की गरिमा के अनुसार नहीं है। देश की जनता देख रही है कि किस तरह से अहम मुद्दों पर चर्चा को बाधित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस सत्र में 419 सवाल किए गए, जिसमें से सिर्फ 55 के मौखिक उत्तर दिए जा सके। पूरे सत्र के दौरान चर्चा का समय 120 घंटे निर्धारित किया गया था, लेकिन 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। लोकसभा में 12 विधेयक पारित हुए।

रोज कार्यवाही बाधित करता रहा विपक्ष

यह सत्र 21 जुलाई को शुरू हुआ था, जिसमें पूरा विपक्ष बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा की मांग को लेकर रोज कार्यवाही बाधित करता रहा। अपने समापन भाषण के बाद बिरला ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। उधर, राज्यसभा में अमित शाह ने 3 बिल जेपीसी में भेजे जाने के लिए रखे। अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग बिल चर्चा के लिए रखा। हालांकि विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा। बाद में इसे राज्यसभा से भी पास कर दिया गया। इसके बाद राज्यसभा भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सांसद बिहार एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग करते रहे। उनके विरोध और हंगामे के कारण दोनों सदनों में आखिरी दिन भी कार्यवाही नहीं हो सकी।

संसद के मॉनसून सत्र में नहीं हुआ मनमाफिक काम

संसद का मॉनसून सत्र निराशाजनक रहा। लगातार 20 दिनों तक इंडिया ब्लॉक से जुड़े विपक्षी दलों ने बिहार मतदाता सूची के मुद्दे पर लोक सभा और राज्य सभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। इसकी वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही काफी बाधित हुई। राज्य सभा के डिप्टी चेयरमैन हरवंश ने मॉनसून सत्र के आखिरी दिन अपने समापन भाषण में कहा, कुल मिलाकर, सदन केवल 41 घंटे 15 मिनट ही चल पाया। इस सत्र की प्रोडक्टिविटी निराशाजनक रूप से सिर्फ 38.88 प्रतिशत रही, जो गंभीर आत्मचिंतन का विषय है। उपसभापति हरिवंश ने कहा, कोशिशों के बावजूद ये सत्र व्यवधानों के की वजह से प्रभावित हुआ, इससे बार-बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इससे न केवल संसद का बहुमूल्य समय बर्बाद हुआ, बल्कि सार्वजनिक महत्व के कई मामलों पर चर्चा और विचार-विमर्श संभव नहीं हो सका। इस सत्र के दौरान सांसदों के पास राज्य सभा में प्रश्नकाल के दौरान 285 सवाल, जीरो ऑवर सबमिशन और 285 स्पेशल मेंशन के जरिये अपनी बात कहने का मौका था। लेकिन, सदन में हंगामे की वजह से प्रश्नकाल के दौरान सिर्फ 14 सवाल पूछना संभव हो पाया और सिर्फ 7 जीरो ऑवर सबमिशन और 61 स्पेशल मेंशन टेकअप किए जा सके। इस सत्र के दौरान राज्य सभा में बिना विस्तृत चर्चा के 15 बिल पारित हुए या उन्हें वापस किया गया। लोक सभा में सदन की प्रोडक्टिविटी और नीचे रही। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने सत्र के समापन पर कहा, ये हमारे लिए चिंतनीय विषय रहा कि इस सत्र की कार्यसूची में 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे, पर लगातार व्यवधान के कारण केवल 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर हेतु लिए जा सके।

लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

लोकसभा स्पीकर ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान सिर्फ 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। जिसमें लोकसभा में 12 विधेयक पारित हुए और 55 सवालों के ही मौखिक जवाब दिए गए। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद रहे।

लोकसभा स्पीकर ने सांसदों को लगाई लताड़

विपक्षी सांसदों के हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को लताड़ लगाई और कहा कि सदन में विपक्ष का आचरण लोकतंत्र के मूल्यों के अनुरूप नहीं रहा। ये संसद की गरिमा के अनुसार नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की जनता देख रही है कि किस तरह से अहम मुद्दों पर चर्चा को बाधित किया जा रहा है।

हमले के बाद दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को जेड सिक्योरिटी

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को केंद्र सरकार ने जेड कैटेगरी की वीआईपी सुरक्षा प्रदान की है। सीएम सिक्योरिटी में 22 से 25 हथियारबंद जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। गुप्ता और उनके आधिकारिक आवास की सुरक्षा अर्धसैनिक बल का वीआईपी सिक्योरिटी ग्रुप करेगा। यह ग्रुप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सोनिया-राहुल और प्रियंका गांधी की सुरक्षा में भी तैनात है। दरअसल, सीएम रेखा पर 20 अगस्त की सुबह करीब 8.15 बजे जनसुनवाई के दौरान एक शख्स ने हमला कर दिया। आरोपी गुजरात के राजकोट का रहने वाला राजेशभाई खीमजी है, जिसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी को बुधवार रात दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका में एक मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया गया। इसके बाद उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। राजेश पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है। गुजरात में भी राजेश पर चाकूबाजी समेत 5 केस पहले से दर्ज हैं। हालांकि, गिरफ्तारी के दौरान उसके पास कोई हथियार नहीं मिला। इंटेलिजेंस ब्यूरो और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल उससे पूछताछ कर रही है। जनसुनवाई में शिकायतकर्ता बनकर पहुंचे राजेश ने सीएम को कागज देते समय उसने हमला किया। हमले में चोटिल सीएम रेखा के हाथ, कंधे और सिर पर चोटें आई हैं। फिलहाल वे घर से काम कर रही हैं।

न्यायिक सक्रियता, न्यायिक आतंकवाद नहीं बननी चाहिए

नई दिल्ली। राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयक को मंजूरी देने की समय सीमा तय करने के मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायिक सक्रियता, न्यायिक आतंकवाद नहीं बनना चाहिए। गुरुवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि निर्वाचित लोगों को काफी अनुभव होता है और उसे कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। इस पर सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि हमने कभी भी निर्वाचित लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा है। मैंने हमेशा कहा है कि न्यायिक सक्रियता, कभी भी न्यायिक आतंकवाद या न्यायिक रोमांच नहीं बनना चाहिए। पीठ में सीजेआई जस्टिस गवई के अलावा जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर भी शामिल हैं। तुषार मेहता ने अपने सबमिशन में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया, जिसमें राज्यपालों की शक्तियों पर बात की गई। इस मामले पर सुनवाई लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। मेहता ने कहा कि निर्वाचित लोग सीधे तौर पर जनता का सामना करते हैं। अब लोग जनप्रतिनिधियों से सवाल करते हैं। 20-25 साल पहले हालात अलग थे। अब मतदाता जागरूक हैं और उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता।

मेहता ने कहा- राज्यपाल के पास विधेयक को मंजूरी न देने की शक्ति

मेहता ने कहा कि राज्यपाल के पास मंजूरी रोकने का पूरा अधिकार है, जो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 200 से मिला हुआ है। बुधवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर कोई विधेयक दूसरी बार राज्यपाल की मंजूरी के लिए, उनके पास भेजा जाए तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए नहीं भेज सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में एक आदेश दिया था, जिसमें राज्यपालों और राष्ट्रपति को एक तय समय में उनके समक्ष पेश विधेयकों पर फैसला लेने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर काफी हंगामा हुआ। राष्ट्रपति ने भी इस पर आपत्ति जताई और कहा कि देश के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर यह फैसला दे सकता है।

रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ-गंगोत्री हाईवे बंद

नई दिल्ली। देश के पश्चिमी हिस्से महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश के कारण जन-जीवन प्रभावित हुआ है। दोनों राज्यों में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में यमुना के कारण कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। यमुना का पानी ताजमहल तक पहुंच गया है। 40 गांव अलर्ट पर हैं। मथुरा में यमुना नदी कटान के बाद अपना मूल रास्ता छोड़कर 2 किमी दूर बह रही हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के कारण बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। गंगोत्री हाईवे धरासू पुराना थाना और सोनागढ़ के पास ब्लॉक है। यमुनात्री हाईवे भी नारदचट्टी के पास बंद है। कुथनौर में ट्रैफिक शुरू हो गया है। बाकी जगहों पर मलबा हटाने का काम जारी है।

इधर, गुजरात के तटीय जिलों में बुधवार को भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। जूनागढ़ जिले में 12 घंटों में 331एमएम बारिश हुई। एनडीआरएफ ने पोरबंदर जिले के एक स्कूल में फंसे 46 बच्चों और 4 टीचर्स को बचाया। वहीं, महाराष्ट्र में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बुधवार को राज्य के कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने दाखिल किया नामांकन

सोनिया गांधी, खड़गे समेत 80 विपक्षी नेता बने प्रस्तावक

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्षी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और गोवा के पहले लोकायुक्त बी. सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार को औपचारिक रूप से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। उनके नामांकन पत्र पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, डीएमके सांसद तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव समेत करीब 80 सांसदों ने प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर किए।

पूर्व जस्टिस रेड्डी के नामांकन की घोषणा करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविदों में से एक हैं। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष का यह फैसला लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की रक्षा के लिए है।

गौरतलब है कि स्वास्थ्य कारणों से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का पद खाली है। इसके बाद सत्ताधारी एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा और एनडीए घटक दलों ने समर्थन के लिए विपक्षी पार्टियों से भी संपर्क साधा, लेकिन सफलता नहीं मिली।

नामांकन दाखिल करने से पहले बी. सुदर्शन रेड्डी ने अपनी उम्मीदवारी को लेकर कहा, कि सुप्रीम कोर्ट के एक साथी न्यायाधीश ने मुझसे पूछा कि मैं राजनीतिक दलदल में क्यों उतर रहा हूं। मैंने जवाब दिया कि मेरा सफर 1971 में एक वकील के रूप में शुरू हुआ था और मौजूदा चुनौती भी उसी सफर का हिस्सा है।

भारत सरकार ने अफवाहों पर लगाया विराम...बाइक और स्कूटर से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा

नई दिल्ली। भारत सरकार ने इसकी पुष्टि की है कि राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर चलने वाले दोपहिया वाहनों (बाइक और स्कूटर) से कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर चल रही उन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) जल्द ही दोपहिया वाहनों से भी टोल वसूलेगा।

मंत्रालय ने कहा कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर यूजर फीस राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 के अनुसार वसूला जाता है और दोपहिया वाहनों से टोल शुल्क वसूलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नियमों के अनुसार, टोल प्लाजा पर यूजर फीस चार या अधिक पहिया वाहनों से लिया जाता है, जिनमें कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन/हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस/बस या ट्रक/भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग इक्विपमेंट (ईएमई) या मल्टी एक्सल वाहन (एमएवी) (तीन से छह एक्सल)/बड़े आकार के वाहन (सात या अधिक एक्सल) जैसी श्रेणियां शामिल हैं।

एक अलग रिपोर्ट के अनुसार, एनएचएआई ने 15 अगस्त के बाद से सिर्फ चार दिनों में 5 लाख से ज्यादा फॉस्टैग-आधारित वार्षिक टोल परमिट की ब्रिकी हैं। इससे 150 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण, बढ़ी परमाणु निवारक क्षमता

नई दिल्ली। भारत ने अपनी परमाणु-सक्षम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के तट पर स्थित चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर) से बुधवार को किया गया। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक यह परीक्षण सामरिक बल कमान के तहत किया गया और इस दौरान मिसाइल ने सभी ऑपरेशनल और तकनीकी मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया।

इस परीक्षण से भारत की सामरिक और परमाणु निवारक क्षमता को और बल मिला है।

अग्नि-5 मिसाइल की खास बात यह है कि यह लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगा सकती है और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि-5 भारत की अब तक की सबसे एडवांस और ताकतवर मिसाइलों में से एक है। इसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने तैयार किया है। यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। अग्नि-5 मिसाइल भारत की अग्नि श्रृंखला की सबसे आधुनिक मिसाइल मानी जाती है। इस सीरीज में पहले भी अग्नि-1, अग्नि-2, अग्नि-3 और अग्नि-4 जैसे सफल संस्करण शामिल हैं, लेकिन अग्नि-5 की रेंज और तकनीक सबसे ज्यादा उन्नत है।

तकिए पर सिर रखने से पहले खुद से पूछें आज जनता का कितना पैसा खर्च हुआ

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने जजों की कार्य प्रतिबद्धता पर जताई नाराजगी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में हाईकोर्ट के कुछ जजों की कार्य प्रतिबद्धता पर कड़ी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि जहां कई जज न्याय के मशालची बनकर भारी बोझ उठाते हैं, वहीं कुछ की कार्यशैली निराशाजनक है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिनकी निष्ठा कमजोर पड़ जाती है, उनसे मेरी अपील है। हर रात तकिए पर सिर रखने से पहले खुद से पूछें कि आज मुझ पर जनता का कितना पैसा खर्च हुआ? क्या मैंने समाज के विश्वास का प्रतिदान दिया?

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि हाल के वर्षों में एक विरोधाभासी स्थिति बन गई है, जहां न्याय तक पहुंच केवल संपन्न वर्ग तक सीमित होती जा रही है। उन्होंने कहा कि जब कानूनी फीस मासिक आय से भी ज्यादा हो जाती है, जब प्रक्रियाएं उस साक्षरता की मांग करती हैं जो करोड़ों लोगों के पास नहीं है और जब न्यायालय की गलियारों में लोग स्वागत से ज्यादा भय महसूस करते हैं तो यह वास्तविकता है कि हमने न्याय के मंदिर तो बनाए पर उनके दरवाजे उन्हीं के लिए संकरे कर दिए जिनके लिए वह बने थे।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने निःशुल्क कानूनी सहायता की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि यह कोई कानूनी दान नहीं बल्कि संवैधानिक ऑक्सीजन है, जो लोकतंत्र की जीवनरेखा है। उन्होंने उदाहरण देते कहा कि कैसे कानूनी सहायता के जरिए एक बुजुर्ग व्यक्ति ने धोखाधड़ी से गंवाई अपनी जीवन भर की पूंजी वापस पाई। उन्होंने बताया कि नालसा की 'वीर परिवार सहायता योजना' जैसे प्रयास सैनिकों और उनके परिवारों को दूरस्थ क्षेत्रों में भी कानूनी सहारा दिलाने में अहम साबित हो रहे हैं।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में करीब 4,600 कैदियों को कानूनी प्रतिनिधित्व देने के लिए आगे आए वकीलों, विशेषकर युवाओं की तारीफ की। उन्होंने वरिष्ठ वकीलों से हर माह कम से कम दो प्रो बोनो मामले लेने का भी आह्वान किया।

जस्टिस सूर्यकांत ने लंबित मामलों और न्याय में हो रही देरी को बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि कई बार न्याय में देरी ही न्याय से इनकार बन जाती है। हमें तय करना होगा कि न्याय तक पहुंच केवल कागजों पर गारंटी न रहे। उन्होंने मध्यस्थता के महत्व पर भी बल दिया और कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत रिश्तों को तोड़ने के बजाय बचाए रखती है।

लचर सिस्टम- आदिवासी प्रसूता की मौत पर जिम्मेदारी तय नहीं

सरकार के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की नाकामी से हुई मौत को सामान्य समझना मनमानी, एक लम्बे अर्से से अव्यवस्था से जूझ रहा है बम्हनी का अस्पताल

कटंगी(पद्मेश न्यूज)। केन्द्र की प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, मातृवंदना योजना, आयुष्मान भारत, राज्य की जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से राज्य में गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव एवं शिशु मृत्यु दर को रोकने का दंभ भरने वाली सरकार के कुंभकरणीय नींद में सोए जनप्रतिनिधि एवं स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही ने सूबे के पठार अंचल में आदिवासी प्रसूता एवं उसके नवजात शिशु की मौत मुकम्मल कर दी। तिरोड़ी तहसील अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर बम्हनी से 17 अगस्त रविवार की रात्रि सामने आए घटनाक्रम ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत चाकाहेटी के अर्जुनटोला निवासी चमनलाल कुमरे अपनी गर्भवती पत्नि सरिता को प्रसव पीड़ा होने पर रविवार की रात्रि करीबन 9 बजे गांव की आशा कार्यकर्ता के साथ बम्हनी अस्पताल पहुँचे थे। चमनलाल के अनुसार मौके पर ड्यूटी पर तैनात महिला स्वास्थ्यकर्मी ने उन्हें एक घंटे के भीतर नार्मल डिलीवरी का आश्वासन दिया था। इस तरह का भरोसा देते हुए करीब ढाई घंटे बीत गए। महिला को अत्यधिक रक्तस्त्राव होने पर स्वास्थ्य कर्मचारी ने उन्हें रेफर कर दिया। महिला के परिजनों ने तुरंत एंबुलेस को कॉल किया तो एंबुलेंस सेवा प्रदाता की ओर से वाहन उपलब्ध कराने में दो घंटे का समय लगने की बात कही गई। ऐसे में चमनलाल अपनी पत्नि को निजी वाहन से लेकर तुमसर के लिए निकल पड़े लेकिन रास्ते में उनकी पत्नि और गर्भस्थ शिशु ने दम तोड़ दिया। अस्पताल स्टॉफ ने अत्यधिक रक्तस्त्राव होने का हवाला देते हुए घटना से पलड़ा झाड़ लिया है। वहीं भोलेभाले आदिवासी परिवार ने घटना को लेकर बिना किसी विरोध के मृतका एवं उसके मृत शिशु का सोमवार को अंतिम संस्कार भी कर दिया है। लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर बम्हनी आरोग्य मंदिर के लिए नियुक्त होने के बावजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कटंगी में संलग्न चिकित्सक डॉ. भूपेन्द्र गजभिए के मूल पदस्थिति पर तैनात न होने लेकर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी कठघरे में है। प्रसूता की मौत के बात जब सवाल उठा तो खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ.पंकज दुबे ने सफाई दी कि उन्होंने डॉ.गजभिए को कटंगी में अटैच नहीं किया है। तो क्या डॉ.गजभिए बिना किसी आदेश के सरकारी अस्पताल कटंगी में सेवाएं दे रहे हैं? इसका जवाब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को देना चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि डॉ.गजभिए अस्पताल में ड्यूटी पर रहते तो शायद जच्चा-बच्चा दोनों को बचाया जा सकता था। आयुष्मान आरोग्य केन्द्र बम्हनी में इस तरह की घटना की आशंका एक लम्बे अर्से से व्यक्त की जा रही थी। कुछ ही दिन पूर्व निरंतर अखबारों में बम्हनी अस्पताल में चिकित्सक की कमी की खबरें प्रकाशित कर शासन के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों का ध्यान इंगित कराया गया था। लेकिन कुंभकरणीय नींद में सोए नेताओं और सिस्टम की लापरवाही ने एक

गरीब आदिवासी की खुशहाली को मातम में तब्दील कर दिया। विडम्बना यह है कि घटना के तीन दिन बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में किसी तरह की जांच या जिम्मेदार तय नहीं की है। न ही विभाग की ओर से डॉ.गजभिए को मूल पदस्थिति पर वापस करने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। घटना से विभाग पर तो सवाल उठ ही रहे हैं साथ ही क्षेत्र के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि खासकर विधायक की निष्क्रियता भी चर्चा में है। बम्हनी अस्पताल का मुद्दा विधायक गौरव सिंह पारधी के संज्ञान में भी था लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का श्रेय लेने में हमेशा आगे रहे विधायक पारधी ने पठार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया। शायद सत्तारूढ़ पार्टी के जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायक इस मामले में हस्तक्षेप करते तो आज यह नौबत नहीं आती।

पांच वर्ष बाद गूंजती किलकारी

आदिवासी युवक चमनलाल का पांच वर्ष पूर्व सरिता से विवाह हुआ था। विवाह के पांच साल बाद उसकी पत्नि एक बच्चे की मां बनती। सूबे की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण खुशहाली की बांट जोहते परिवार में गम का पहाड़ टूट गया। पिता बनने का इंतजार कर रहे पीड़ित ने अपनी पत्नि के साथ बच्चे को भी खो दिया।

दर्जनभर से अधिक ग्राम प्रभावित, शिकायतों पर हावी उदासीनता

बम्हनी अस्पताल में चिकित्सक नहीं होने से चाकाहेटी, अर्जुनटोला, सतीटोला, जामुनटोला, नीमटोला, सादाबोड़ी, रामजी टोला, आंजनबिहरी, दिग्धा, कोड़बी, हरदोली, पुलपुट्टा, छतेरा, टुईयापार, महकेपार और गोरेघाट की प्रसुति महिलाओं को प्रसव के लिए कटंगी, बालाघाट जाना पड़ता है। इस समस्या को लेकर एक लम्बे समय से ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से कई शिकायतें कर डाली। स्थानीय पटेल जितेन्द्र सिंह रावत ने बताया कि उन्होंने कई बार इस संबंध में सीएम हेल्पलाईन में भी शिकायत की लेकिन अधिकारी अपने स्तर पर निराकरण दर्ज कर शिकायतें बंद करते रहे।

जिपं.सभापति ने सीएमएचओ के समक्ष रखा था मुद्दा

सनद रहे कि जिला पंचायत की महिला एवं बाल विकास विभाग सभापति केसर बिसेन ने करीबन एक माह पूर्व जिला मुख्यालय में आयोजित सामान्य सभा की बैठक में सीएमएचओ डॉ.उपलव के समक्ष बम्हनी अस्पताल में चिकित्सक की नियुक्ति का मुद्दा उठाया था। सभापति ने कहा था कि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर डॉ.भूपेन्द्र गजभिए को सप्ताह में कम से कम दो दिन बम्हनी अस्पताल में पदस्थ किया जाए। अधिकारियों ने जिपं.सभापति की मांग पर सहमति तो जताई लेकिन कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए।

कब जागेंगे माननीय?

बम्हनी अस्पताल में चिकित्सक की कमी का मुद्दा शुरू से ही संवेदनशील बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में भी कई बार अस्पताल में चिकित्सक न होने के कारण गर्भवती महिलाओं सहित अन्य मरीजों को निजी अस्पताल में जाकर अपनी जान बचानी पड़ी है। ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी के क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारधी का इस मामले में निष्क्रिय रहना वाकई में चिंताजनक है। स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधियों ने कई बार बम्हनी में चिकित्सक नियुक्त किए जाने की मांग रखी परंतु एक क्षेत्र के एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायक ने कभी इस मामले में रूचि नहीं दिखाई। आखिर कब विधायक इस मामले को लेकर शासन एवं प्रशासन से बात करेंगे? यह सवाल भविष्य के गर्त में है।

5 साल बाद भी अधूरा है कर्मचारियों के कैशलेस इलाज का सपना

वर्ष 2019 में कमलनाथ सरकार कैबिनेट ने दी थी मंजूरी

भोपाल। प्रदेश में 5 साल बाद भी करीब 12 लाख कर्मचारियों के लिये कैशलेस इलाज का सपना अधूरा है। जबकि इसका अनुमोदन वर्ष 2019 में कमलनाथ सरकार कैबिनेट कर चुकी है। तब यह योजना एक अप्रैल से लागू करने का प्रस्ताव था। बावजूद इसके अमल में नहीं आने से कर्मचारियों में भी निराशा आई है।

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के सचिव उमाशंकर तिवारी ने इस मामले में नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि तीन मुख्यमंत्रियों की घोषणा के बाद भी प्रदेश के कर्मचारियों को अब तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ नहीं मिल सका है। जबकि अधिकारी और कर्मचारी अन्य राज्यों में लागू आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा की तरह 5 लाख से 10 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा मिलने की उम्मीद कर रहे थे। इसके बाद भी अब तक किसी प्रकार का आदेश सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है। जिसके कारण कर्मचारी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी इस सुविधा से वंचित हैं।

योजना से बढ़ेगा सरकार पर वित्तीय भार

योजना के लागू होने से सरकार पर लगभग 756.56 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। योजना के तहत साधारण बीमारियों के लिए 5 लाख रुपए और गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जानी थी।

इन कर्मचारियों को लाभ

तब इस स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में शासकीय कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, शिक्षक संवर्ग और नगर सैनिक के अलावा राज्य की स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी शामिल थे। इसके अलावा यह योजना निगम मंडलों में काम करने वाले कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारियों के लिए विकल्प के तौर पर रखा गया है।

तीन सीएम पर फाइल पर नहीं अमल

तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा 2019 में घोषित इस योजना को लेकर बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉ मोहन यादव भी कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं। ठोस कदम नहीं उठाये जाने से कर्मचारियों को सिर्फ आश्वासन मिला है। जबकि शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदेश के कर्मचारियों को आयुष्मान जैसी योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा का लाभ देने की बात की थी। इसके चलते भी मामले में देरी आई है।

विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ का सम्मेलन इंदौर में सम्पन्न

बालाघाट (पद्मेश न्यूज)। म.प्र. विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ भोपाल का क्षेत्रीय सम्मेलन दिनांक 18 अगस्त 2025 को इंदौर में सम्पन्न हुआ। यह इंदौर क्षेत्रीय शाखा का शुभारंभ भी था, जिसका उद्देश्य पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन से संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु एक संगठन गठित करना है। उल्लेखित संगठन की बालाघाट इकाई की ओर से उक्त सम्मेलन में डीपी सेलोकर, अनूप कुमार भोयर तथा एमएल चावके उपस्थित हुए।

गांधी मेडिकल कॉलेज के मामले में हाई कोर्ट का आदेश

पदोन्नति वाले पद पर सीधी भर्ती नहीं हो सकती

भोपाल। मप्र हाई कोर्ट से भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज को झटका लगा है। जीएमसी द्वारा डॉक्टरों की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को हाई कोर्ट ने अवैध बताते हुए निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने दायर याचिका की सुनवाई करते हुए पाया कि स्वायत्तशासी कॉलेज की कार्यकारिणी ने सीधी भर्ती के पदों का विज्ञापन देने से पहले आंतरिक उम्मीदवारों की पदोन्नति की प्रक्रिया पर निर्णय नहीं लिया था। एकलपीठ ने कॉलेज प्रबंधन को नियुक्ति प्रक्रिया नये सिरे से प्रारंभ करने के आदेश जारी किये हैं। भोपाल निवासी डॉ. रजनी ठाकुर की तरफ से दायर याचिका में कहा गया एनेस्थीसिया विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर का पद पदोन्नति द्वारा भरा जाना चाहिए था। वह कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग में 12 वर्षों से अधिक समय से सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थीं। इसलिए उन्हें इस पद पर पदोन्नति मिलनी चाहिए थी। कॉलेज प्रबंधन द्वारा पदोन्नति प्रदान करने की बजाय सीधी भर्ती से इस पद पर नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

अस्पताल प्रबंधन ने ये जवाब दिया

याचिका में कहा गया कि नियम अनुसार फीडर लाइन से पदोन्नति द्वारा भरा जाने वाला पद सीधी भर्ती से नहीं भरा जा सकता है। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से तर्क दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन के कारण पदोन्नति नहीं दी जा सकती है। राज्य सरकार ने सीधी भर्ती के माध्यम से पदोन्नति के पदों को भरने की अनुमति प्रदान की है। याचिकाकर्ता के तरफ से तर्क दिया गया कि सीधी भर्ती के माध्यम से उससे जूनियर को एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

हाई कोर्ट ने नियुक्ति का विज्ञापन निरस्त किया

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि पदोन्नति द्वारा पद भरने में कानूनी बाधा है, इसलिए उन्होंने सीधी भर्ती को आगे बढ़ाया है और इसे आंतरिक उम्मीदवारों तक सीमित कर दिया है। स्वायत्तशासी कॉलेज की कार्यकारिणी ने सीधी भर्ती के पदों का विज्ञापन देने से पहले आंतरिक उम्मीदवारों की पदोन्नति की प्रक्रिया पर निर्णय नहीं लिया। एकलपीठ ने नियुक्ति के विज्ञापन को अवैध करार देते हुए निरस्त कर दिया।

नीट में स्टेट काउंसलिंग का कटऑफ 452, पिछले साल 621

भोपाल। नीट यूजी 2025 की स्टेट लेवल काउंसलिंग शुरू हो गई है। संचालनालय शिक्षा विभाग द्वारा 4181 एमबीबीएस सीटों का आवंटन किया गया है। इस साल पिछले वर्ष की तुलना में कट ऑफ काफी घट गया है। पिछले साल सामान्य कटऑफ 621था। जो इस वर्ष घटकर 452 पर आ गया है। मध्य प्रदेश में 29 मेडिकल कॉलेज में 17 सरकारी और 12 निजी क्षेत्र में है। नीट काउंसलिंग में सबसे ज्यादा पसंद छात्रों की भोपाल रही है। भोपाल में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज, और पांच निजी मेडिकल कॉलेज हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर और जीआर मेडिकल कॉलेज ग्वालियर काउंसलिंग में परीक्षार्थियों की सबसे ज्यादा पसंद रही है। मध्य प्रदेश में 4883 सीटों में से इस बार 4181 सीटों का अलॉटमेंट हुआ है। कुछ सीटें आरक्षण और विशेष प्रावधान के कारण रोकी गई हैं। भोपाल के चिरायु एवं पीपल्स मेडिकल कॉलेज तथा इंदौर के श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज की सभी सीटें पहली ही काउंसलिंग में भर गई हैं। निजी मेडिकल कॉलेज की दौड़ में सबसे पसंदीदा यही तीन मेडिकल कॉलेज हैं।

आरिफ मसूद मामले में डीजीपी ने गठित की एसआईटी

भोपाल। डीजीपी कैलाश मकवाणा ने विधायक आरिफ मसूद के फर्जी दस्तावेजों के जरिए कॉलेज की मान्यता के मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद डीजीपी कैलाश मकवाना ने एसआईटी का गठन संजीव शमी एडीजी (टेलीकॉम) के नेतृत्व मे किया है। तीन सदस्यीय एसआईटी में डी. कल्याण चक्रवर्ती, डीआईजी छिंदवाड़ा रेंज और निमिशा पांडे एआईजी (प्रशिक्षण) पीएचक्यू भोपाल को शामिल किया गया है। एडीजी संजीव शमी के नेतृत्व मे बनाई गई यह एसआईटी जाली दस्तावेजों के आधार पर विधायक आरिफ मसूद के इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता के मामले की जांच की निगरानी करेगी। एसआईटी गठित करने के बाद अब पूरे मामले की जल्द से जल्द जांच शुरू की जायेगी।

विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज मामले की जांच शुरू

भोपाल। भोपाल की मध्य विधानसभा से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज की मान्यता के मामले में डीजीपी कैलाश मकवाना ने तीन सदस्यीय जांच दल गठित किया है। यह जांच दल फर्जी दस्तावेजों के जरिए कॉलेज की मान्यता के मामले में जांच करेगा। हाई कोर्ट की डबल बेंच के निर्देश के बाद डीजपी कैलाश मकवाना ने एसआईटी का गठन संजीव शमी एडीजी (टेलीकॉम) के नेतृत्व मे किया गया है जिसमें डी. कल्याण चक्रवर्ती डीआईजी छिंदवाड़ा रेंज और निमिशा पांडे एआईजी (प्रशिक्षण) पीएचक्यू भोपाल को शामिल किया गया है। एडीजी संजीव शमी के नेतृत्व मे बनाई गई एसआईटी जाली दस्तावेजों के माध्यम से विधायक आरिफ मसूद के इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता के मामले की जांच करेगी। गौरतलब है कि कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद पर जो मामला दर्ज किया गया है वो कॉालेज को मान्यता दिलाने से जुड़ा है। इसमे ये कहा गया है कि उन्होंने अपने कॉलेज को मान्यता दिलवाने में फर्जी कागजात दिलवाए थे। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिसके बाद भोपाल की एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित का कहना है कि, कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके मुताबिक ही ये कार्रवाई की गई है, विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

17 लाख की ऑडी सहित चोरी करने वाला आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार

भोपाल। राजधानी भोपाल की एमपी नगर पुलिस ने 17 लाख की लग्जरी ऑडी कार चोरी करने वाले आरोपी को मायापुरी दिल्ली से गिरफ्तार करते हुए कार को भी बरामद कर लिया है। शातिर आरोपी दिल्ली में कार के पार्टस खोलकर बैचने की फिराक मे था। टीआई एमपी नगर जयहिन्द शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया की फरियादी रविकांत त्रिपाठी ने शिकायत की थी, की उनकी ऑडी कार जिला अदालत के पास से चोरी हो गई है। जॉच के बाद पुलिस ने 28 जुलाई 2025 को अज्ञात के खिलाफ मामला कायम किया था। आरोपी की तलाश में पुलिस टीम ने हाथ लगे सुरागो के आधार पर घटना स्थल से दिल्ली तक आने-जाने वाले रास्तो पर लगे हजारो सीसीटीवी कैमरे खंगाले। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार टीम ने चोरी गई कार सहित आरोपी वाहन चोर को मायापुरी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रोशन अहिरवार पिता हरि अहिरवार (25) मायापुरी साउथ वेस्ट दिल्ली के रुप में हुई है। आरोपी ने बताया की वह कार को खोलकर उसके पार्टस अलग-अलग कर बेचने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया।

मधुमक्खी के हमले में महिला घायल

बालाघाट(पद्मेश न्यूज)। हट्टा थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम पाथरी में मधुमक्खी के हमले में एक महिला घायल हो गई। घायल महिला श्रीमती उर्मिला पति छगनलाल पिछोड़े 55 वर्ष का इलाज जिला अस्पताल बालाघाट में किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उर्मिला पिछोड़े घरेलू काम के अलावा अपने परिवार के साथ खेती किसानी करती है। 20 अगस्त को उर्मिला पिछोड़े अपने खेत कृषि कार्य करने गई थी।शाम 5:00 बजे कृषि कार्य के दौरान मधुमक्खी के झुंड ने उर्मिला पिछोड़े पर हमला कर दिया और उसके चेहरे को काट दिया ।जैसे तैसे उर्मिला पिछोड़े अपने घर आई और अपने बेटे को बताई ।उर्मिला पिछोड़े को उसके बेटे अर्जुन पिछोड़े ने मोटरसाइकिल से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया।

मजदूर को सांप ने काटा

बालाघाट(पद्मेश न्यूज)। बैहर थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम कोसमी में एक मजदूर को सांप में काट दिया। सांप के काटने से अस्वस्थ मजदूर सरवन पिता गब्बर सिंह उइके 27 वर्ष ग्राम भारदा थाना बैहर निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरवन उइके मजदूरी करता है। 20 अगस्त को 12:00 बजे ग्राम कोसमी में सरवन उइके सरपंच के घर के सामने विद्युत पोल गड़ा रहे थे ।विद्युत पोल के गड्ढे के पास पहले से मिट्टी गिरी पड़ी थी। मिट्टी को हटाते समय अचानक सांप ने सरवन उइके के दाहिने हाथ के अंगूठे में काट दिया। इस संबंध में सरवन उइके ने लाइनमैन को बताया। जिसके बाद लाइनमैन संतराम कावरे ने सरवन उइके को मोटरसाइकिल से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया।

आम सूचना

मैं मुकेश अग्रवाल अधिवक्ता सिविल कोर्ट वारासिवनी अपने पक्षकार श्री यशवंत राव घोरमारे पिता श्री सीताराम घोरमारे जाति माना निवासी वार्ड नं.१४ ग्राम किरनापुर तह:किरनापुर जिला बालाघाट की ओर से अधिकृत होकर आम जनता को सूचित करता हूँ कि मेरे पक्षकार के एकमेव स्वामित्व व आधिपत्य की मौजा ग्राम गर्रा प.ह.न. ४५/७७, रा.नि.मं. कनकी तह: लालबर्रा जिला बालाघाट में स्थित खसरा नं. ५१६/२/१/१/३ रकबा ०.००८ हे.परिवर्तित भूमि स्थित है। इस भूमि को मेरे पक्षकार ने विक्रेता श्री छगन हनवत पिता सेवकराम हनवत से दिनांक १८/१२/२०१९ को क्रय किया है और विक्रय पत्र का पंजीयन उपपंजीयन कार्यालय वारासिवनी में हुआ। जिसका ई.पंजीयन क्रमांक एमपी ०१०४२०१९ए १८५१४४३ है। किंतु इस भूमि का विक्रय पत्र दिनांक १८/१२/२०१९ असल कंही गुम हो चुका है जो बहुत कोशिश करने के बाद भी प्राप्त नही हुआ है। यह कि वर्णित भूमि को मेरे पक्षकार के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में बंधक रखे जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है अत: इस भूमि व विक्रय पत्र दिनांक १८/१२/२०१९ के संबंध में किसी भी बैंक, संस्था या व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह ७ दिन के अंदर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा बाद में प्रस्तुत किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नही की जायेगी।

वास्ते आम सूचना प्रेषित है
दिनांक २१-०८-२०२५

प्रेषक
मुकेश अग्रवाल
अधिवक्ता सिविल कोर्ट वारासिवनी

स्थान परिवर्तन

मेसर्स पंकज एफ अग्रवाल एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंट का कार्यालय जो वर्तमान में वार्ड नं 20 अन्नपूर्णा मंदिर के पास बालाघाट में स्थित है। अब अपने नवनिर्मित कार्यालय, आर्थिक आर्केड, दूसरी मंजिल, यूको बैंक के ऊपर, रेलवे स्टेशन रोड, बालाघाट में संचालित होगा

संपर्क नं- 9425138797

बारबेड वायर (कांटेदार तार) एवं चेन लिंक जाली उचित दाम पर उपलब्ध

लघु उद्योग निगम भोपाल से संबद्ध

निर्माता

तिरूपति इंजीनियरिंग वर्क्स

मयूर टॉकिज के सामने हनुमान चौक, बालाघाट

फोन:- 07632-243531

मो:- 8989976858, 9425139998

कई नई ट्रेनों की सौगात के बाद भी यात्रियों को घंटों करना पड़ रहा स्टेशन में ट्रेन आने का इंतजार

बालाघाट(पद्मेश न्यूज)। अभी कुछ दिन पहले ही जनप्रतिनिधियों द्वारा बालाघाट रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली कुछ नई ट्रेनों की सौगात जिले के यात्रियों को दी गई है । किंतु ट्रेन अभी भी सही समय पर नहीं चल पा रही है। जिसके कारण यात्रियों को कई घंटे रेलवे स्टेशन में ट्रेन आने का इंतजार करना पड़ रहा है। कई यात्रियों का रिजर्वेशन भी ट्रेन समय पर नहीं चलने के कारण कैंसिल हो रहा है । जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है । यह पूरी घटना 21 अगस्त की है। जब सुबह से ही बालाघाट से गुजरने वाली लोकल और लंबी दूरी की ट्रेन में कई घंटे तक नहीं आई। जिस कारण यात्रियों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा । कई घंटे तक यात्रियों को रेलवे स्टेशन में ही अपना समय व्यतीत करना पड़ा । यात्रियों का मानना है कि भले ही जितनी ट्रेनें हैं , उनमें और अधिक ट्रेनें ना जोड़ी जाए जो ट्रेन वर्तमान में चल रही है। उन ट्रेनों को समय पर ही संचालन के लिए यहां के जनप्रतिनिधियों को प्रयास करना चाहिए । ताकि रेल का सफर यात्रियों का सुखद सफर हो ।

आपको बता दे कि जिले के रेलयात्रियो के लिए रेल का सफर, मुसीबतों भरा होते जा रहा है, जनप्रतिनिधि, नई ट्रेन चलवाने पर ही वाहवाही लूट रहे है। लेकिन यात्रियों को, रेलयात्रा में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यात्री, ट्रेन की देरी से परेशान है, जिसमें लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को सबसे पहले जो बालाघाट से होकर गुजर रही ट्रेन को समय पर चलाए जाने को लेकर प्रयास किया जाना चाहिए। किंतु आज कोई भी जनप्रतिनिधि ट्रेनों की लेट लतिफी पर ध्यान नहीं दे रहा है । सिर्फ नई ट्रेनों की सौगात पर ही वाहवाही लूट रहे हैं । वह यह बिल्कुल नहीं देख रहे हैं कि कौन सी ट्रेन कितने समय आ रही है और यहां रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को कितनी परेशानी हो रही है। इसका कोई भी जनप्रतिनिधियों को इसे कोई मतलब नहीं है । जबकि रेलवे स्टेशन पर घंटों इंतजार करने वाले यात्रियों का मानना है कि जनप्रतिनिधियों को यहां की लोकल सहित लंबी दूरी की चलने वाली ट्रेनों के समय को लेकर वरिष्ठ स्तर से चर्चा कर उन्हें समय पर चलाने के लिए प्रयास करना चाहिए। 21 अगस्त को भी सुबह से ही गोंदिया की ओर से आने वाली ट्रेन कई घंटे लेट हो गई । जिस कारण लोकल में आवागमन करने वाले सहित लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ लोग तो यहां सुबह से ही ट्रेन आने का इंतजार करते रहे , तो कुछ यात्री ऐसे भी थे जो दोपहर से ही अपने घर जाने के लिए लोकल ट्रेन का आने का इंतजार करते रहे । यात्रियों का कहना था कि विभाग को समय पर ट्रेन का संचालन करना चाहिए, जिससे कि यात्रियों को अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

आज कई घंटे ट्रेन लेट चल रही है - भोलाराम पटले

भोलाराम पटले और उनके साथी यात्री ने बताया कि 2:00 बजे ट्रेन बालाघाट रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है , किंतु आज कई घंटे ट्रेन लेट चल रही है। अभी उन्हें जानकारी लगी है कि 3:00 बजे ट्रेन बालाघाट पहुंचने वाली है । इस अनुसार 5:00 बजे ट्रेन तिरोड़ी पहुंचेगी । इस अनुसार आज ट्रेन कई घंटे लेट चल रही है । जिस कारण बहुत अधिक उन्हें परेशानी हो रही है। वह शासन प्रशासन से मांग करते हैं की ट्रेन अपने यथावत समय पर संचालित होना चाहिए।

कई यात्री रेलवे स्टेशन से वापस चले गए - प्रहलाद पटले

प्रहलाद पटले निवासी नंदगांव ने बताया कि उन्हें कोचेवाही जाना था, किंतु ट्रेन के समय पर नहीं चलने की वजह से उन्हें बहुत अधिक परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि आज सुबह 8:00 बजे ट्रेन को आना था ,जो 11:30 बजे ट्रेन आयी । जिससे वह कई घंटे लेट हो गए। उसके बाद अब घर जाते समय भी ट्रेन बहुत अधिक लेट हो रही है । कई यात्री रेलवे स्टेशन से वापस चले गए । अभी भी वह रेलवे स्टेशन में ट्रेन आने का इंतजार कर रहे हैं । उन्होंने यह भी बताया कि ट्रेन आने को लेकर कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है की ट्रेन कब तक बालाघाट आएगी।

ट्रेन को समय पर चलाना चाहिए - राजा चौकसे

राजा चौकसे बताते हैं कि वह कटंगी से बालाघाट 3:15 मिनट पर पहुंचे हैं । जबकि उन्हें रायपुर जाना था और अभी बालाघाट रेलवे स्टेशन से गोंदिया के लिए कोई ट्रेन नहीं है। जिस कारण उनका रिजर्वेशन भी अब व्यर्थ जाएगा । उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा । जबकि उन्हें कटंगी से बालाघाट आने में सिर्फ 50 मिनट का समय लगता है। उन्होंने बताया कि विभाग को इतनी अधिक ट्रेन ना चलाते हुए , चलाई जाने वाली ट्रेन को समय पर चलाना चाहिए । जिससे कि यात्रियों को रेलवे स्टेशनों में अधिक इंतजार ना करना पड़े । जितनी भी ट्रेने चल रही है उन्हें व्यवस्थित चलाने को लेकर प्रयास करना चाहिए। रेलवे स्टेशन में अभी स्कूली बच्चों सहित ग्रामीण अंचलों से आने वाले यात्री भी बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं।

गोंदिया में कुछ परेशानी हो गयी थी - कृष्ण मोहन चौधरी

इस विषय को लेकर जब हमारे द्वारा रेलवे स्टेशन के प्रबंधक कृष्ण मोहन चौधरी से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि गोंदिया में कुछ परेशानी आने की वजह से आज गोंदिया की ओर से आने वाली लोकल और लंबी दूरी की ट्रेन अपने निर्धारित समय पर नहीं चल पा रही है जिस कारण यात्रियों को परेशानी हुई है ।

नाले में बहने से एक व्यक्ति की हुई मौत

दूसरे दिन एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला शव

बालाघाट(पद्मेश न्यूज)। परसवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम शेरपार के नाले में एक व्यक्ति के पानी में बह जाने से मौत हो गई है। जिसे होमगार्ड

और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू का शव को नाले के पानी से निकाल लिया है। अग्रिम कार्रवाई करते हुए शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। मिली जानकारी अनुसार बताया जा रहा है कि 20 अगस्त को अनिल पिता बासीराम उम्र 26 वर्ष, निवासी खामटोला थाना चांगोटोला जो अपने ससुर के साथ अपने परिजनों के यहां जा रहे थे, तभी शेरपार के नाले में अधिक पानी बह रहा था, अनिल और ससुर दोनों के द्वारा नाला पार किया जा रहा था । तभी अधिक पानी के संपर्क में आने की वजह से अनिल पानी के बहाव के साथ बह गया तो वहीं उनके ससुर अधिक पानी होने की वजह से बाहर की ओर आ गए । यह पूरी घटना 20 अगस्त के सुबह के समय की है। इसके बाद अनिल के परिजनों द्वारा नाले में अनिल को बहुत ढूंढा गया किंतु 20 अगस्त की रात्रि तक कहीं भी अनिल का पता नहीं चला। जिसके बाद 21 अगस्त को इस घटना की सूचना अनिल के परिजनों ने परसवाड़ा थाने में दी और परसवाड़ा पुलिस द्वारा नाले में रेस्क्यू किए जाने के लिए होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम को सूचित किया । जिसमें होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद , लगभग तीन घंटे में अनिल के शव को रेस्क्यू किया और शव परसवाड़ा पुलिस को सौंप दिया गया। परसवाड़ा पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव को परिजनों को सौंप दिया गया । इस रेस्क्यू टीम में होमगार्ड और एसडीआरएफ के हवलदार रामभरोसे वरकड़े, योधराज पटले , हीरालाल टेकाम, घनश्याम सोनकर , कमलेश मरावी , राजेश धुर्वे ,वाहन चालक मुलेंद्र आड़े उपस्थित रहे।

जनजाति कार्य विभाग के बाबू पर रसोईया ने मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप

सहायक आयुक्त ने कहा की जायेंगी जांच

बालाघाट(पद्मेश न्यूज)। बैहर क्षेत्र की रसोईया ने जनजाति कार्य विभाग के बाबू पर अटैचमेंट करवाने के नाम पर बार-बार विभाग बुलाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सहायक आयुक्त राहुल नायक ने इस पूरे मामले को दिखवाने की बात कही है।

आपको बता दे की बालक छात्रावास भंण्डेरी, बैहर में पदस्थ रसोईया मीरा मरकाम ने बताया कि वह कन्या आश्रम सोनगुड्डा में कई वर्षों से रसोईया के पद पर पदस्थ थी। जिनका पिछले वर्ष बालक छात्रावास भंण्डेरी, बैहर में अटैचमेंट कर दिया गया है। जबकि देखा जाए तो बालक छात्रावास में उन्हें देर रात तक कार्य करने में असहज महसूस होता है । वह वहां अकेली ही हैं अन्य महिला वहां कोई नही है। कई बार देर रात तक उन्हें छात्रावास में रहना पड़ता है। साथ ही वह एक विधवाह महिला है । उनका एक छोटा बेटा है। मीरा ने बताया कि वह चाहती हैं कि उन्हें उनके गांव के करीब ही कन्या आश्रम सोनगुड्डा में भेज दिया जाए । इसके लिए उन्होंने पिछले

कुछ महीने पहले ही आवेदन लगा रखा है। जनजाति कार्य विभाग के बाबू द्वारा उन्हें बार-बार बैहर से बालाघाट बुलाया जाता है, और परेशान किया जाता हैं, जिस कारण उन्हें आवागमन में काफी दिक्कतें होती है । मीरा मरकाम ने बाबू अमित कुम्मरे पर आरोप लगाया है कि जनसुनवाई में कलेक्टर द्वारा अटैचमेंट को हटा कर उन्हें मूल स्थान पर भेजने के निर्देश देने के बावजूद भी, उन्हें बार-बार बालाघाट बुलाकर परेशान किया जा रहा है । जबकि वह बैहर से अपने छोटे बेटे को लेकर बालाघाट आती है और उन्हें यहां घंटों जनजाति कार्य विभाग में बिठाकर रखा जाता है। जिस कारण वह मानसिक रूप से प्रताडित हो रही है और बाबू पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इस विषय को लेकर जनजाति कार्य विभाग के बाबू अमित ने बताया कि जो रसोईया द्वारा आरोप लगाए गए हैं। वह निराधार है उन्होंने कभी उन्हें नहीं बुलाया ।

रसोईया के आरोप पर संज्ञान लेंगे - राहुल नायक

इस पूरे विषय को लेकर जब हमारे द्वारा सहायक आयुक्त राहुल नायक से दूरभाष पर, इस विषय को लेकर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि फाइल उनके पास आई है। अभी अटैचमेंट का कार्य बंद है। रसोईया आरोप लगा रही है, उस पर भी वह संज्ञान लेंगे। लेकिन अटैचमेंट के लिए बार-बार बालाघाट आना सही नहीं है। यह विभागिय कार्य है । उन्हें बैहर से बालाघाट आने की आवश्यकता नहीं है । जो भी विभागीय कार्रवाई है ,वह स्वयं करते हैं । बाबू इसमें कोई काम नहीं करता। उनके हस्ताक्षर के बाद ही कोई भी अटैचमेंट या स्थानांतरण का कार्य होता है। बाबू इसमें कुछ नहीं करता है।

सांप काटने के बाद तुरंत मिला इलाज, बची जान

वनकर्मी ने पवन आर्मो को तत्काल पहुंचाया हॉस्पिटल, झाड़-फूंक से दूर रहने की अपील

बालाघाट(पद्मेश न्यूज)। जिले के परियोजना परिक्षेत्र अंतर्गत कक्ष क्रमांक 1818 में निंदाई का कार्य कर रहे एक व्यक्ति को जहरीले सांप ने काट लिया। लेकिन समय पर सही दवाई मिल पाने से उसकी जान बच गई। बैहर हॉस्पिटल में कराया गया इलाज। उन्हें एंटी वेनम दिए गए। अब उनकी स्थिति में सुधार है और वे खतरे से बाहर हैं। आपको बता दे कि 18 अगस्त को परियोजना परिक्षेत्र अंतर्गत कक्ष क्रमांक 1818 में वृक्षारोपण क्षेत्र में पवन आर्मो ग्राम खंडापार अन्य मजदूर के साथ काम कर रहा था, तभी उसे वहां एक सांप ने काट दिया । जिसकी सूचना मजदूरों द्वारा चूरन कुमार मड़ावी परियोजना सहायक को दी गई । जिसके बाद , परियोजना सहायक द्वारा इसकी जानकारी सर्पमित्र सचिन पदमें, वनरक्षक को दी गई जिन्होंने मरीज को तत्काल हॉस्पिटल ले जाने हेतु कहा। परियोजना सहायक चूरन मड़ावी द्वारा तत्काल मरीज को शासकीय स्वास्थ्य केंद्र बैहर लेजाया गया, जहां ट्रीटमेंट के पश्चात व्यक्ति की सकुशल जान बच गई। सचिन पदमें, वनरक्षक वन परिक्षेत्र उत्तर उकवा सामान्य द्वारा

बताया गया कि वे नेहा श्रीवास्तव वनमण्डलाधिकारी उत्तर बालाघाट सामान्य के निर्देशन में लगातार सर्प रेस्क्यू का काम कर रहे है । इनके द्वारा लोगों से अपील की है कि सांप काटने पर झाड़फूंक न कराएं। इसके बजाय तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराएं। डॉक्टरों के अनुसार देरी से इलाज कराने पर जान का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने लोगों को जमीन पर सोने से भी मना किया है। बाहर निकलते समय पर्याप्त उजाला, पैरों में जूते और घर के आसपास साफ सफाई रखने अपील किया है। वर्तमान में सर्प ज्यादा निकलते है और सर्प दंश की घटना ज्यादा होती है । यदि किसी को सर्पदंश हो तो तत्काल हॉस्पिटल जाए।

मरीज को तत्काल हॉस्पिटल लेकर जाए- चूरन कुमार मड़ावी

चूरन कुमार मड़ावी परियोजना सहायक ने बताया कि जब उन्हें सूचना मिली कि सर्प ने एक व्यक्ति को काटा है तो उन्होंने सांप की फोटो और काटे गए अंग की फोटो सचिन पदमें वनरक्षक को भेजा उनके द्वारा बताया गया कि विषैला सर्प बम्बू पीट वाइपर है । मरीज को तत्काल हॉस्पिटल लेकर जाए और जयप्रकाश मड़ावी, वनरक्षक के साथ तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। जहां मजदूर को तुरंत ही चिकित्सकों ने उपचार दिया । जिसके बाद मजदूर आज वह स्व: कुशल है। उन्होंने बताया कि कोई भी सर्प काटने की स्थिति में गांव में झाड़फुक आदि के चक्कर में न जाए । सांप काटने वाले व्यक्ति को तत्काल ही चिकित्सा उपचार दें। जिससे कि उनकी जान बचाई जा सकती है।

राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन आज से

बालाघाट(पद्मेश न्यूज)। मध्य प्रदेश जूडो एसोसिएशन द्वारा सब जूनियर तथा केडेट बालक बालिका राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन 22 अगस्त से 24 अगस्त तक इंदौर जिला एसोसिएशन द्वारा मध्य प्रदेश जूडो एसोसिएशन के अध्यक्ष जगजीत सिंह सेधु ,सचिव ,नरेश टटवाड़े, के निर्देश अनुसार किया जा रहा है । जिसमें निर्णायक के रूप में मध्य प्रदेश के कोषाध्यक्ष आबिद खान द्वारा प्रतियोगिता संपन्न करवाने में सहयोग किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में बालाघाट जिले खिलाड़ी सहभागी हो रहे हैं । बालाघाट जिला खेल विभाग जिला खेल अधिकारी अभिषेक चौधरी एसडीओपी वारासिवनी तथा मुख्य प्रशिक्षक संतोष पारधी युवा समन्वयक कटंगी के मार्गदर्शन में बालाघाट टीम कोच शुभम मनेश्वर द्वारा सब जूनियर तथा केडेट वर्ग ,हर्ष अनिल पंचेश्वर, हिमांशु दिलीप डोंगरे दो छात्रो के साथ शामिल होकर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे जिसमें कराटे संस्था संरक्षक अनिल धुवारे अध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी उपाध्यक्ष रविंद्र भाटिया सह सचिव चंद्रकांत पीपलेवार, सदस्य राजेंद्र बल्ले, वीरेंद्र ब्रह्ममे साक्षी खैरकर ,संजू मेश्राम गणेश बूढ़े उर्वशी चौधरी, विनय श्रीवास्तव प्रधान पाठक कटंगी कन्या शालाएम,एल भलावी जिला खेल विभाग के सभी समन्वयक प्रशिक्षक कर्मचारी द्वारा प्रतियोगिता में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं प्रदान की गई ।

मजदूरी करने गये पति के घर नही आने पर एक महिला पराए मर्द के झांसे में आई

महिला ने लगाये शादी का झांसा देकर देहशोषण करने का आरोप, आरोपी संदीप परवार गिरफ्तार-भेजा गया जेल

बालाघाट(पद्मेश न्यूज)। अन्य राज्य में मजदूरी करने गए पति के कई दिनों तक घर नहीं लौटने पर एक महिला ने पराए व्यक्ति द्वारा शादी करने दिये गए झांसे में आकर अपना बसा बसाया घर ही बर्बाद कर दी और बाद में इस महिला ने इस पराए व्यक्ति पर शादी करने का झांसा देकर देहशोषण करने का आरोप लगा दी। यह घटना मलाजखंड थाना क्षेत्र की है। मलाजखंड पुलिस ने30 वर्षीय महिला द्वारा की गई रिपोर्ट पर संदीप पिता चमन दास परवार 33 वर्ष ग्राम मोहगांव निवासी के विरुद्ध इस महिला का देश शोषण करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज कर उसे इस अपराध में गिरफ्तार कर लिया जो इन दिनों न्यायिक अभिरक्षा में बैहर जेल में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सन 2013 में इस महिला की शादी गढ़ी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक लड़के के साथ दोनों के पसंद से हुई थी । जिनकी एक बेटी है।सन 2019 में इस महिला का पति गुजरात मजदूरी करने चला गया था। इसी दौरान इस महिला की पहचान संदीप परवार ग्राम मोहगांव निवासी से हुई थी और दोनों की मोबाइल से बातचीत होते रहती थी। जिसके बाद संदीप परवार का इस महिला के घर आना जाना शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे।संदीप परवार ने इस महिला को शादी करने का झांसा देने लगा था। यह महिला अपने पति के कई दिनों तक घर नहीं आने से परेशान होकर और संदीप परवार के झांसे में आकर उससे शादी करने तैयार हो गई थी। जिसके बाद संदीप परवार इस महिला को शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा था। उस समय यह महिला अपनी बेटी के साथ में रहती थी। संदीप परवार द्वारा शारीरिक संबंध बनाने से यह महिला गर्भवती हो गई। इस महिला के गर्भवती होने के संबंध जब उसके पति को मालूम हुआ। तब इस महिला को उसके पति ने बोला कि जिसका बच्चा है उसके साथ ही रहो और उसने इस महिला को साथ रखने से इंकार कर दिया और अपनी बेटी को अपने साथ रख लिया।जिसके बाद महिला ने गर्भवती होने के संबंध में संदीप परवार को बताई। तब संदीप परवार ने इस महिला को अपने साथ सन्तापुर ले गया। संदीप परवार ने इस महिला को वहा दो माह तक रखा। वहा संदीप परवार के माता-पिता को पता चलने पर संदीप परवार इस महिला को बैहर लेकर आया और नर्सिंग टोला बैहर में किराये के कमरे में इस महिला को अपने साथ रखा। उस समय यह महिला तीन माह की गर्भवती थी। किंतु बाद में अपने आप मिसकैरेज हो गया था। महिला को शक हुआ कि संदीप परवार ने खाने में कुछ मिलाकर दिया है जिससे मिसकैरेज हो गया है। नर्सिंग टोला बैहर में यह महिला संदीप परवार के साथ डेढ़ माह रही। 23 जुलाई 2025 को संदीप परवार इस महिला को छोड़कर कहीं चला गया था। संदीप परवार से बात नहीं होने ओर उसके नही आने से यह महिला परेशान हो गई थी। तब वह संदीप परवार को ढूंढते हुए उसके ग्रह ग्राम मोहगांव गई। जहां पर संदीप परवार तो नही मिला किंतु उसके भाई और पिता ने इस महिला से लड़ाई झगड़ा कर उसे मारपीट किए और घर से निकाल दिए थे। जिसकी रिपोर्ट इस महिला ने मलाजखंड थाना में की थी। 4 अगस्त 2025 को संदीप परवार नर्सिंगटोला बैहर आया और इस महिला को अश्लील गालियां देते हुए बोला कि मेरे पापा और भाई के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई यह कहते हुए संदीप परवार इस महिला से शादी करने से इंकार हो गया और ज्यादा कुछ बोलने पर संदीप परवार ने इस महिला को जान से मरवाने की धमकी दे दी। संदीप परवार द्वारा शादी करने इंकार होने के बाद यह महिला रिपोर्ट करने के लिए मलाजखंड पुलिस थाना पहुंची। मलाजखंड पुलिस ने इस 30 वर्षीय महिला द्वारा की गई रिपोर्ट पर संदीप पिता चमन दास परवार 33 वर्ष ग्राम मोहगांव निवासी के विरुद्ध 69 296 351(3) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपराध दर्ज किये। और जांच विवेचना दौरान संदीप परवार को इस अपराध में गिरफ्तार कर लिए । जो इन दोनों न्यायिक अभिरक्षा में बैहर जेल में है।

दो साल पहले सीएम राइज विद्यालय की हुई थी घोषणा, सुविधा की बजाय नाम बदल रही सरकार

नाम का सीएम राइज विद्यालय, ना भवन मिला, ना सुविधा और ना ही खेल मैदान, छात्र-छात्राएं,

अभिभावक व क्षेत्रीयजनों ने सीएम राइज (सांदीपनी स्कूल) का भवन निर्माण कर सभी सुविधा उपलब्ध करवाने की शासन-प्रशासन से की मांग

लालबर्रा (पद्मेश न्यूज)। प्रदेश सरकार के द्वारा तीन वर्ष पूर्व शासकीय स्कूल के बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने एवं प्रायवेट स्कूल की तरह शिक्षा व सुविधा उपलब्ध करवाने की मंशा से प्रदेश के हर विकासखण्ड में प्रथम चरण में एक-एक सीएम राइज स्कूल खोलने की घोषणा की थी। इसी घोषणा के अनुसार नगर मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालबर्रा को सीएम राइज स्कूल बनाया गया था एवं अन्य प्रक्रियाएं भी प्रारंभ हो चुकी थी। लेकिन बाद में उत्कृष्ट विद्यालय के स्थान पर लेण्डेझरी को सीएम राइज विद्यालय बना दिया गया था। जिसके बाद से लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त था। जिसको देखते हुए शासन के द्वारा द्वितीय चरण में दो वर्ष पूर्व शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्रा को सीएम राइज विद्यालय बनाया गया है परंतु यह विद्यालय नाम मात्र का सीएम राइज विद्यालय है क्योंकि विद्यालय के पास ना ही नवीन सर्वसुविधायुक्त भवन है, ना ही छात्र-छात्राओं के खेलने के लिए बेहतर खेल मैदान है। जबकि शासन के द्वारा जब तीन साल पहले सीएम राइज स्कूलों की शुरूआत की गई थी, उस समय सरकार ने बड़ी-बड़ी घोषणा करते हुए कहा था कि ये निजी स्कूलों से भी बेहतर सर्वसुविधायुक्त स्कूल बनेगें और शासन का प्रस्ताव भी कुछ ऐसा ही था। यहीं वजह थी कि अधिकांश विद्यार्थियों ने सीएम राइज विद्यालय में प्रवेश भी लिया है और वर्तमान में लालबर्रा सीएम राइज विद्यालय (सांदीपनी स्कूल) में के.जी. वन से लेकर कक्षा 12 वीं तक 1676 विद्यार्थी अध्ययनरत है।

पुराने भवन में ही संचालित हो रही है कक्षाएं

सीएम राइज विद्यालय की घोषणा होने के बाद भी अब तक नवीन भवन की स्वीकृति नहीं मिल पाई है। यही वजह है कि कक्षाएं भी पुराने भवन में ही संचालित हो रही है, ऐसी स्थिति में बच्चों की दर्ज संख्या अधिक होने व कमरे की कमी के चलते छात्र-छात्राओं को पढ़ाई करने एवं शिक्षकों को अध्ययपन कार्य करवाने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं पुराने क'चे भवन में तेज बारिश होने पर पानी का रिसाव होता है जिसकी रोकथाम के लिए स्कूल प्रशासन के द्वारा पालीथिन लगा दिया गया है। लेकिन अब तक नवीन भवन एवं सीएम राइज स्कूल में जो सुविधा मिलती है, वह सुविधा लालबर्रा के सीएम राइज उत्कृष्ट विद्यालय को नही मिल रही है। इस तरह से सरकार के द्वारा दो वर्ष पूर्व ही उत्कृष्ट विद्यालय को सीएम राइज विद्यालय बनाये जाने की घोषणा कर दी है, लेकिन सर्वसुविधायुक्त भवन के लिए अब तक शासन के द्वारा राशि स्वीकृत नही की गई है। वहीं विभागीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा कहा जा रहा है कि सीएम राइज विद्यालय के नवीन भवन निर्माण के लिए जगह देखी जा रही है जैसे जगह मिलती है शासन को राशि स्वीकृति के लिये पत्र भेज दिया जायेगा। अब देखना है कि स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा लालबर्रा में सीएम राइज विद्यालय के नवीन भवन की स्वीकृति व अन्य सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध करवाने में किस तरह के सार्थक प्रयास किये जाते है।

1676 विद्यार्थी है दर्ज, सुविधाओं की कमी

आपकों बता दे कि सरकार के द्वारा दो वर्ष पूर्व लालबर्रा स्थित उत्कृष्ट विद्यालय को सीएम राइज स्कूल बनाया गया है और सीएम राइज स्कूल का नवीन भवन बनना प्रस्तावित भी है। लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक शासन स्तर से सीएम राइज स्कूल के नवीन भवन के लिए राशि स्वीकृत नही हो पाई है। जबकि लंबे समय से लालबर्रा क्षेत्र के छात्र-छात्राएं व अभिभावक सीएम राइज के नवीन भवन निर्माण होने का इंतजार कर रहे है और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने भी पूर्व में लालबर्रा मुख्यालय में सीएम राइज स्कूल का भवन जल्द बनने की बात कही थी। साथ ही भवन निर्माण के लिए भूमि भी देखा जा रहा है, लेकिन अब तक भवन के लिए जगह उपलब्ध नही हो पाया है। जबकि जिस स्थान पर वर्तमान समय में स्कूल संचालित हो रहा है एवं खेल मैदान दोनों को मिलाकर भवन निर्माण के लिए पर्याप्त जगह है। लेकिन अब तक नवीन भवन निर्माण के लिए शासन से राशि स्वीकृत नही हो पाई है, ना ही सीएम राइज स्कूल की तर्ज पर शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। पुराने शिक्षक-शिक्षिकाओं के द्वारा ही शिक्षा अध्यापन कार्य संपन्न करवाया जा रहा है। जबकि क्षेत्र के अभिभावक उत्कृष्ट विद्यालय सीएम राइज स्कूल बन गया है समझकर अपने ब'चों को स्कूल भेज रहे है एवं बच्चें आ भी रहे है। लेकिन उन्हे सीएम राइज स्कूल में जो सुविधा मिलनी चाहिए वहां नही मिल पा रही है। इस तरह से सरकार की सीएम राइज स्कूल की घोषणा अधुरी नजर आ रहे है। वहीं स्कूल में केजी वन से लेकर कक्षा 12 वीं तक 1676 विद्यार्थी दर्ज है एवं 32 नियमित, 14 अतिथि शिक्षक पदस्थ है जिनके द्वारा शिक्षा अध्यापन कार्य संपन्न करवाया जा रहा है।

सीएम राइज स्कूल की तरह विद्यार्थियों को नही मिल रही है सुविधा - सुमित

सीएम राइज उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्रा विधायक प्रतिनिधि सुमित स्वामी ने बताया कि लालबर्रा मुख्यालय स्थित उत्कृष्ट विद्यालय दो वर्ष पूर्व सीएम राइज स्कूल बन चुका है एवं भवन निर्माण के लिए घोषणा भी हो चुकी है। लेकिन अब तक नवीन भवन निर्माण एवं राशि की स्वीकृति नही हो पाई है। जिस कारण से पुराने भवन में ही स्कूल संचालित हो रहा है और सीएम राइज स्कूल की तरह विद्यार्थियों को सुविधाएं नही मिल पा रही है। श्री स्वामी ने बताया कि स्कूल में लगभग 1700 विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन कर रहे है लेकिन भवन के अभाव में उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। जबकि सीएम राइज स्कूल में अन्य स्कूलों की तुलना बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने की मंशा से शुरू की गई है लेकिन सरकार सुविधा उपलब्ध करवाने के स्थान पर स्कूल का नाम परिवर्तित कर रही है। शासन-प्रशासन से मांग है कि सीएम राइज स्कूल प्रस्तावित है जो स्वीकृति प्रदान कर नवीन भवन का निर्माण कर अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाये।

सीएम राइज विद्यालय के लिए प्रस्तावित है नाम - दुबे

सीएम राइज विद्यालय प्रभारी प्राचार्य सनत दुबे ने बताया कि दूसरे चरण में उत्कृष्ट विद्यालय का नाम सीएम राइज विद्यालय के लिए प्रस्तावित है जिसकी वजह से स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या में वृध्दि पिछले कुछ वर्षों की अपेक्षा अधिक हुई है और केजी 1 से लेकर 12 वीं तक लगभग 1700 बच्चे अध्ययनरत है। साथ ही बच्चों की संख्या बढ़ने एवं कमरों की संख्या कम होने से अध्ययपन कार्य में कुछ परेशानी होती है। श्री दुबे ने बताया कि पुराने भवन का मरम्मत कार्य करवाकर कक्षा संचालित की जा रही है और हमारा विद्यालय सीएम राइज विद्यालय के लिए प्रस्तावित है। उसे स्वीकृति प्रदान कर और नवीन भवन का निर्माण किया जाता है तो बच्चों को अच्छी सुविधा मिलेगी।

सभी दुकानदार एवं व्यापारीगण अपनी दुकानों के सामने प्राथमिकता से लगाये सीसीटीव्ही कैमरे - सुनिल

लालबर्रा (पद्मेश न्यूज)। नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अपराधों पर अंकुश लगाने और सामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने के लिए थाना प्रभारी सुनिल चतुर्वेदी ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि वे अपनी दुकानों के बाहर सड़क की ओर सीसीटीव्ही कैमरे प्राथमिकता से लगाये। इन कैमरों की मदद से सड़क पर होने वाली गतिविधियों और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जा सकती है। साथ ही उ'च गुणवत्ता वाले कैमरे लगाने की बात कही है ताकि फुटेज साफ हो और अपराधियों की पहचान आसानी से की जा सके। श्री चतुर्वेदी ने बताया कि कुछ मामलों में अपराधी वारदात के बाद कैमरों को नुकसान पहुंचा देते हैं, जिससे जांच में बाधा आती है। इसलिए कैमरों की सुरक्षा और उनकी सही दिशा में लगाने पर भी ध्यान देना जरूरी है। श्री चतुर्वेदी ने बताया कि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पुलिस और जनता के आपसी सहयोग से ही संभव है। सीसीटीवी नेटवर्क का विस्तार होने से न केवल अपराध कम होंगे, बल्कि महिला सुरक्षा को भी और अधिक मजबूती मिलेगी। वर्तमान में जिले में लगे कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है, जिससे घटनाओं पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित हो रही है। इसलिए लालबर्रा नगर के दुकानदार एवं व्यापारीगण अपने दुकानों के सामने प्राथमिकता से सीसीटीव्ही कैमरे लगाये।

जनपद में प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना का शिविर आज

लालबर्रा (पद्मेश न्यूज)। नगर मुख्यालय स्थित जनपद पंचायत के सभाकक्ष में 22 अगस्त को प्रात: 11 बजे से प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजनांतर्गत शिविर का आयोजन किया गया है। चर्चा में विद्युत विभाग के कनिष्ठ यंत्री सरफराज कुरैशी ने बताया कि उ'चाधिकारियों के मार्गदर्शन में भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के प्रचार प्रसार हेतु इस शिविर का आयोजन किया गया है। जिसमें प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं योजना अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी सहित घर में सोलर रूफ टॉप लगाने से होने वाले फायदे के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी जायेगी। साथ ही किसानों को सोलर पंप भी उपलब्ध करवाया जायेगा। श्री कुरैशी ने समस्त पंचायत कर्मियों एवं क्षेत्रवासियों व किसानों से अधिक से अधिक संख्या में जनपद पंचायत लालबर्रा में आयोजित शिविर में पहुंचकर प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना व सोलर पंप योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लाभ लेने की अपील की है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए मिट्टी की प्रतिमा निर्माण का प्रस्फुटन समितियों को दिया गया प्रशिक्षण

लालबर्रा (पद्मेश न्यूज)। नगर मुख्यालय के कम्प्यूटर केन्द्र में जन अभियान परिषद के द्वारा बुधवार को ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों को प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम धनेंद्र भलावी जनपद सदस्य के मुख्य आतिथ्य, जिला समन्वयक सुशील बर्मन, ब्लॉक समन्वयक श्रीमती बैजंती कटरे, सहित अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रारंभ हुआ। जिसमें सर्वप्रथम उपस्थितजनों ने माँ सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्र'वलित कर माल्यार्पण किया। पर्यावरण संरक्षण के लिए मिट्टी की प्रतिमा निर्माण के लिए विकासखण्ड के पांच सेक्टर के ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें उन्हे बताया गया कि पिछले दिनों नवांकुर सखियां जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बनी है जिन्हे एवं जन अभियान परिषद के सीएमसीएलडीपी के कोर्स कर रहे विद्यार्थियों व परामर्शदाताओं को अपने हाथों से मिट्टी का भगवान गणेश की प्रतिमाएं बनाने सहित अन्य प्रतिमा व मूर्ति कैसे बनाये उसके बारे में उमाशंकर खोलपीटने के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। वहीं मिट्टी की प्रतिमा निर्माण करने से उन्हे आय भी प्राप्त होगी और पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहतर होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनपद सदस्य धनेन्द्र भलावी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें मूर्तियों का निर्माण मिट्टी और प्राकृतिक चीजों से करना चाहिए और जो वर्तमान में प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं अन्य केमिकल्स का उपयोग करके जो मूर्तियां बना रहे हैं। इससे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, जिससे जीव जंतुओं को भी नुकसान होता है। जिला समन्वयक सुशील बर्मन ने प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को इस कार्यक्रम के उद्देश्य और कार्यक्रम की सारगर्भिता के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जन अभियान परिषद और नर्मदा समग्र का यह संयुक्त अभियान है कि हम जो भी मूर्तियां पूर्व में बनाते थे। वह अक्सर प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती थी और प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में घुलनशील नहीं होता है। जो जल प्रदूषण को बढ़ाता है इसलिए इस अभियान के अंतर्गत घर-घर गणेश, हर घर गणेश कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ग्रामीणों के माध्यम से अपने ही हाथों से श्री गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। ब्लाक समन्वयक श्रीमती बैजंती कटरे ने कहा कि जन अभियान परिषद के साथ-साथ नर्मदा समग्र के संयुक्त अभियान में पर्यावरण शुध्दता के संदेश को देने के लिए घर-घर गणेश, हर घर गणेश कार्यक्रम के अंतर्गत माटी के गणेश निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लालबर्रा में आयोजित ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित पांच सेक्टर की समितियों को मिट्टी की प्रतिमा किस तरह से बनाना है उसके बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। इस अवसर पर थानेंद्र ठाकरे, चंद्रकुमार बसेने, हेमराज अंगूरे, मुकेश गाड़ेश्वर, चैनलाल चौधरी, दामेंद्रप्रसाद हरिनखेड़े, प्रेमवती उईके, निकिता गोयल, पूजा बनवाले, सरिता यादव, उषा चौहान, कुंदन मड़ावी, फूलकली मात्रे, प्रियंका खैरवार, पुस्तकला सेलोकर, इंद्रिका डोंगरवार ,अनिता टेंभरे, विनीता इनवाती, प्रभात इनवाती, विकास पटले, जीवनलाल गाडेश्वर, कल्पना यादव, संगीता राणा, जयसिंह, महेंद्र कटरे, बेनीराम बोपचे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

दो दिन से लापता व्यक्ति का शव पुलिस ने किया बरामद

पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा, जांच में जुटी पुलिस

लालबर्रा (पद्मेश न्यूज)। लालबर्रा थानांतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत टेकाड़ी ला. निवासी 40 वर्षीय सालिकराम उइके का शव उसी के खेत के समीप से बुधवार की शाम में पुलिस ने बरामद किया है एवं दुसरे दिन गुरूवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टेकाड़ी ला. निवासी 40 वर्षीय सालिकराम उइके कृषि कार्य करता है, जो मंगलवार की सुबह बिना बताये कही चले गया था और परिजनों को लगा कि कही गया होगा, शाम तक घर आ जायेगा किन्तु वह देरशाम तक वापस घर नही आया तो परिजन घबरा गये। जिसके बाद आसपास एवं रिस्तेदारी में पतासाजी किये किन्तु कही कुछ पता नही चला। बुधवार की शाम में कुछ ग्रामीण जंगल से लगे अपने खेत की ओर घुमने गये थे तभी उन्हे एक व्यक्ति बेसुध अवस्था में दिखाई दिया और पास जाकर देखे तो वह सालिकराम था जिसकी मौत हो चुकी थी। जिसके बाद उसके परिजनों व पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। वहीं दो दिनों से लापता व्यक्ति का शव उसी के खेत के समीप मिलने की जानकारी ग्राम में आग की तरह फैल गई और घटना स्थल में लोगों की भीड़ लग गई। दो दिन से लापता व्यक्ति का शव मिलने की जानकारी पुलिस को लगी तो थाना प्रभारी के निर्देश पर उपनिरीक्षक महेन्द्रसिंह बघेल पुलिसबल के साथ घटना स्थल पहुंचकर आवश्यक

कार्यवाही कर शव बरामद कर लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर आये। किन्तु देरशाम हो जाने के कारण मृत व्यक्ति की लाश को शव वि'छेदन गृह में रखवा दिया गया एवं दुसरे दिन गुरूवार को चिकित्सक के द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक 40 वर्षीय सालिकराम उइके **कृषि कार्य करता था, जिसके परिवार में पत्नि, दो बच्चें है जो परिवार का मुखिया था। वहीं मृतक शराब का सेवन भी करता था जो बुधवार की सुबह बिना बताये कही चले गया था और दो दिन बाद उसकी लाश खेत के समीप मिली है, जिससे ऐसा लग रहा है कि वह नशे की हालत में खेत की ओर गया होगा और अचानक तबियत खराब होने, अधिक नशा करने। साथ ही दो दिनों तक जंगल के समीप पड़े रहने से सालिकराम के शरीर में जंगल के कीड़े-मकोड़े के काटने के निशान भी बने है जिससे संभावना व्यक्त की जा रही है कि जहरीले कीड़े-मकोड़े के काटने व अधिक नशा करने से उसकी मौत हुई होगी। वहीं सालिकराम की मौत किस वजह से हुई है, कारण अज्ञात है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी स्पष्ट हो पायेगा। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।**

मामले की जांच की जा रही है - महेन्द्र

दूरभाष पर चर्चा में उपनिरीक्षक महेन्द्रसिंह बघेल ने बताया कि बुधवार की शाम में टेकाड़ी ला. से सूचना मिली थी कि दो दिनों से लापता व्यक्ति का शव उसी के खेत के समीप देखा गया है। जिसके बाद घटना स्थल पहुंचकर सालिकराम उइके का शव बरामद कर लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया एवं दुसरे दिन गुरूवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया है और मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है।

शासकीय विद्यालयों में पंखों की कमी से विद्यार्थी हो रहे परेशान

पंखे खरीदी का फंड तकनीकी खराबी से हो गया है वापस

वारासिवनी(पद्मेश न्यूज)। वारासिवनी विकास खंड अंतर्गत समस्त शासकीय हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में दूसरा सत्र प्रारंभ हो गया है। जहां पर पंखों की कमी बनी हुई है पर संस्था प्रमुख के द्वारा व्यवस्था बनाकर शिक्षा अध्ययन अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है। हालांकि जरूरत बनी हुई है पिछले सत्र के मार्च २०२५ में शासन के द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय वारासिवनी को राशि आवंटित की गई थी। किंतु तकनीकी खराबी के चलते आहरण नहीं हो पाया और सत्र समाप्त होते ही राशि शासन को वापस हो गई। जिसके कारण विद्यालयों में लगे हुए पंखे बदले नहीं गए और ना ही नए पंखों की खरीदी हो पाई है। ऐसे में किसी कक्षा में दो तो किसी कक्षा में तीन या कहीं एक पंखे में ही बच्चों को शिक्षा अध्ययन करना पड़ रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों सहित शिक्षक एवं पालको के द्वारा गर्मी से निजात दिलाने बेहतर व्यवस्था बनाने की मांग शासन प्रशासन से की जा रही है।

१६ विद्यालय को स्वीकृत की गई थी राशि

प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा ६ मार्च २०२५ को गर्मी से बचाव के लिए उपकरण खरीदी को लेकर आदेश जारी किया गया था। जिसमें स्वीकृति आदेश दिया गया था कि प्रदेश में करीब ८ करोड रुपये विभिन्न स्कूलों के लिए स्वीकृत किए गए थे। इसमें वारासिवनी विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अंतर्गत १६ विद्यालयों के लिए ३ लाख २० हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। वह भी प्रत्येक स्कूल में २०० विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर २०००० प्रति स्कूल के रूप में दिए गए थे। जिसके माध्यम से विद्यालयों में गर्मी से बचाव के लिए जरूरी व्यवस्था जैसे पंखे लगाए जाने थे।

तकनीकी खराबी से नहीं हो पाया राशि का आहरण

वारासिवनी विकासखंड अंतर्गत ११ हाई स्कूल एवं ११ हायर सेकेंडरी स्कूल इस प्रकार कुल २२ हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल स्थित है। जहां २०० से अधिक दर्ज संख्या के आधार पर १६ हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों को २०-२० हजार रुपये प्रति स्कूल आवंटित किया गया था। यह आदेश मार्च २०२५ में किया गया था जिसमें संबंधित विद्यालयों के द्वारा सूचना प्राप्त होते ही बिल तैयार कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को दिया गया। जहां लगातार लंबे समय तक पोर्टल की तकनीकी खराबी के कारण बिलों की स्वीकृति नहीं हो पाई। जिससे खरीदी का अभाव बना रहा वहीं मार्च के साथ ही वित्तीय सत्र समाप्त होते ही समस्त राशि शासन को वापस हो गई। ऐसे में पंखों की खरीदी स्कूलों के द्वारा नहीं की जा सकी जहाँ अति आवश्यक होने पर विद्यालय के द्वारा शाला विकास निधि या अन्य स्रोत से खरीदी की गई है। परंतु वह पर्याप्त नहीं है और कुछ विद्यालयों के पास पर्याप्त फंड नही होने पर उनके द्वारा प्राप्त साधन में ही व्यवस्था बनाने का कार्य किया जा रहा है।

उम्मस भरी गर्मी से विद्यार्थी हो रहे परेशान

शासकीय हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रत्येक कक्ष में पंखे तो लगे हुए हैं परंतु पर्याप्त नही होने के कारण समस्या बनी हुई है। जहां पर विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षा अध्ययन किया जा रहा है वर्तमान में गर्मी का मौसम चल रहा है जिसमें बारिश का मौसम बना रहता है। परंतु बारिश रुकते ही तेज धूप निकलती है जिससे उम्मस भरी गर्मी वातावरण में व्याप्त हो जाती है। लोग परेशान होने लगते हैं ऐसे में विद्यार्थियों को भी इस गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। कक्षा में कम पंखे होने से सभी विद्यार्थियों को पर्याप्त शीतल और ठंडी हवा नहीं मिल पा रही है। उनके द्वारा शासन से पुनः उक्त व्यवस्था के लिए राशि उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है ताकि पर्याप्त पंखे समस्त स्कूलों में लगाए जा सके।

स्कुलों में पंखे की आवश्यकता है यदि शासन राशि देती है तो उपयोग किया जायेगा-कुंजीलाल चौहान

शासकीय कमला नेहरू स्कुल के प्राचार्य कुंजीलाल चौहान ने बताया कि स्कूल में पंखे खरीदी के लिए मिलने वाली राशि का लेटर आया था परंतु राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। बाद में पता चला कि वह राशि शासन को वापस हो गई है हमारे यहां पर पंखे की जरूरत है १५ पंखे लगाये जा सकते हैं। एक कमरे में चार पंखे हमने अनिवार्य कर दिए हैं राशि यदि आती है तो अच्छी बात है अभी समस्या होने पर हमने शाला विकास निधि से पांच पंखे खरीदे हैं। काम चल रहा है किंतु जरूरत तो बनी हुई है बीते मार्च में यह राशि मिली थी किंतु उपयोग नहीं हो पाया।

तकनिकी खराबी के कारण शासन को राशि वापस हो गई-वीरेंद्र बनोटे

विकासखंड शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र बनोटे ने बताया कि मेरे द्वारा अभी कार्यालय का प्रभार लिया गया है इसकी जानकारी मुझे है नहीं हैं। किंतु हमारे कार्यालय सहायक ने मुझे इसमें बताया है कि मार्च में एक आवेदन आया था जिसमें हमारे यहां १६ संस्थाओं को २०-२० हजार रुपये राशि स्वीकृत की गई थी। किंतु जब तक संस्था के बिल प्रस्तुत किये गये तब तक तकनीकी खराबी के कारण राशि का आहरण नहीं किया जा सका। वह शासन को वापस हो गई स्कूलों में बच्चों के लिए पंखे जरूरी है वर्तमान में तो कोई बजट आया नहीं है यदि प्राप्त होता है तो तत्काल समस्त विद्यालयों को उपलब्ध कराया जायेगा।

मोटरसाइकिल की टक्कर से आवारा मवेशी की मौत

नगर में घुम रहे आवारा मवेशी से नगरवासियों में नपा के प्रति आक्रोश

वारासिवनी(पद्मेश न्यूज)। नगर के रामपायली रोड़ स्थित भगवान दत्तात्रेय मंदिर के पास में २१ अगस्त की शाम करीब ५.३० बजे मोटरसाइकिल की टक्कर से एक मवेशी की दर्दनाक मौत हो गई। यह मवेशी आवारा बताया जा रहा है जिसके मालिक का वर्तमान तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर की सबसे बड़ी समस्या आवारा मवेशी बने हुए हैं जो नगर के विभिन्न मार्गों पर बड़ी संख्या में घूमते रहते हैं। बीच मार्ग में बैठ जाते हैं या धमाचौकड़ी मचाकर लोगों को परेशान करते हैं, इस दौरान कई बार राहगीरों को दुर्घटनाग्रस्त होकर चोटिल भी होना पड़ता है। ऐसे ही प्रतिदिन की तरह रामपायली रोड़ पर दत्तात्रेय मंदिर के पास में आवारा मवेशी घूम रहे थे। जहां पर बुलट मोटरसाइकिल से जा रहा व्यक्ति और आवारा मवेशी में जबरदस्त टक्कर हो गई जिसमें मौके पर ही आवारा मवेशी गिरकर तड़पने लगा। तो वहीं मोटरसाइकिल चालक मौके से फरार हो गया घटना की जानकारी लगते ही नगर के गौ सेवक वेटरनरी डॉक्टर के साथ मौके पर पहुंचे किंतु तब तक उक्त आवारा मवेशी की मौत हो गई। इसके बाद मवेशी मलिक को सूचना देने के लिए सोशल मीडिया पर फोटो प्रसारित किया जा रहा है किंतु वर्तमान तक मवेशी के मालिक का पता नहीं चल पाया है। जिससे उक्त मवेशी रामपायली रोड़ पर दत्तात्रेय मंदिर के पास सड़क किनारे पड़ा हुआ है। विदित हो की नगर सहित क्षेत्र के लोग मवेशी पालते हैं जिसे सुबह और शाम दूध निकालने के लिए लाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। जो नगर के बालाघाट रोड़ रामपायली ,रोड़ कटंगी रोड़ में सुबह शाम घूमते रहते है। और इन मवेशियों के कारण कई बार दुर्घटनाएं भी घटित होती है। तो वहीं कुछ दुर्घटनाओं में इन्हें भी नुकसान सहन करना पड़ता है जिसको लेकर नगर पालिका के द्वारा लगातार कार्यवाही आवारा मवेशियों पर की जा रही है। किंतु मवेशी मालिकों के द्वारा अपने मवेशियों को सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है तो वहीं लंबे समय से नगर वासियों के द्वारा मवेशी मालिकों पर कार्यवाही की भी मांग की जाती रही है। किंतु आज तक इस पर कुछ हो नहीं पाया है ऐसे में इस मवेशी कि इस दर्दनाक मौत से गौ सेवको सहित नगर वासियो में आक्रोश व्याप्त है।

पुलिस ने किया पिकअप वाहन चोरी का खुलासा

मामले में एक आरोपी गिरफ्तार ,तीन आरोपी फरार

वारासिवनी(पद्मेश न्यूज)। नगर के लालबर्रा रोड़ से अज्ञात चोरों के द्वारा पिकअप वाहन चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी रूपेश बघेले को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं तीन आरोपी फरार है जिनकी पतासाजी की जा रही है। इनके द्वारा सेकंड हैंड पिकअप के इंजन को बदलने के लिए यह चोरी की गई थी। मामले में पुलिस के द्वारा पूर्व में दर्ज अपराध में रूपेश बघेल को न्यायालय के समक्ष पेश किया है।

यह था मामला

ग्रामीण निखिल राहंगडाले निवासी सिवनघाट थाना रामपायली ने नगर के लालबर्रा रोड़ स्थित एहफाज की दुकान में अपनी पिकअप क्रमांक एमपी ५० जी १८४६ के इंजन का काम करने के लिए दिया हुआ था। जो दुकान में रात्रि के समय खड़ी कर सब घर चले गए थे जहां सुबह आए तो देखे की मौके पर पिकअप वाहन नहीं है। जिसकी आसपास पतासाजी की गई की गई तो कहीं पता नहीं चला जिसे ११ अगस्त की दरमियानी रात अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया था। इसके बाद प्रार्थी निखिल रहाँगडाले के द्वारा थाना वारासिवनी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी पिकअप वाहन क्रमांक एमपी ५० जी १८४६ को इंजन का काम कराने हेतु लालबर्रा रोड़ स्थित एहफाज भाई की दुकान पर खड़ा किया गया था। जिसे रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा टोचन कर चोरी कर ले जाया गया। पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक ४१९/२०२५ धारा ३०३ २ बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया वहीं तलाश प्रारंभ कर दी गई।

इंजन बदलने को लेकर की गई थी पिकअप चोरी

उक्त चोरी के मामले में पुलिस के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हेमंत नायक के नेतृत्व में चोरी गये वाहन एवं अज्ञात आरोपी की तलाश हेतु विशेष टीम गठित की गई। जिनके द्वारा लगातार ५० से अधिक सीसीटीव्ही फुटेज खंगाले गये व तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण कर तलाश की गई। विवेचना के दौरान चोरी गया अशोक लीलैंड का पिकअप वाहन एवं चोरी में प्रयुक्त टोचन वाहन ग्राम बड़गांव स्थित तालाब किनारे इंजन बदलते हुए दिखे। मौके पर पुलिस के द्वारा छापामार कार्यवाही की गई जहां कार्यवाही के दौरान आरोपी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गये। लगातार प्रयासों से मुख्य आरोपी रुपेश पिता धरमचंद बघेले उम्र २१ वर्ष निवासी प्रेमाटोला मरेरा थाना लालबर्रा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने सेकंड हैंड अशोक लीलैंड पिकअप वाहन खरीदा था जिसके इंजन में खराबी थी। घटना वाले दिन उसने मैकेनिक एहफाज भाई की दुकान पर खड़े एक पिकअप वाहन को देखा और इंजन बदलने की योजना बनाकर अपने तीन साथियों के साथ वाहन चोरी कर लिया।

पुलिस ने दो पिकअप एवं इंजन किया जप्त

मामले में पुलिस के द्वारा आरोपी रूपेश बघेले को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। वहीं फरार आरोपी में ३ दोस्तो की तलाश की जा रही है। मामले में पुलिस ने इनके पास से चोरी गया अशोक लीलैंड पिकअप वाहन चोरी में प्रयुक्त अशोक लीलैंड पिकअप वाहन एवं एक खुला इंजन एवं टोचन हेतु प्रयुक्त रस्सी को जप्त किया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी हेमंत नायक ,उपनिरीक्षक पवन यादव ,सहायक उपनिरीक्षक महाल सिंह धुर्वे ,आरक्षक हेमंत बघेल, तारेन्द बिसेन ,शिवदत्त शर्मा, कल्याण सिंह भदौरिया ,आर. जय भगत सायबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

आवारा श्वानो के हमले से वानर की मौत : वन विभाग ने कार्यवाही कर वानर के शव को किया नष्ट

वारासिवनी(पद्मेश न्यूज)। नगर में आवारा श्वानो का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जिनके द्वारा आम लोगों के साथ वन्य प्राणी एवं मवेशियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर के न्यायालय के पीछे आवारा श्वानो ने एक वन्य प्राणी वानर के ऊपर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जहां मौके पर उसकी मौत हो गई सूचना पर वन विभाग के द्वारा वानर के शव को बरामद कर नष्ट करने की कार्यवाही की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर में लगातार आवारा श्वान चौक चौराहा वह गलियों में भ्रमण करते रहते हैं। जिनके द्वारा बीते कुछ समय से नगर में घूम रहे आवारा मवेशी वन्य प्राणी सहित आम इंसान पर भोकना दौड़ना और हमला करने जैसे कार्य करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी जा रही है। जिसको लेकर अनेकों बार लोगों के द्वारा इन आवारा श्वानो पर कार्यवाही करने की मांग की जा चुकी है किंतु नपा के द्वारा इस पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे ही कुछ आवारा श्वान वार्ड नंबर १५ सिविल लाइन वारासिवनी न्यायालय के पीछे भ्रमण कर रहे थे। जहां वृक्ष के ऊपर एक वानर बैठा हुआ था जो नीचे आया तो अचानक उसके ऊपर करीब एक दर्जन आवारा श्वानो के द्वारा हमला कर दिया गया। जिसमें वानर के द्वारा भागने और बचने के कई प्रयास किए गए । किंतु उक्त आवारा श्वान इतने खूंखार हो गए थे कि मौके पर उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा भी मामले में दखल देकर आवारा श्वान को भगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इस दौरान बुरी तरह वानर को आवारा श्वानो के द्वारा काट लिया गया जहां मौके पर ही वानर की गंभीर रूप से घायल होकर मौत हो गई।

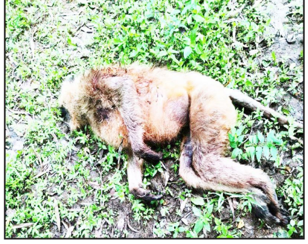

घटना की जानकारी लगते ही वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे जिनके द्वारा घटना स्थल पर मृत अवस्था में पड़े हुए वानर को उठाकर दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र कार्यालय वारासिवनी में लाया गया। जहां पर आवश्यक कार्यवाही करने के बाद वानर के शव को नष्ट कर दिया गया। इस दौरान प्रत्यक्षदर्शी यह घटना देख काफी दहशत में आ गए की कभी किसी आवारा श्वान के द्वारा किसी व्यक्ति या घर के सामने खेल रहे बच्चों पर हमला किया गया तो क्या स्थिति होगी यह सोचकर वह काफी डरे हुए हैं। उक्त श्वान नगर के विभिन्न स्थानों पर झुंड के रूप में भ्रमण करते रहते हैं जो खतरे का घर साबित हो रहे हैं। ऐसे में नगर के जागरूक नागरिकों के द्वारा उक्त आवारा श्वानो के ऊपर कार्यवाही करने की मांग की जा रही है ताकि कोई बड़ी दुर्घटना घटित ना हो।

महाविद्यालय में मनाया गया सद्भावना दिवस दिलाई गई शपथ

लामता(पद्मेश न्यूज)। गुंजे गगन में महके पवन में हर एक मन में सद्भावना शासकीय महाविद्यालय लामता की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा आज दिनांक 20 अगस्त 2025 को सद्भावना दिवस महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ सुनीता वैद्य की

अध्यक्षता में मनाया गया और सद्भावना शपथ भी दिलाई गई यह दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य देश में शांति, राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, अहिंसा और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना है, राष्ट्रीय सेवा योजना समाज सेवा के साथ जन जागरूकता अभियान के प्रति के स्वयंसेवक समर्पित भाव से कार्य करते हैं और आज स्वयंसेवकों के द्वारा सद्भावना का संदेश दिया गया सभी को मिलजुल कर रहने की बात बताई गई कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर डुलेश्वरी टेम्भरे के द्वारा बताया गया कि सबके लिए समान भाव अपने मन में रखने चाहिए सद्भावना शपथ एवं संतुष्टि कार्यक्रम में श्रीमती वंदना उरकूड़े, श्रीमती चित्रमाला भीमटे, श्री निरंजन, श्री प्रवेश यादव, डॉक्टर ढालसिंग गौतम राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों में हरेंद्र बघेल, रीना, सुप्रिया और नव प्रवेशित स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

वोट चोरी : तू इधर उधर की बात न कर

भारत में इन दिनों वोट चोरी का मुद्दा आम लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में होने वाले चुनावों की हालांकि पूरे विश्व में सराहना की जाती है परन्तु यह भी सही है कि इन चुनावों की पारदर्शिता को लेकर भी दशकों से सवाल उठते रहे हैं। आज यदि ई वी एम से होने वाली कथित धांधली पर सवाल उठाया जाता है तो बैलेट पेपर और मत पेटी के दौर में बूथ कैप्चरिंग व वोट गिनती में धांधली के आरोप भी लगते रहे हैं। परन्तु पिछले दिनों इस सम्बन्ध में उठा विवाद कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ गया है। इस विवाद में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी व चुनाव आयोग है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में इण्डिया गठबंधन के सभी दल। यह विवाद दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव व कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद उस समय शुरू हुआ, जब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में गड़बड़ियों और वोटर फ्रॉड के गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित अनेक विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर चुनावों में बेईमानी की गयी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं और डुप्लिकेट वोटर की प्रविष्टियां बनाई गई हैं। कि कई जगह तो मतदाताओं के नाम सूची से भी हटा दिए गए हैं । इस संबंध में राहुल गाँधी ने चुनाव आयोग द्वारा ही उपलब्ध कराये गये वोटर लिस्ट के विशाल भंडार के शोध के आधार पर ही विशेष रूप से कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया। उन्होंने अपनी पड़ताल में पाया कि अकेले महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में ही डुप्लिकेट प्रविष्टियों और फर्जी पतों के द्वारा 1,00,250 वोट चुराए गए। विपक्ष के मुताबिक इस तरह की गड़बड़ियों के कारण ही कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को 2024 के चुनाव में पराजय हुई। विशेष रूप से उन सीटों पर जहां हार का अंतर 50,000 वोटों से कम था। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक दावा किया कि इसी वोटर फ्रॉड की वजह से ही कांग्रेस को लगभग 70 लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ। इसी बीच बिहार में निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से पूर्व चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) का काम शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में बिहार की मतदाता सूची से लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिसे विपक्ष ने वोट चोरी का हिस्सा बताया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए चुनाव आयोग को इन हटाए गए नामों का विवरण और कारण सार्वजनिक करने का निर्देश दिया। उसके बाद ही चुनाव आयोग ने इन्हें सार्वजनिक किया। एक तरफ तो विपक्ष अर्थात इण्डिया गठबंधन, इस पूरे प्रकरण को लेकर चुनाव आयोग की बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगा रहा है जबकि बीजेपी व चुनाव आयोग इसे विपक्ष की बौखलाहट और अनर्गल आरोप करार दे रहे हैं। पहले भी चुनाव आयोग विपक्ष के इस तरह के आरोपों को बार-बार खारिज करता रहा है। परन्तु कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक ने इस मुद्दे को जनता तक ले जाने के लिए वोट चोरी से आजादी अभियान शुरू किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गत 17 अगस्त, 2025 को चुनावी राज्य बिहार के सासाराम से अपनी 16 दिवसीय मतदाता अधिकार यात्रा शुरू की। 1,300 किलोमीटर की यह यात्रा 1 सितंबर को पटना में एक विशाल रैली के साथ समाप्त होगी, जिसमें विभिन्न भारतीय राजनैतिक दलों के नेता शामिल होंगे। दूसरी तरफ ठीक उसी दिन व उसी समय यानी 17 अगस्त 2025 को ही चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि मतदाता सूची की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत है। आयोग ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की जांच के लिए समय दिया जाता है, लेकिन विपक्ष ने समय पर आपत्तियां दर्ज नहीं कीं।

महामहिम की जबावदेही से आदिवासी क्षेत्रों को नई ताकत

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार इस बात को लेकर मोर्चा खोले हुए है कि जब संविधान राष्ट्रपति और राज्यपाल को निर्णय लेने की समय सीमा में नहीं बांधे हुए है तो कोर्ट क्यों निर्णय ले। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों और राष्ट्रपति के पास लंबित पड़े विधेयकों पर समय-सीमा तय करने का ऐतिहासिक फैसला दिया है, तो सवाल केवल विधेयक मंजूरी की देरी का नहीं है। प्रश्न यह है कि पाँचवीं और छठी अनुसूची जैसे विशेष संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद पिछले सात दशकों में राज्यपालों और राष्ट्रपति—दोनों ने ही इन संवैधानिक दायित्वों का पालन शायद ही कभी गंभीरता से किया। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला केवल सामान्य केंद्र-राज्य विवादों तक सीमित नहीं है, बल्कि पंचम और षष्ठम अनुसूची के क्षेत्रों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं और अधिकारों से भी गहराई से जुड़ा है। बहस इस पर नहीं है कि लोकतंत्र के संरक्षक के तौर पर राज्यपाल और राष्ट्रपति ने अपनी भूमिका नहीं निभाई है और इन्हें कैसे जबावदह बनाया जाए। संविधान सभा में जब पाँचवीं और छठी अनुसूची पर चर्चा हो रही थी, तब आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा ने साफ़ कहा था। आदिवासी समाज हजारों वर्षों से अपनी ग्रामसभाओं और पारंपरिक शासन व्यवस्था से चलता आया है। यह केवल प्रशासनिक संरचना नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। यदि संविधान इन परंपराओं को मान्यता नहीं देगा, तो आदिवासी समाज अपने को ठगा हुआ महसूस करेगा। इसी बहस के दौरान डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भी स्पष्ट किया था कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका केवल औपचारिक नहीं होगी, बल्कि वह संरक्षक की तरह कार्य करेंगे। लेकिन दुख की बात है कि संविधान की यह दृष्टि कभी व्यवहार में नहीं उतरी। राज्यपाल राजनीतिक संतुलन साधने में उलझे रहे और राष्ट्रपति ने भी स्वतंत्र रिपोर्टों को नजरअंदाज कर दिया।

आदिवासी इलाकों में राज्यपालों की निष्क्रियता

पंचम अनुसूची विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय समुदायों के प्रशासन से संबंधित है। इसके अंतर्गत, अनुच्छेद 244(1) स्पष्ट करता है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का शासन विशेष प्रावधानों के अधीन होगा। राज्यपाल को यह शक्ति दी गई है कि वह इन क्षेत्रों में लागू होने वाले किसी भी राज्य विधान को, चाहे पारित हो चुका हो, अस्वीकार, संशोधित या निलंबित कर सकता है। राज्यपाल पर यह संवैधानिक दायित्व डाला गया है कि वह समय-समय पर राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर स्वतंत्र और निष्पक्ष रिपोर्ट भेजें। परंतु वास्तविकता यह है कि संविधान लागू होने के बाद से बार-बार रिपोर्टें समय पर और निष्पक्ष रूप में राष्ट्रपति को भेजे जाने का एक भी ठोस उदाहरण सामने नहीं आता। राज्यपालों ने इस शक्ति का उपयोग आदिवासियों के पक्ष में नीति-निर्माण को प्रभावित करने के लिए लगभग कभी नहीं किया। राज्यपाल के वार्षिक प्रतिवेदन का मकसद राष्ट्रपति को उस वर्ष अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन, विकास, कल्याण कार्यों की स्थिति के बारे में सूचित करना होता है। झारखंड जैसे राज्यों के इन प्रतिवेदनों में चल रही कल्याणकारी योजनाओं का विवरण, लाभार्थियों की संख्या, खर्च का ब्यौरा और बजटीय आवंटन शामिल होता है। लेकिन बहुतायत में ऐसे प्रतिवेदनों में इन क्षेत्रों में आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा, भूमि हस्तांतरण पर रोक, जनजातीय परामर्शदात्री परिषद के कार्य या प्रदर्शन का कोई जिक्र नहीं होता। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, वन अधिकार, खनन जैसे महत्वपूर्ण कानूनों के जनजातीय समुदायों पर पड़ने वाले प्रभावों को भी प्रतिवेदन में नहीं दर्शाया जाता। संविधान की अपेक्षाओं और व्यवहार में भारी अंतर रहा है। 2016 में जब झारखंड की राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण और टेनेंसी कानूनों में संशोधन का प्रयास किया, तब राज्यपाल को संविधान की रोशनी में आदिवासी हितों की रक्षा करनी थी। लेकिन राज्यपाल की भूमिका केवल औपचारिक रही। झारखंड में खनन और ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ दर्जनों आंदोलन हो रहे हैं लेकिन राज्यपाल मौन हैं। पेसा कानून राज्य में लागू नहीं है, राज्यपाल बेफिक्र हैं। छत्तीसगढ़ में सलवा जुडूम और नक्सल हिंसा में हजारों निर्दोष आदिवासी मारे गए, गाँव के गाँव जला दिए गए, राज्यपाल के कान पर जूं नहीं रेंग। हँसदेव की जमीन लूट ली गयी, जंगल साफ हो गए, वनाधिकार को ठेंगा दिखाया जाता रहा लेकिन राजपाल ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। राज्य में पेसा कानून का क्रियान्वयन राज्यपाल के संरक्षण में होना था, परंतु ग्राम सभाओं को अधिकार देने की प्रक्रिया लगातार अधूरी पड़ी रही। ढेबर आयोग सहित अनेक आयोगों ने जनजातीय परामर्शदात्री परिषद को निष्क्रिय, कमजोर और अप्रभावी बताया है तथा इसे सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। साथ ही राज्यपालों की भूमिका की भी आलोचना हुई है कि वे संवैधानिक जिम्मेदारी के बावजूद प्रशासन की वास्तविक चुनौतियों पर पर्याप्त रिपोर्टिंग नहीं करते। 2015 में केरल ने पांच जिलों में 2,133 बस्तियों, पांच ग्राम पंचायतों और दो वार्डों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव पारित किया था और इसे अब भी केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के मंजूरी का इंतजार है। छठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के राज्यों— असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा के लिए एक विशेष व्यवस्था करती है। इसमें स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की गई है, जिनके पास भूमि, संस्कृति, न्याय, वन, संसाधन और शिक्षा से जुड़े व्यापक अधिकार निहित हैं। लेकिन इन परिषदों के निर्णयों के निरीक्षण और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी अंततः राज्यपाल पर डाल दी गई है। राज्यपाल यहां भी अंतिम निर्णायक बनते हैं कि कोई प्रस्ताव लागू होगा या नहीं। पूर्वोत्तर में जातीय संघर्ष और संसाधनों पर विवाद स्थायी समस्या बना हुआ है। छठी अनुसूची की परिषदों में बार-बार विवाद हुए, लेकिन गवर्नरों ने निर्णायक और संरक्षक की भूमिका शायद ही निभाई। व्यवहार में देखा गया है कि राज्यपाल अक्सर इन परिषदों को न तो पर्याप्त अधिकारों के साथ कार्य करने देते हैं और न ही रिपोर्टिंग व निष्पक्ष निरीक्षण की अपनी भूमिका गंभीरता से निभाते हैं। परिणामस्वरूप, आदिवासी समाजों की वास्तविक आकांक्षाएं शासन व्यवस्था में पूर्णतः परिलक्षित नहीं हो पातीं।

सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 (जो कोर्ट को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति देता है) का उपयोग करते हुए निम्नलिखित समय-सीमाएँ तय कीं है। राज्यपाल को बिल पर सहमति देना या असहमति जताना है तो यह 1 महीने के अंदर करना होगा। अगर बिल मनी बिल (वित्तीय विधेयक) नहीं है, तो उसे वापस करने के लिए 3 महीने का समय है। अगर बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा गया है, तो उस पर फैसला 3 महीने के अंदर होना चाहिए। अगर विधानमंडल ने बिल को दोबारा पारित करके राज्यपाल के पास भेजा है, तो राज्यपाल को 1 महीने के अंदर सहमति देनी होगी। अगर कोई देरी होती है, तो राज्यपाल को लिखित में कारण बताना होगा और इसे राज्य सरकार को सूचित करना होगा। संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को बिल पर सहमति देने, सहमति रोकने, बिल को (मनी बिल को छोड़कर) वापस भेजने और बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने का विकल्प देता है।अनुच्छेद 201 उन बिल्स से संबंधित है जो राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजे जाते हैं। पहले इसमें कोई समय-सीमा नहीं थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने समय-सीमा तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से काफी पहले सरकारिया आयोग (1988) और पुंछी आयोग (2007) ने सुझाव दिया था कि राज्यपालों को बिल्स पर फैसला करने के लिए समय-सीमा तय की जानी चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ली जानी चाहिए। राज्यपाल की जबावदेही तय करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी हस्तक्षेप किया है। शमशेर सिंह (1974) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना चाहिए।

- सुधीर पाल

मृत्यु भोज देना या उसमें भाग लेना दंडनीय अपराध है -जाना पड़ सकता है जेल

वैश्विक स्तरपर दुनियां में भारत ही एक ऐसा देश है जहां हजारों समाज, लाखों जातियां, उपजातियां धर्म व आध्यात्मिक आस्था की जड़ कहा जाता रहा है, जिसकी गिनती विदेशो में भारतीय खूबसूरती की विशेषताओं में से एक है। कई सैलानी इस अनोखी व्यवस्था को देखनें ही भारत यात्रा पर आते हैं और कहते हैं काबिल-ए-तारीफ़! इसी कारण ही भारत धर्मनिरपेक्ष देश की ताक़त से प्रसिद्ध है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र, मानता हूं के भारतीय रीति रिवाज को हर समाज स्तर पर अलग अलग रूप से लागू किया जाता रहा है,परंतु बहुत सी ऋतियां और रिवाज ऐसे हैं जो करीब करीब हर समाज जाति में कॉमन है, उन्हें में से एक है, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उस परिवार में 13 दिवसीय शोक मनाया जाता है तथा अंतिम दिन को, 13 वीं या 12 वीं दिन के रूप में अंतिम दिन मृत्यु भोज दिया जाता है, जिसे समाज स्तर व पारिवारिक व रिश्तेदारों के लोग शामिल होते हैं। परंतु समय के बदलते परिपेक्ष में आजकल समय अभाव के कारण समाज में अपने-अपने समय अनुसार मृत्यु भोज दिया जाता है, तो अनेक समाजों में यह मृत्यु भोज केवल पारिवारिक व रिश्तेदारी तक सीमित कर दिया गया है, जो कि इस प्रकार के नियम समझो कि पंचायत द्वारा ही बनाए गए हैं, जो मेरा मानना है कि काफी हद तक उचित भी हैं।हमारी राइस सिटी गोंदिया नगरी के कुछ समाजों के प्रबुद्ध नागरिकों से इस मृत्यु भोज के विषय पर मेरी लंबी चर्चा हुई तो, उन्होंने कहा हमारे समाज में मृत्यु भोज प्रतिबंधित है परंतु समाज के लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों तक सीमित रूप से मृत्यु भोज की रस्म करते रहते हैं। यह चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आज 16 अगस्त 2025 को एक महिला ने डिस्पोजल शॉप पर बताया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, वह उसकी 13 वीं में मृत्यु भोज कर रहे हैं। पूरे 13 दिवसीय शोक में एक लाख रुपए से अधिक खर्च आ गया है, व मृत्यु भोज पर भी करीब 40-50 हज़ार रुपए खर्च होगा। उन्होंने कहा कि वह यह मृत्यु भोज नहीं करना चाहती है परंतु कुछ समाज के लोगों ने कहा इससे समाज वाले उंगली उठाएंगे,बदनाम करेंगे, व सामाजिक प्रतिष्ठा कम होगी! इसलिए मैं यह सब कर रही हूं। बस! इसलिए मैंने आज इस विषय पर आर्टिकल लिखने की सोचा और मैंने फिर इस पर रिसर्च शुरू की तो,मुझे राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 मिला, जिसके तहत मृत्यु भोज देना या उसमें भाग लेना दंडनीय अपराध है, जेल जाना पड़ सकता है। उसमें 1 साल की सजा वह 1000 रुपए जुर्माना की सजा है।दुसरा 13 दिसंबर 2023 तारीख़ की राजस्थान पुलिस की एक सोशल मीडिया पर पोस्ट मिली जिसमें लिखा था, मृत्यु भोज करने और उसमें शामिल होना कानूनं दंडनीय अपराध है। मानवीय दृष्टिकोण से भी यह आयोजन अनुचित है, इसलिए आओ मिलकर इस कुरीति को समाज के से दूर करें, इसका विरोध करे।चूंकि राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत मृत्यु भोज कानून दंडनीय अपराध है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे पारिवारिक सदस्य की मृत्यु पर 13 दिवसीय शौक पर मृत्यु भोज को कुरीति/रीति/धार्मिक संस्कार पर बस छिड़ी। राष्ट्रीय स्तरपर इसका समाधान होना जरूरी है। साथियों बात अगर हम मृत्यु भोज की करें तो, हिंदू परिवारों में मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए परिजन अंतिम संस्कार के बाद विधि विधान से तेरह दिन पर तेरहवीं के रूप में मृत्यु भोज रखते हैं, मगर राजस्थान पुलिस का फरमान देख लगता है कि यह लोगों का अधिकार नहीं बल्कि अपराध है। राजस्थान पुलिस ने 13 दिसंबर की सुबह सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया था - मृत्यु भोज करना और उसमें शामिल होना कानूनन दंडनीय है। मानवीय दृष्टिकोण से भी यह आयोजन अनुचित है,तो क्या किसी को भोज दे ही नहीं ?असल में मृत्यु भोज ऐक्ट आज का नहीं है, यह 1960 से है। इसमें साफ लिखा है कि मृत्यु भोज देना या उसमें भाग लेना दंडनीय अपराध है। सजा के रूप में एक साल तक का या एक हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसमें साफ है कि धार्मिक संस्कार के तहत रखे गए भोज में सौ से ज्यादा लोगों की संख्या नहीं होनीचाहिए। एक्ट बने इतने साल बीत गए मगर हकीकत यह है कि लोग इसके बारे में जानते भी नहीं। राजस्थान पुलिस के ट्वीट पर भी कई लोगों की प्रतिक्रिया थी कि क्या ऐसा भी कोईकानून है। ऐसा कहने वाले भी कम नहीं थे कि यह उनका निजी विषय है। एक ने एक्स पर लिखा-ऐसे हिंदू विरोधी क़ानून बंद करें।यह हिंदू धर्म के लिए ठीक नहीं।इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती। हर इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से ही करता है। तो कुछ लोगों ने इसके समर्थन में भी पोस्ट किया। एक ने लिखा-हमारे यूपी में भी ऐसा कानून होना चाहिए! मरने के बाद धर्म संकट में डालकर लूटने वालों की दुकानों पर ताला लगना चाहिए!राजस्थान में कुरीति बन चुकी है मृत्यु भोज ?लोगों के तर्क से बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या शोकाकुल परिजनों को मृत्यु भोज के लिए धर्म संकट में डाला जाता है? राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार ने सबसे पहले पुलिस को ट्रोल करने वालों को जवाब दिया। वह बताते हैं-ट्रोल करने वालों में ज्यादातर लोग प्रदेश के बाहर के हैं। शायद इन्हें नहीं पता होगा कि राजस्थान में नुकता यानी मृत्युभोज कितनी बड़ी कुरीति रही है। राजस्थान में शादियों में ढाई-तीन हजार लोगों को आमंत्रित किया जाता है और मृत्युभोज में भी इतनी ही तादाद में भोज कराने का दबाव रहता है। बेशक खाने के आइटम शादी के मुकाबले थोड़े कम होते हैं। यहां तक कि अगर घर में किसी युवा शख्स की मौत होती है तो भी इतना बड़ा भोज करने का दबाव रहता है। यह आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को भावनात्मक और आर्थिक रूप से बहुत कमजोर कर देता है। कई बार तो कर्ज लेना पड़ जाता है। पुलिस की कानूनी बंदिश यह कहती है कि आप सौ-सवा सौ से ज्यादा लोगों को भोज न दें। साथियों बात अगर हम राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 की मुख्य धाराओं की करें तो, परिभाषा - इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -(ए) मृत्यु भोज का अर्थ है किसी व्यक्ति के निधन के अवसर पर या उसके संबंध में किसी भी अंतराल पर आयोजित या दी जाने वाली दावत और इसमें एक नुक्ता, एक मोसर और एक चहल्लुम शामिल है,और (बी) मृत्यु भोज आयोजित करने या देने में तैयार या बिना तैयार भोजन की वस्तुओं का वितरण शामिल है, लेकिन इसमें धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष संस्कारों के पालन में परिवार के लोगों या पुरोहित वर्ग के व्यक्तियों या फागीरों को खाना खिलाना शामिल नहीं है, जो कि इससे अधिक नहीं है। कुल मिलाकर सौ व्यक्तियों की संख्या।(3) मृत्यु भोज का निषेध- राज्य में कोई भी व्यक्ति मृत्यु भोज आयोजित नहीं करेगा,न देगा,न शामिल होगा, न ही भाग लेगा।(4) धारा 3 के उल्लंघन के लिए सजा- जो कोई भी धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या ऐसे किसी भी उल्लंघन को करने के लिए उकसाता है, उकसाता है या सहायता करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों के साथ।(5) निषेधाज्ञा जारी करने की शक्ति- यदि धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने में सक्षम न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मृत्यु भोज की व्यवस्था की गई है या होने वाली है या दी जाने वाली है तो ऐसी अदालत आयोजन पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकती है या ऐसे मृत्यु भोज देना (6) धारा 5 के तहत निषेधाज्ञा की अवज्ञा के लिए सजा- जो कोई भी, यह जानते हुए कि धारा 5 के तहत एक आदेश जारी किया गया है, ऐसे निषेधाज्ञा की अवज्ञा करेगा, उसे एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, जो एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।इस अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी हस्ताक्षर के किसी भी उल्लंघन पर एक वर्ष या पांच रुपये तक की सजा का प्रावधान किया गया है।1000/ - या दोनों (7) सरंपच आदि जानकारी देने के लिए बाध्य (1) राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम 21) के तहत स्थापित ग्राम पंचायत के सरपंच और प्रत्येक पंच और प्रत्येक पटवारी और लंबरदार धारा 4 या के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम निकटतम मजिस्ट्रेट को तुरंत सूचित करने के लिए बाध्य होंगे। धारा 6 कोई भी जानकारी जो उसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर ऐसे अपराध को करने या करने के इरादे के संबंध में उसके पास हो।(2) ऐसे किसी भी सरपंच, पंच, पटवारी या लंबरदार को उप-धारा (1) के तहत आवश्यक जानकारी देने में विफल रहने पर तीन महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।यह धारा सरपंच और प्रत्येक पंच या ग्राम पंचायत, पटवारी और लंबरदार के लिए धारा 6 में से 5 के तहत अपराध की जानकारी निकटतम प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को देना अनिवार्य बनाती है, यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे दंडित भी किया जा सकता है और इस धारा के तहत दोषी ठहराए जाने पर 3 महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों।(8) पैसा उधार लेने या उधार देने पर रोक(1) कोई भी व्यक्ति मृत्यु भोज आयोजित करने या देने के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति से धन या सामग्री उधार नहीं लेगा या उधार नहीं देगा।(2)इस जानकारी के साथ या यह विश्वास करने का कारण होने पर कि दिए गए ऋष्ण का उपयोग मृत्यु भोज रखने या देने के उद्देश्य से किया जाएगा, दिए गए ऋष्ण के पुनर्भुगतान के लिए प्रत्येक समझौता शून्य होगा और कानून की अदालत में लागू नहीं किया जाएगा।(9) अपराध का क्षेत्राधिकार और संज्ञान- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, या उस पर मुकदमा नहीं चलाएगी।(10) अभियोजन के लिए परिसीमा- कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान उस तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं लेगी जिस दिन अपराध होने का आरोप लगाया गया है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि मृत्यु भोज देना या उसमें भाग लेना दंडनीय अपराध है!- जाना पड़ सकता है जेल !राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत मृत्यु भोज कानून दंडनीय है।पारिवारिक सदस्य की मृत्यु पर 13 दिवसीय शोक पर मृत्यु भोज को कुरिति/रीति या धार्मिक संस्कार इसपर बहस छिड़ी-राष्ट्रीय स्तरपर इसका समाधान होना ज़रूरी है।

-किशन सनमुखदास भावनानी

चैन से सोना है तो सोने को कहें ना

सोने की चमक सभी को आकर्षित करती है। इसी आकर्षण के कारण लोग अधिक से अधिक सोना खरीदने चाहते हैं। यह चाहत तब और भी बढ़ जाती है जब सोने की कीमत में अचानक थोड़ी गिरावट आती है। लोग इस मौका का लाभ उठाना चाहते हैं। आज कल बाजार में यही स्थिति है क्योंकि सोने की कीमत कमी आयी है। आइए जानें सोने के बारे में हमारे शास्त्रों क्या कहा गया है। ज्यादातर पौराणिक ग्रंथों में इस बात को कई तरह से कहा गया है कि सोने की खरीदारी से जितनी खुशी नहीं होती है उससे अधिक चिंता बढ़ जाती है। हमेशा यह चिंता सताती है कि सोना चोरी न हो जाए। इसे कैसा संभालकर रखें। पड़ोसी की नज़र सोने के गहनों पर नहीं जाए, क्योंकि नज़र लग जाएगी।यह भी कहा जाता है कि किसी अवसर पर सोने के गहने पहन लें तो हमेशा इसी पर ध्यान रहता है कि कहीं गिर न जाए, कोई खींच न ले। इस चिंता के कारण उत्सव का पूरा आनंद भी नहीं उठा पाते हैं। सोना सिर्फ आपको चिंतित ही नहीं करता है बल्कि आपकी सोच और व्यवहार को भी प्रभावित करता है। इससे अभिमान भी जन्म लेता है। यही कारण है कि रहीम ने लिखा है कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय। वा खाये बौराय नर, वा पाये बौराय।। इस दोहे में रहीम ने दो बार कनक शब्द का प्रयोग किया है। एक कनक धतूरे के लिए और दूसरा सोना के लिए। रहीम ने कहा है कि सोने का नशा धतूरे भी ज्यादा होता है। धतूरा खाने के बाद आदमी बौरा जाता है लेकिन सोने का नशा इतना तेज होता है कि इसे प्राप्त कर लेने मात्र से इंसान बौरा जाता है। पुराणों में कथा है कि कलियुग का प्रवेश भी सोने के माध्यम से हुआ था। कलियुग सोने में निवास करता है इसलिए सोने के कारण विवाद और रिश्तों में दूरियां तक आ जाती है। साधु पुरूष कहते हैं कि सोना चिंता का बड़ा कारण है। जब आप इसे पाने की सोचने लगते हैं तभी से चिंता आपके ऊपर हावी होने लगती है।

अधूरे वादे और जनता की मुश्किलें

इंदौर जो अपनी तेज विकास गति के लिए जाना जाता है, आज भी कुछ बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसी ही एक समस्या सिंगापुर टाउनशिप रेलवे क्रॉसिंग पर है, जहां सालों से एक ओवरब्रिज की मांग की जा रही है। यह सिर्फ एक पुल का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह शासन-प्रशासन के अधूरे वादों और जनता की वास्तविक जरूरतों के बीच के अंतर को दर्शाता है। बारिश के मौसम में इस अंडरपास में पानी भर जाता है, जिससे 80 हजार से अधिक निवासियों का जीवन थम सा जाता है। यह एक वार्षिक समस्या है, जिसका हर बार केवल तात्कालिक समाधान किया जाता है। मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री तक ने ओवरब्रिज बनाने की घोषणा की, 41 करोड़ की राशि की बात हुई और रेलवे से भी स्वीकृति मिली, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अब रेलवे ने अंडरपास को ही चौड़ा करने की योजना बनाई है, जो जनता की मांग के विपरीत है। यह कैसा समाधान है? जब जरूरत ओवरब्रिज की है, तो अंडरपास को चौड़ा करने से क्या समस्या का स्थायी हल निकल पाएगा? यह निर्णय यह भी दिखाता है कि प्रशासन अक्सर सबसे आसान रास्ता चुनता है, भले ही वह जनता के लिए दीर्घकालिक समाधान न हो। निवासियों द्वारा लोक निर्माण विभाग के सर्वे पर सवाल उठाना भी जायज है। जब ओवरब्रिज बनाने के लिए खाली जमीन उपलब्ध है, तो सघन क्षेत्र के बीच से प्रस्ताव क्यों लाया गया, जिससे अतिक्रमण और इमारतों को खतरा हो? यह कदम यह दर्शाता है कि प्रशासन जनता की राय को गंभीरता से नहीं लेता है। इंदौर को अगर सच में एक स्मार्ट सिटी बनना है, तो उसे ऐसी सतही सोच से बाहर निकलना होगा।

राजनीति या कुछ और...! एक महीने की जेल तो खत्म सत्ता का खेल... ?

केंद्र की मोदी सरकार देश के राजनेताओं के लिए एक नया संविधान संशोधन विधेयक लाई है, जिसे संसद में भी पेश कर दिया है, जिसके तहत यदि किसी राजनेता की किसी गंभीर मामले में गिरफ्तारी हुई है और वह लगातार एक महीने जेल में रहा है, तो उसके लिए राजनीति के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। यद्यपि यह विधेयक गंभीर है, किंतु इसके दायरे में कौन से गंभीर मामले आ रहे हैं, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, यदि इसमें देश की राष्ट्रीयता या अस्मिता से जुड़ें मामले शामिल हैं, तो आज देश का पूरा सत्तापक्ष सलाखों के पिछे खड़ा दिखाई दे सकता है। क्योंकि आज तो जो राजनेता सत्तासीन है, वह सभी इंदिरा जी के आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा कानून (मीसा) के तहत 19 महीने जेल में रह चुके हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित भाई शाह ने एक सौ तीसवां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 75, 164 तथा 229एए में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र या राज्य के मंत्री गिरफ्तारी के बाद यदि 30 दिन जेल में रहते हैं, तो वे सत्ता के सिंहासन पर बैठने का हक खो देंगे। गवर्नमेंट आफ यूनियन टेरिटरिज (संशोधन) बिल 1963 के एक्ट में बदलाव कर, पीएम, सीम तथा मंत्रियों को ऐसे मामलों में सत्ता से वंचित करने का प्रावधान किया गया है, इसके साथ ही संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधायक भी शामिल है। यह विधेयक संसद संयुक्त संसदीय समिति के पास विचारार्थ भेज सकती है, मौजूदा सत्र एक-दो दिन में ही खत्म होने जा रहा है। वैसे प्रतिपक्ष का इन कानून संशोधन को लेकर विचार है कि यह कानून प्रतिपक्ष को अस्थिर करने का हथियार बन सकता है।

सत्तापक्ष के सीएम व मंत्री को नहीं छुआ जाएगा, ऐसा कानून के वरिष्ठ विद्वान अभिषेक मनुसिंघवी का कहना है, सरकार की दलील है कि मौजूदा कानूनों में इस बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, इसीलिए सरकार यह विधेयक पेश करने जा रही है, इसके सथ ही सरकार की यह दलील भी है कि यह कदम लोकतंत्र को मजबूत करेगा। यद्यपि केंद्र के इस कदम की राजनीतिक क्षेत्रों में सराहना की जा रही है, किंतु यह तथ्य किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है की इस विधेयक में यह प्रावधान क्यों किया गया है कि जेल से रिहाई के बाद संबंधित शख्स फिर पूर्व पदों पर नियुक्त किया जा सकेगा। फिलहाल यह विधेयक संसद में पेश हुआ है, इस पर चर्चा के दौरान जहां इसके लिए सुझाव आएंगे, वहीं इस पर नोंकझोंक भी होगी, फिलहाल स्वयं सरकार का रुख भी इस संशोधन विधेयक को लेकर स्पष्ट नहीं हो पाया है।

-ओमप्रकाश मेहता

आरबीआई अपनाएगा सिद्धांत और परिणाम आधारित नियामकीय ढांचा

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अब पारंपरिक नियम आधारित नियमन के बजाय सिद्धांत और परिणाम आधारित नियामकीय ढांचे की ओर बढ़ रहा है। यह जानकारी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम. राजेश्वर राव ने भारतीय प्रबंध संस्थान, कोझीकोड में एक कार्यक्रम के दौरान दी। डिप्टी गवर्नर ने बताया कि यह नया दृष्टिकोण विनियमित संस्थाओं को अधिक लचीलापन प्रदान करेगा, जिससे वे नियामकीय अपेक्षाओं का पालन करते हुए अपने व्यवसाय मॉडल के अनुसार काम कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि उद्देश्य यह है कि बिना अधिक कठोरता के, वांछित नियामकीय परिणाम हासिल किए जा सकें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी नियामकीय ढांचा पूर्ण नहीं होता, लेकिन सिद्धांत आधारित नियमन विकसित और परिपक्व बाजारों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए नियम आधारित ढांचा भी जरूरी है। डिप्टी गवर्नर ने वित्तीय प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए नवाचार, डेटा और तकनीक के रणनीतिक उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही उन्होंने पर्यवेक्षण की दक्षता बढ़ाने, नियामकीय ढांचे की समय-समय पर समीक्षा करने और नए जोखिमों के प्रति सतर्क रहने की बात भी कही। उनका मानना है कि इन उपायों से न केवल अनुपालन दबाव घटेगा, बल्कि नियमन अधिक प्रभावी और समयानुकूल भी बन पाएगा। नियमन को पहली बार में ही सही बनाना और समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखना आरबीआई की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल होगा।

रियल मनी गेम्स बैन के खिलाफ गेमिंग इंडस्ट्री ने लगाई गुहार

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ऑनलाइन स्किल गेमिंग संगठनों ने एक संयुक्त पत्र लिखकर भारत में सभी प्रकार के ?रियल मनी गेम्स (आरएमजी) पर प्रस्तावित पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ हस्तक्षेप की मांग की है। उद्योग ने चेतावनी दी है कि इस कदम से 400 से अधिक कंपनियां बंद हो सकती हैं और करीब 2 लाख से अधिक नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। द ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (एआईजीएफ), द ई-गेमिंग फेडरेशन (ईजीएफ) और द फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटसी स्पोर्ट्स ने कहा है कि इस तरह का प्रतिबंध उद्योग के लिए 'सफाए की घंटी साबित होगा। उन्होंने गृह मंत्री से इस मसले पर बैठक का भी अनुरोध किया है। इन संगठनों का मानना है कि यदि वैध कंपनियां बंद होती हैं तो अवैध विदेशी जुआ संचालक और मटका नेटवर्क जैसे असुरक्षित और गैरकानूनी मंचों को बढ़ावा मिलेगा। इससे लाखों भारतीय उपयोगकर्ता असुरक्षित प्लेटफॉर्म की ओर मुड़ सकते हैं। भारत में वर्तमान में लगभग 50 करोड़ गेमर्स हैं और यह क्षेत्र 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित कर चुका है। इस उद्योग की प्रमुख कंपनियों में ड्रीम11, जंगली गेम्स, मोबाइल प्रीमियर लीग, हेड डिजिटल वर्क्स और नजारा टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। सरकार ने हाल ही में एक मसौदा विधेयक तैयार किया है, जिसमें सभी ऑनलाइन मनी गेम्स से संबंधित लेनदेन को बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है। उद्योग का कहना है कि इससे राज्य और केंद्र दोनों के कर राजस्व में कमी आएगी और डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रधानमंत्री मोदी के 1 लाख करोड़ डॉलर के लक्ष्य को भी ठेस पहुंचेगी। ऑनलाइन स्किल गेमिंग संगठनों का आग्रह है कि सरकार इस क्षेत्र को प्रतिबंधित करने के बजाय इसके नियमन और सुधार की दिशा में कदम उठाए।

कृषि व ग्रामीण श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 0.77 एवं 1.01 फीसदी हुई

नई दिल्ली। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2025 में कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति दर में गिरावट दर्ज की गई। कृषि श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई दर घटकर 0.77 प्रतिशत रही, जबकि जून में यह 1.42 प्रतिशत थी। इसी प्रकार ग्रामीण श्रमिकों के लिए यह दर जुलाई में 1.01 प्रतिशत रही, जो जून में 1.73 फीसदी थी। मंत्रालय के मुताबिक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) जुलाई में 1.23 अंकों की वृद्धि के साथ 135.31 पर पहुंच गया। वहीं ग्रामीण श्रमिकों का सीपीआई 1.30 अंक बढ़कर 135.66 हो गया। खाद्य सूचकांक की बात करें तो, इसमें भी वृद्धि दर्ज की गई। कृषि श्रमिकों के लिए 1.94 अंक और ग्रामीण श्रमिकों के लिए 2.16 अंक की बढ़ोतरी हुई। हालांकि सूचकांक में बढ़ोतरी हुई, लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट देखने को मिली। जुलाई 2025 में कृषि श्रमिकों के लिए यह दर (-)1.56 प्रतिशत और ग्रामीण श्रमिकों के लिए (-)1.13 प्रतिशत रही, यानी खाद्य वस्तुओं के दामों में औसतन गिरावट आई। इन सूचकांकों को आधार वर्ष 2019=100 के अनुसार तैयार किया गया है और यह आंकड़े देश के 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 787 गांवों से जुटाए गए हैं। गिरती मुद्रास्फीति दर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए राहत का संकेत मानी जा रही है।

सरकारी रिफाइनरियों ने बढ़ी छूट के चलते रूस से कच्चा तेल खरीदना शुरू किया

नई दिल्ली। सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनियों ने रूस से कच्चे तेल की खरीद फिर से शुरू कर दी है। भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल ने सितंबर और अक्टूबर डिलीवरी के लिए रूसी कच्चे तेल की खरीद में तेजी लाई है। पिछले कुछ महीनों में रूस के तेल पर मिलने वाली छूट कम होने के कारण घरेलू कंपनियों ने खरीद पर ब्रेक लगा दिया था। हालांकि, अब छूट बढ़कर लगभग तीन डॉलर प्रति बैरल हो गई है, जिससे रूस से तेल खरीदना फिर से आकर्षक हो गया है। रूसी तेल की खरीद पर भारत की रिफाइनरियों द्वारा फिर से जोर देने से चीन के लिए रूस से तेल की आपूर्ति कम होने की संभावना है। जब भारत ने रूस से तेल खरीदना कम किया था, तब चीन ने अपनी खरीद बढ़ा दी थी। भारत ने मुख्य रूप से यूराल्स क्रूड के अलावा वरंडे और साइबेरियन लाइट जैसे अन्य रूसी तेल ग्रेड भी खरीदे हैं। हालांकि, जुलाई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 27 अगस्त से भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी और अमेरिका की आलोचना के चलते भारत ने रूस से तेल की खरीद रोक दी थी।

आज का राशिफल

मेष- आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आप कुछ नया करने की सोचेंगे, लेकिन आपको कामों में कुछ उलझनें आएंगी, जिससे आपको टेंशन भी रहेगी। आपको कामों समस्याएं भी हो सकती हैं। आप अपने धन से संबंधित मामलों को मिल बैठकर निपटाने की कोशिश करें और यदि आपको कोई जिम्मेदारी मिले, तो आप उसको किसी दूसरे पर ना डालें। परिवार में किसी सदस्य की सेहत में गिरावट आने से भागदौड़ अधिक रहेगी।

वृषभ- आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आपके सुख-सुविधाएं बढ़ने से खुशी होगी। घूमने-फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। लेनदेन से संबंधित मामलों को आप मिल बैठकर निपटाने की कोशिश करें, जो विद्यार्थी अपने विषयों में कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए आप किसी सीनियर से सलाह मशवरा आवश्यक करें। आप किसी निर्णय को जल्दबाजी में ले सकते हैं, जो बाद में आपकी टेंशनों को बढ़ा सकता है।

मिथुन- आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। छोटे बच्चों के साथ आप कुछ समय मौज-मस्ती करेंगे, उनके लिए आप कुछ खाने पीने की चीज आदि भी लेकर आ सकते हैं। यदि आपकी कोई प्रिय वस्तु खो गई थी, तो उसके भी आपको मिलने की पूरी संभावना है। वाहनों का प्रयोग आप थोड़ा सा संभलकर करें, क्योंकि कोई दुर्घटना होने की संभावना बनती दिख रही है।

कर्क- आज का दिन आपके लिए मौज-मस्ती से भरा रहने वाला है। आपका कोई कानूनी मामला आपको टेंशन देगा। कार्यक्षेत्र में कोई आपको धोखा देने की कोशिश करेगा, जिसके लिए आपको अपनी आंख और कान खुले रखने होंगे। आप अपनी इनकम को बढ़ाने का सोर्सो पर भी पूरा ध्यान देंगे। परिवार में किसी वाद-विवाद को आप मिल बैठकर दूर करने की कोशिश करें, नहीं तो बाहरी व्यक्ति इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा।

सिंह- आज आपको अपने बढ़ते खर्चो को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ससुराल पक्ष से आपको मान-सम्मान मिलेगा। आप अपने घर के रिनोवेशन का काम शुरू कर सकते हैं। आपकी कोई आदत परिवार के सदस्यों के लिए सिरदर्द बन सकती है। आप अपने कामों को लेकर मिल बैठकर चले। जीवनसाथी से आपके रिश्ते पहले से बेहतर रहेंगे। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें अपनी मेहनत जारी रखनी होगी।

कन्या- आज का दिन आपके लिए सेहत पर ध्यान देने के लिए रहेगा। तकनीकी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को अच्छी सफलता मिलेगी। आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर रहेगी। आपकी कला कौशल में निखार आएगा, जिससे आप कुछ बड़े-बड़े निर्णय आसानी से ले सकेंगे। आप किसी के बहकावे में आकर कोई काम ना करें। परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा को लेकर आपको टेंशन बनी रहेगी। आप किसी को धन उधार देने से बचें।

तुला- आज का दिन आपके लिए सफलता दिलाने वाला रहेगा। आप किसी बात को लेकर वाद विवाद में ना पड़ें। आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने की प्लानिंग कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी को लेकर मुद्दा आपको समस्या देगा, इसलिए आप किसी ऐसे काम में आगे ना बढ़ें। आपको परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर पूरा ध्यान देना होगा, इसलिए आप उनको समय दें और काम के साथ-साथ आराम के लिए भी समय निकाले।

वृश्चिक- आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपके गृहस्थ जीवन में यदि कुछ समस्या चल रही थी, तो वह भी दूर होगी। परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आप अपनी जरूरत की आवश्यकताओं को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। आपकी कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी थी, तो उसके लिए पूरा होने की संभावना है।

धनु- आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को साथी के मन में चल रही उलझनों को जानने की कोशिश करनी होगी। आप किसी परिवार के सदस्य पर कोई फैसला ना डालें और उन्हें काम को लेकर सलाह अवश्य दें। संतान को तरक्की करते देखा आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। घूमने-फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।

मकर- आज का दिन आपके लिए सेहत के मामले में एहतियात बरतने के लिए रहेगा। आपके कुछ गुप्त शत्रु आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। बिजनेस में आप किसी अजनबी से कोई लेन-देन ना करें। नौकरी में कार्यरत लोगों के बॉस उनके कामों पर नजर रखेंगे, इसलिए आपके आपको अपने कामों पर ध्यान देना होगा। यदि आप धन को लेकर परेशान चल रहे थे, तो आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।

कुंभ- आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। परिवार में खुशियां भरपूर रहेगी। भगवान जी की भक्ति में आपका खूब मन लगेगा। आप किसी की कहीसुनी बातों पर भरोसा ना करें, नहीं तो इससे आपके बेवजह के दोस्तों में कड़वाहट होने की संभावना है। माता जी आपको कोई जिम्मेदारी दे, तो उसे लेकर ढील बिल्कुल ना दें। आप अपने आलस्य को त्यागकर काम में जुट सकते हैं।

मीन- आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। यदि आपका धन डूबा हुआ था, तो वह आपको वापस मिल सकता है। आपके बिजनेस में चार चांद लगेंगे। आपको कुछ अपरिचित लोगों से भी मदद मिलने की संभावना है। आप अपने मन में कुछ नया करने की ठान सकते हैं। सिंगल लोग यदि किसी से प्रेम करते हैं, तो उनसे अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं।

शब्दजाल - 7997

शब्दजाल में 10 शहरों के नाम ढूंढिए. शब्द ऊपर से नीचे एवं तिरछे हो सकते हैं.

म	अ	मु	न	सी	जा	म	न	ग	र	व
रा	वि	ली	प्रे	क	ना	स	द	ज	कां	ड
सू	र	त	बा	दी	छ	सि	आ	ब	वृ	ज
ई	नौ	ब	न	बा	वा	स	क	ल	ष	ल
वा	अ	मी	ल	ज	चा	न	क्रो	न	भ	गां
रा	ल	न	र	य	ब	ली	ती	बैं	घ	व
न	सिं	र्नि	ग	पु	न	ल	स	ग	व	स
सी	ह	ऊ	ई	र	ब	क	पु	लो	श	क
रा	म	तु	ला	रा	म	स	या	र	र	आ
क	गॉ	सो	नी	प	त	कुं	भ	म	प	द
क	ड	क	र्क	या	क	र्त	शि	म	ला	म

जयपुर, जामनगर, बेंगलोर, सोनीपत, जलगांव, नासिक, वाराणसी, सूरत, जबलपुर, शिमला

शब्दजाल - 7996 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

दैनिक पंचांग

22 अगस्त 2025 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

ग्रह स्थिति		लग्नारंभ समय	
सूर्य	सिंह में	सिंह	05.16 बजे से
चंद्र	कर्क में	कन्या	07.32 बजे से
मंगल	कन्या में	तुला	09.43 बजे से
बुध	कर्क में	वृश्चिक	11.58 ब.से
गुरु	मिथुन में	धनु	14.14 बजे से
शुक्र	कर्क में	मकर	16.19 बजे से
शनि	मीन में	कुंभ	18.05 बजे से
राहु	कुंभ में	मीन	19.38 बजे से
केतु	सिंह में	मेष	21.09 बजे से
राहुकाल		वृष	22.49 बजे से
10.30 से		मिथुन	00.47 बजे से
12.00 बजे तक		कर्क	03.00 बजे से

शुक्रवार 2025 वर्ष का 234 वा दिन **दिशाशूल** पश्चिम **ऋतु** वर्षा। **विक्रम संवत्** 2082 **शक संवत्** 1947 **मास** भाद्रपद (दक्षिण भारत में श्रावण) **पक्ष** कृष्ण **तिथि** चतुर्दशी 11.57 बजे को समाप्त। **नक्षत्र** आश्लेषा 00.17 बजे को रात्र समाप्त। **योग** वरीयान 14.35 बजे को समाप्त। **करण** शकुनि 11.57 बजे तदनन्तर चतुष्पद 23.43 बजे को समाप्त। **चन्द्रायु** 24.2 घण्टे **रवि क्रान्ति** उत्तर 11° 46' **सूर्य** दक्षिणायन **कलि अहर्गण** 1872444 **जूलियन दिन** 2460909.5 **कलियुग संवत्** 5126 **कल्पारंभ संवत्** 1972949123 **सृष्टि ग्रहारंभ संवत्** 1955885123 **वीरनिर्वाण संवत्** 2551 **हिजरी सन्** 1446 **महीना** सफर **तारीख** 27 **विशेष** पिठोरी अमावस्या, दर्श अमावस्या।

दिन का चौघड़िया			रात का चौघड़िया		
चर	05.55 से	07.23 बजे तक	रोग	05.38 से	07.1 बजे तक
लाभ	07.23 से	08.51 बजे तक	काल	07.11 से	08.43 बजे तक
अमृत	08.51 से	10.19 बजे तक	लाभ	08.43 से	10.15 बजे तक
काल	10.19 से	11.47 बजे तक	उद्वेग	10.15 से	11.47 बजे तक
शुभ	11.47 से	01.15 बजे तक	शुभ	11.47 से	01.19 बजे तक
रोग	01.15 से	02.43 बजे तक	अमृत	01.19 से	02.51 बजे तक
उद्वेग	02.43 से	04.10 बजे तक	चर	02.51 से	04.23 बजे तक
चर	04.10 से	05.38 बजे तक	रोग	04.23 से	05.55 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अत: आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। Jagrutidaur.com, Bangalore

प्रसंगत: धैर्य का पाठ

वासुदेव, बलदेव और सात्यकि अपने-अपने घोड़ों पर चढ़ कर वन विहार के लिए निकले। चलते हुए वे रास्ते से भटक गए और एक सघन वन में जा फंसे। उन्होंने वहीं किसी पेड़ के नीचे रात बिताने का निश्चय किया। तय हुआ कि तीनों बारी-बारी से पहरा देंगे ताकि सुरक्षा होती रहे और दो साथी सोते रह सकें। पहली बारी सात्यकि की थी। वे जागे बाकी दोनों सो गए। इतने में पेड़ पर से एक पिशाच उतरा और उन्हें मल्ल युद्ध के लिए ललकारने लगा। सात्यकि ने उसके कटु वचनों का वैसा ही उत्तर दिया और घूसों का जवाब लात से देते रहे। बड़ी देर तक मल्ल युद्ध होता रहा। सात्यकि को कई चोटें लगीं पर उन्होंने उस समय अपने साथियों से उस प्रसंग की चर्चा न कर, सो जाना ही उचित समझा। फिर बलदेव की बारी आई। पिशाच ने उन्हें भी चुनौती दी, जवाब में उसे वैसे ही गर्मागर्म उत्तर मिले। प्रेत का आकार और बल पहले की तरह ही बढ़ता रहा और बलदेव की बुरी दुर्गति हुई। लेकिन उस समय वह भी चुप रहे। अंत में वासुदेव की बारी आई। उन्हें भी चुनौती मिली। वह हंसते हुए लड़ने लगे और बीच-बीच में कहते रहे, 'बड़े मजेदार आदमी हो तुम। नींद और आलस्य से बचने के लिए मित्र जैसा उपहास कर रहे हो।' धीरे-धीरे पिशाच का बल घटता गया और आकार भी छोटा होने लगा। अंत में वह झींगुर जैसा छोटा रह गया। तब वासुदेव ने उसे कपड़े में बांध लिया। प्रातः नित्यकर्म से निपट कर जब चलने की तैयारी होने लगी तो सात्यकि और बलदेव ने पिशाच से मल्लयुद्ध होने की घटना सुनाई और चोटों के निशान भी दिखाए। आश्चर्यचकित साथियों को देख कर वासुदेव ने बताया, 'वह पिशाच और कोई नहीं, हमारा क्रोध ही था जो वैसा ही प्रत्युत्तर पाने पर बढ़ता है और दोगुना होता जाता है। लेकिन जब उसकी उपेक्षा की जाती है, तो वह दुर्बल और छोटा हो जाता है।'

फिल्म वर्ग पहेली- 6941

बायें से दायें:-

१. मनोजकुमार, हेमा की 'बाली उमरिया भजन करू कैसे' गीत वाली फिल्म-३
३. 'दिल तुझपे फिदा' गीत वाली सैफअली खान, काजोल की फिल्म-३
५. संजयदत्त, शरदकपूर, मनीषा, रवीना की 'ओ गोरी तू चली कहां' गीत वाली फिल्म-२
७. 'लकड़ी की काठी' गीत वाली नसीरूद्दीनशाह, शबाना की फिल्म-३
९. जीतेंद्र, परवीन बाबी की रविकांत निर्देशित एक एक्शन फिल्म-२
११. 'दीवाना तो कह दिया' गीत वाली विकास भल्ला, सुमीत सहगल, नीलम की फिल्म-२
१३. अजय देवगन, जूही चावला की 'लाल लाल होठों पें' गीत वाली फिल्म-४
१५. बोनीकपूर की फिल्म 'रूप की रानी चोरों का राजा' की नायिका थी-३
१६. अमिताभ, वहीदा, जीनत, परवीन की 'हर गोरी रानी यहां' गीत वाली फिल्म-३
१९. 'बाबूजी जरा धीरे' गीत वाली विवेक ओबेराय, दीया मिर्जा की फिल्म-२
२१. अनिल कपूर, माधुरी की 'तू अपने दिल पे मेरा' गीत वाली फिल्म-४
२३. फिल्म 'कोशिश' में संजीवकुमार के साथ नायिका कौन थी-२
२४. फिल्म 'दिलजला' में जैकी श्रॉफ के साथ नायिका कौन थी-३
२५. 'क्या यही प्यार है' गीत वाली संजयदत्त, टीना मुनीम की फिल्म-२
२६. धर्मेन्द्र, हेमा मालिनी की 'जलता है बदन' गीत वाली फिल्म-३,३
२९. फिल्म 'जीवन मृत्यु' में धर्मेन्द्र के साथ नायिका कौन थी-२
३०. फिल्म 'पहला पहला प्यार' में ऋषिकपूर, के साथ नायिका थी-२

ऊपर से नीचे:-

१. जैकीश्रॉफ, रवीना टंडन की फिल्म-२
२. 'तू प्यार का सागर है' गीत वाली फिल्म-२
३. 'कागज कलम दवात ला' गीत वाली अमिताभ, गोविंदा, रजनीकांत की फिल्म-२
४. जीतेंद्र, रामेश्वरी, सारिका की फिल्म-३
६. 'हम तो तेरे आशिक हैं' गीत वाली फिल्म-२
८. मिथुन, आयशा जुल्फा की 'थोड़ा इंतजार का मजा' गीत वाली फिल्म-३
१०. 'ये हसीं वादियां' गीत वाली फिल्म-२
११. राजेश खन्ना, टीना मुनीम की 'जिंदगी प्यार का गीत है, गीत वाली फिल्म-३
१२. 'तिरछी टोपी वाले' गीत वाली फिल्म-३
१३. सुमीत सहगल, शिखा स्वरूप की 'पीछे पीछे आजा मेरी' गीत वाली फिल्म-४
१४. 'गर तुम भुला न दोगे' गीत वाली धर्मेन्द्र शर्मिला टैगोर की फिल्म-३
१६. 'हवा में क्या है' गीत वाली फिल्म-३
१७. 'परदेसी तो हैं परदेसी' गीत वाली जीतेंद्र, रणधीर, राकेश रोशन, रेखा की फिल्म-३
२०. देव आनंद, माला सिन्हा की 'कोई सोने के दिलवाला' गीत वाली फिल्म-२
२१. 'हमारी ही मुट्ठी में' गीत वाली नाना पाटेकर, डिम्पल कपाड़िया की फिल्म-३
२२. अमिताभ, परवीन, आशापारेख कीफिल्म-३
२३. 'क्या मोहब्बत है' गीत वाली फिल्म-४
२४. शशिकपूर, शबाना आजमी की फिल्म-३
२७. 'मेरे ख्वाबों का' गीत वाली जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु की फिल्म-२
२८. लक्की अली, गौरी कार्णिक की 'खोया है तूने जो' गीत वाली फिल्म-२

फिल्म वर्ग पहेली- 6940

खा	मो	शी		आ	प	की	क	स	म
की		शा	दी		डो		भी		स्त
	आ		वा	प	स		ना		
प	ह	चा	न		न	या	क	द	म
रा			गी	ता			भी		ड
या	रा	ना		ज	मा	ना		स	र
ध		य	ति	म			रा	नी	
न	म	क		ह	म	रा	ज		फ
	र्या			ल		जे			रा
अ	दा	ल	त		इं	द्र	कु	मा	र

Jagrutidaur.com, Bangalore

सूडोकु नवताल- 7250

★☆☆☆☆ सरल

3				8				9
		8	6		9	5		
6	5			4			7	1
	4						2	
1	2			6			9	8
		6	4		5	8		
9				1				7

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7249 का हल

8	2	4	3	9	7	5	1	6
3	5	6	1	4	2	7	8	9
1	9	7	6	5	8	2	3	4
9	6	2	5	8	3	1	4	7
5	3	1	4	7	9	8	6	2
4	7	8	2	1	6	9	5	3
2	8	3	9	6	1	4	7	5
6	1	5	7	2	4	3	9	8
7	4	9	8	3	5	6	2	1

शब्द पहेली - 8465

बाएँ से दाएँ

1. रुद्र, शिव, भैरव-4
4. आर्युवेद के जनक-3
6. भीगा हुआ-2
7. ताला(अंग्रेजी-2)
9. शेविंग करना -4
11. योग्य, अनुरूप-3
12. अल्सर-3
13. ज्वालामुखी से निकला गर्म द्रव-2
14. नमाज पढ़ने से पहले हाथ- पांव धोना-2
15. नाप जोख करना-3
17. अनुमान लगाना-3
19. उदारता, बड़प्पन-4
21. गाथा, कहानी -2
23. जनकपुत्री-2
24. जिज्ञासा, उत्साह-3
25. राजा, सम्राट- 4

ऊपर से नीचे

1. इच्छुक, अलमस्त-4
2. मात, पराजय-2
3. बोलने का तरीका-3
4. अचंभित-3
5. आर्ट, हुनर-2
8. गुनाह, अपराध-3
9. अटक-अटक कर बोलना-4
10. सरुर, खुमार, नशा, घमंड-2
12. नजाकत-4
15. अभिनेता, कप्तान-3
16. आनंद बोधक शब्द-2
18. सम्राट, राजा-4
19. व्यंग, परिहास-3
20. मुलायम-3
22. परात, बड़ी थाली-2
23. हलवा, एक मिष्ठान्न-2

शब्द पहेली -8464 का हल

	स	ला	म	त		ल	ल	क
दा	दा		न	म	न			ल
म	चा	न		स	र	फ	रो	श
	र	का	बी		क			या
आ		रा	ज		म	न		त्रा
ल			डा		य	म	ज	
म	नो	मि	ल	न		न	ल	का
गी			ना	र	द		च	र
र	बा	ना		क	र	ता	र	

Jagrutidaur.com, Bangalore

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

मुंबई। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को तेजी के साथ बंद हुआ। बाजार में ये बढ़त दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीदारी हावी रहने से आई है। इस कारण दिन के अंत में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 142.87 अंक बढ़कर 82,000.71 और 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 33.20 अंक उछलकर 25,083.75 पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान फार्मा शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त रही। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में 0.95 फीसदी की बढ़त देखी गई। वहीं वित्तीय सेवा, आईटी, संपत्ति, निजी बैंक और इन्फ्रा शेयर उछाल के साथ बंद हुए। वहीं ऑटो, पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, मेटल, एनर्जी और कमोडिटीज में गिरावट रही। लार्जकैप के विपरीत मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में बिकवाली दर्ज की गयी। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 221.55 अंक या 0.38 फीसदी की गिरावट के साथ 57,708.95 और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 2.05 अंक की मामूली गिरावट के साथ 17,966.35 पर था। सेंसेक्स पैक में बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, एलएंडटी, बीईएल, टाइटन, मारुति सुजुकी, सन फार्मा, भारती एयरटेल, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और एशियन पेंट्स शेयर सबसे अधिक लाभ में थे। पावर ग्रिड, इटरनल (जोमैटो), एचयूएल, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, एमएंडएम, एसबीआई, टाटा स्टील, एचसीएल टेक, एक्सिस बैंक और टेक महिंद्रा के शेयर गिरे। वहीं व्यापक बाजार का रुख मिला जुला था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर 2,094 शेयर हरे निशान में और 2,000 शेयर लाल निशान में और 154 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए। वहीं गत दिवस भी बाजार तेजी के साथ बंद हुआ था। वहीं इससे पहले आज सुबह शेयर बाजारों की शुरुआत मजबूती के साथ हुई। सेंसेक्स 362.62 अंक चढ़कर 82,220.46 पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी-50 91.45 अंकों की बढ़त के साथ 25,142 पर कारोबार कर रहा था। निवेशकों की नजर आज जारी होने वाले भारत के विनिर्माण और सेवा पीएमआईफ्लैश आंकड़ों पर टिकी है, जो देश की आर्थिक गति का संकेत देंगे। इसके अलावा जीएसटी प्रणाली में सुधार, रूस-यूक्रेन शांति वार्ता में प्रगति और भारत-चीन संबंधों में नरमी जैसे घटनाक्रमों ने भी बाजार की धारणा को मजबूत किया है। वहीं वैश्विक स्तर पर एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख देखने को मिला। जापान का निक्केई 225 0.3 फीसदी गिरा, हांगकांग का हैंग सेंग 0.07 फीसदी नीचे रहा, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग 1 फीसदी ऊपर था। अमेरिका में टेक शेयरों में बिकवाली के चलते एसएंडपपी 500 और नेस्डैक में गिरावट रही, जबकि डाऊ जोंस लगभग स्थिर रहा।

स्टारलिंक भारत में ग्राहकों के लिए आधार प्रमाणीकरण का करेगा इस्तेमाल

नई दिल्ली। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भारत में अपने उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब भारत में स्टारलिंक अपने ग्राहकों को जोड़ने से पहले उनके पहचान सत्यापन के लिए आधार' प्रमाणीकरण का उपयोग करेगी। इस संबंध में हाल ही में एक आधिकारिक बयान जारी किया गया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत, स्टारलिंक भारत में अपने ग्राहकों को जोड़ने के लिए आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया अपनाएगा। इससे ग्राहक सत्यापन की प्रक्रिया न केवल सुरक्षित होगी, बल्कि यह काफी सुगम और तेज भी हो जाएगी। आधार का उपयोग करने से कंपनी को ग्राहकों की असली पहचान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, जिससे धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। भारत में स्टारलिंक की उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा को पहले ही लाइसेंस मिल चुका है। कंपनी ने भारती एयरटेल और रिलायंस जियो जैसी बड़ी टेलिकॉम कंपनियों के साथ भी अपने नेटवर्क विस्तार के लिए करार किए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, स्टारलिंक भारत में लगभग 20 लाख से अधिक ग्राहकों को अपनी सेवा से जोड़ने की क्षमता रखती है।

कश्मीरी अर्थव्यवस्था में जान फूंकेगी दिल्ली-बड़गाम मालगाड़ी सेवा...सेब से केसर तक पहुंचेगा देश के हर कोने

नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर में वंदे भारत जैसी यात्री ट्रेनों ने जहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया है, वहीं दिल्ली-बड़गाम मालगाड़ी सेवा किसानों, कारीगरों और व्यापारियों के लिए वरदान साबित होगी। यह सेवा परिवहन की गति और लागत में सुधार करके कश्मीर के विशिष्ट उत्पादों को सीधे राष्ट्रीय बाज़ार से जोड़ेगी। इसके तहत सेब, केसर, अखरोट, पश्मीना शॉल और कालीन जैसे कश्मीरी उत्पाद अब कम समय में और कम लागत पर दिल्ली और देश के अन्य बड़े शहरों तक पहुँच सकते है। इससे परिवहन में लगने वाला समय कम होगा और उत्पादों की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। इतना ही नहीं परिवहन लागत में कमी से किसानों और व्यापारियों का मुनाफा बढ़ेगा। साथ ही, बेहतर लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग की ज़रूरत से नए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। यह सेवा कश्मीर के प्रसिद्ध हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को एक मजबूत पहचान दिलाएगी, जिससे उनकी पहुँच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में और भी बढ़ेगी। बता दें कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर्यटन, कृषि और हस्तशिल्प पर आधारित है। यदि इन तीनों को सशक्त परिवहन व्यवस्था का सहारा मिले, तो घाटी न केवल आत्मनिर्भर बनेगी बल्कि देश की आर्थिक धारा में और अधिक मजबूती से शामिल होगी। देखा जाए तो यह मालगाड़ी सेवा कश्मीर के लिए केवल रेल की पटरियों पर दौड़ती गाड़ी नहीं, बल्कि आर्थिक पुनरुत्थान और स्थायी विकास की रफ़्तार है। बहरहाल, दिल्लीङ्कबडगाम मालगाड़ी सेवा न सिर्फ़ कश्मीर को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी, बल्कि उसे राष्ट्रीय और वैश्विक बाज़ार से जोड़ने का भी काम करेगी। यह कदम कश्मीर के लिए वही साबित हो सकता है जो फूलों के लिए नीदरलैंड की हवाई परिवहन व्यवस्था रही है तेज, भरोसेमंद और लाभकारी होगी।

लांजी की बेटियों ने नीट 2025 में लहराया परचम

साकेत पब्लिक स्कूल की भूमि, सृष्टि, चारू, अमुल्या, दीक्षा का MBBS के लिए चयन

लांजी (पद्मेश न्यूज)। लांजी क्षेत्र ने एक बार फिर अपनी शैक्षणिक प्रतिभा का डंका बजाया है। क्षेत्र के साकेत पब्लिक स्कूल की पांच मेधावी छात्राओं ने नीट 2025 (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS के लिए चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इन छात्राओं की सफलता ने न केवल उनके परिवार और स्कूल, बल्कि पूरे लांजी क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। नीट 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली साकेत पब्लिक स्कूल की पांच छात्राओं में शामिल हैं- कु. भूमि भागवत सुलाखे - अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा। कु. सृष्टि दिलीप वासनिक - नेताजी सुभाष चन्द्र बोस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर। कु. चारू ज्ञानीराम फरदे - शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छिंदवाड़ा। कु. अमुल्या दीनदयाल सिल्हारे - एलएन सिटी चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर। कु. दीक्षा चमरूलाल लिल्हारे - अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, देवास।

सफलता का मंत्र- मेहनत, मार्गदर्शन और एनसीईआरटी

इन छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अपनी कड़ी मेहनत को दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की पुस्तकों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया और नियमित अध्ययन के साथ-साथ शिक्षकों द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन किया। छात्राओं ने अन्य विद्यार्थियों को भी सलाह दी कि नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकों का गहन अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कु. भूमि भागवत सुलाखे ने कहा, हमारी सफलता के पीछे स्कूल के शिक्षकों का मार्गदर्शन और हमारी मेहनत का बड़ा योगदान है। एनसीईआरटी की किताबें नीट की तैयारी का आधार हैं, और इन्हें गहराई से पढ़ने से हमें बहुत मदद मिली। इसी तरह, कु. सृष्टि वासनिक ने बताया कि नियमित अभ्यास और शिक्षकों के प्रोत्साहन ने उन्हें आत्मविश्वास दिया।

स्कूल और समुदाय में खुशी की लहर

साकेत पब्लिक स्कूल के संचालक संतोष मोरघड़े ने छात्राओं की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा, हमारे विद्यालय की ये बेटियां हमारा गौरव हैं। उनकी मेहनत और शिक्षकों के समर्पण ने यह साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन और कठिन परिश्रम से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।

इस उपलब्धि पर विद्यालय के समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं, महाविद्यालय के प्राचार्य आर.आर. सोनवाने, बीईओ प्रमोद भिमटे, डॉ. अक्षय उपराडे, डॉ. किशोर सोनवाने, डॉ. राजेश रणदिवे, डॉ. जेपी सुनेरी, डॉ. अंकित खरोले, डॉ. ओ.पी. नेवारे, दिनेश रामटेककर, कपिल अग्रवाल, झनकार किरनापुरे, विशाल राउत, विजय रामटेक्कर, राजू मोहारे, अजय खरगाल, रमेश आसटकर, नूतेंद्र रहमतकर, टी.सी. बिहोने, मयूर सुले, संजय टेंभरे, आलोक चौरसिया, कोमल काड़े, पुनीत रामटेककर, संदीप सिकंदरपुरी, दीपक अग्रवाल, महेंद्र रणदिवे, और राजू रामटेककर सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

लांजी की शैक्षणिक विरासत

लांजी क्षेत्र लंबे समय से अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। यहाँ के विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहे हैं। साकेत पब्लिक स्कूल ने भी इस क्षेत्र की शैक्षणिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्कूल के अनुशासित शिक्षण माहौल और समर्पित शिक्षकों ने छात्रों को उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। इन पांच छात्राओं का चयन न केवल उनके लिए, बल्कि लांजी के अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि छोटे शहरों और कस्बों के विद्यार्थी भी कठिन मेहनत और सही मार्गदर्शन के बल पर देश के शीर्ष संस्थानों में अपनी जगह बना सकते हैं। लांजी की इन बेटियों ने साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी स्थान या परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। उनकी यह उपलब्धि निश्चित रूप से अन्य छात्र-छात्राओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी।

कल मनाया जाएगा किसान वर्ग का प्रमुख त्यौहार पोला पर्व

लांजी (पद्मेश न्यूज)। लांजी क्षेत्र जो कि महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं से होने के कारण इन दोनो ही पड़ोसी राज्य में मनाये जाने वाले सभी प्रमुख त्यौहारो एवं बोली भाषाओं का असर लांजी क्षेत्र में देखा जा सकता है। इसी के चलते लांजी क्षेत्र में भी पोला पर्व धुम धाम से मनाया जाता है। भादो मास की अमावस्या को पोला पिठोरा पर्व मनाया जाता है। यह पोला पर्व किसान वर्ग का प्रमुख त्यौहार है, खेती किसानी का काम समाप्त हो जाने के बाद पशु धन का पूजन कर आभार व्यक्त करने का दिन है। इस दिन बैल जोडीयों को सजाकर इनकी पूजा की जाती है एवं घर घर ले जाकर भी पूजन किया जाता है। यह भी मान्यता है कि इस दिन धान के पौधे में दुध भरता है धान गर्भ धारण करता है। इस दिन घरो में माताऐं बहने पर्व के लिये तरह तरह के पकवान व्यंजन जिसमें पुरणपोली, उडददाल के बडे, गुजिया, ठेठरी, खुरमी, खीर पुड़ी सहित अनेको व्यंजन बनाये जाते है। जिन घरो में बैल जोडीयॉ होती है वे उस दिन अपने बैल जोडीयों को अच्छी तरह से नहलाकर सजाकर एवं उन्हे रंग बिरंगे फुलों अन्य साज सज्जाओं की सामग्रियों से सजाकर एक स्थान पर एकत्रित करते वहां उनका पूजन कर घर घर ले जाया जाता है। जहां उनका पूजन कर उन्हे घर मे बने व्यंजनो का भोग लगाया जाता है।

लांजी नगर परिषद के द्वारा मनाया जायेगा पोला पर्व

पोला पर्व पर 23 अगस्त दिन शनिवार को नगर परिषद लांजी के द्वारा परंपरानुसार नगर के पूराना गुजरी चौक के समीप में पोला पर्व मनाया जाएगा। नगर परिषद कार्यालय से आरती थाल लेकर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, पार्षद गण, गणमान्य नागरिक गणो सहित कार्यालयीन अधिकारी कर्मचारी आतिशबाजी करते हुये बाजे गाजे के साथ पोला पर्व स्थल पर पंहुचकर सर्वप्रथम माँ लंजकाई मंदिर में पूजा अर्चना करने के उपरांत श्री हनुमान मंदिर में पूजन करने के पश्चात आतिशबाजी कर बैल जोडीयों को रवाना किया जाता है।

श्री गणेश स्थापना को लेकर सजने लगे पंडाल

कठिन व्रत हरतालिका तीज की तैयारियां में जुटी महिलाएं

लांजी (पद्मेश न्यूज)। सनातन धर्म में श्री गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। यह पर्व भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। धार्मिक मत है कि भगवान गणेश जी की पूजा करने से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के विघ्न एवं बाधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही जीवन में मंगल का आगमन होता है। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी तथा हरतालिका जीत व्रत का महत्व और शुभ मुहूर्त-पंडित घनश्याम कृष्ण महाराज जी माँ काली मंदिर परिसर लांजी ने दी श्री गणेश प्रतिमा स्थापना एवं मुहूर्त की जानकारी दी।

हरतालिका तीज का व्रत

पंचांग अनुसार, भाद्रपद शुक्लपक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। यह व्रत अखंड सौभाग्य की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं करती हैं। इस साल तीज पर चार विशिष्ट योग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि, शोभन, गजकेसरी और पंचमहापुरुष योग बनने से तीज व्रत का महात्म्य और भी बढ़ गया है। इन चारों ही योगों के फल अत्यंत शुभ और लाभप्रद हैं। गजकेसरी योग का महत्व विशेष रूप से माना गया है। इस प्रकार की ग्रहीय स्थिति लंबे अंतराल पर बनती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 25 अगस्त की दोपहर 12-34 बजे लगेगी और 26 अगस्त की दोपहर 1-54 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार, हरतालिका तीज का

व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। इस बात का रखें ध्यान- धार्मिक मान्यताओन के अनुसार,जिन परिवारों में तृतीया तिथि के अंतर्गत ही तीज पूजन का विधान है उन्हें 26 अगस्त को दोपहर 1-54 बजे से पहले पूजा करनी होगी। दूसरी मान्यता यह भी है कि उदय काल में मिलने वाली तिथि यदि मध्याह्न बाद बदल जाती है तो भी सूर्यास्त तक उस तिथि का मान किया जाता है। दिनांक 26.8.2025 दिन मंगलवार को दोपहर 2 बजकर 22 मिनट के बाद से हस्त नक्षत्र में पूजन प्रारंभ करें यह रात्रि तक का व्रत होता है इस व्रत को पति पत्नी मिलकर करें तो दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होता है गणेश जी की स्थापना का सबसे शुभ समय मध्याह्न होता है, क्योंकि माना जाता है कि इसी समय भगवान गणेश का जन्म हुआ था। 27 अगस्त 2025 को मध्याह्न काल में गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11-05 बजे से दोपहर 01-40 बजे तक रहेगा। लांजी नगर सहित क्षेत्र में बडी मात्रा में श्री गणेश जी सार्वजनिक एवं घरो घर स्थापना की जाती है। जिसको लेकर जहां सार्वजनिक श्री गणेश समितियों के द्वारा तैयारियो प्रारंभ कर दी गई है पण्डाल आदि तैयार किये जा रहे है वही घंरो में भीश्री गणेश जी की स्वागत के लिये साज सज्जा प्रारंभ कर दी गई है। वहीं मुर्तिकारों द्वारा श्री गणेश जी की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। घरो में विराजमान होने वाली प्रतिमाऐ तो लगभग तैयार भी चुकी है क्योंकि पूर्व से ही लोग अपनी पंसद की मुर्तिया चयनित कर लेते है वही सार्वजनिक स्थल पर विराजमान होने वाली प्रतिमाऐं भी तैयार हो चुकी है मुर्तिकार प्रतिमा को अंतिम रूप देते नजर आ रहे है साज सज्जा के साथ सभी मुर्तिया तैयार हो जायेगी। 27 अगस्त को धूमधाम से श्री गणेश जी का स्वागत सत्कार कर विराजमान किया जायेगा।

प्रदेश अध्यक्ष खण्डेलवाल ने जीतू पटवारी द्वारा भाजपा विधायक को अमर्यादित शब्द कहने पर दी कड़ी प्रतिक्रिया

भाजपा विधायक के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग कांग्रेस अध्यक्ष की हताशा का प्रतीक

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा बैतूल जिले के मुलताई से भाजपा के तीसरी बार के विधायक चंद्रशेखर देशमुख को लेकर अमर्यादित शब्द कहने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश के साथ मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग को दिए जा रहे सम्मान से कांग्रेस पार्टी और उसके नेता बौखला गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा भाजपा के वरिष्ठ विधायक के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग कांग्रेस की हताशा का प्रतीक है। जीतू पटवारी ने एक जनप्रतिनिधि नहीं मध्यप्रदेश के समूचे पिछड़े वर्ग का अपमान किया है। राजनीति में मतभेद स्वाभाविक हैं, किंतु अशोभनीय भाषा का प्रयोग करना लोकतांत्रिक परंपराओं की अवहेलना और राजनीतिक मर्यादाओं का हनन है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का अमर्यादित शब्द कांग्रेस पार्टी के गिरते राजनीतिक स्तर को दिखाता है। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता पटवारी द्वारा जिस तरह से पिछड़ा वर्ग का अपमान किया जा रहा है, मध्यप्रदेश की जनता इसका सबक कांग्रेस को जरूर सिखाएगी।

पटवारी का अमर्यादित बयान कांग्रेस के गिरते राजनीतिक स्तर को दिखाता है

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता प्रदेश में अपनी खोई हुई लोकप्रियता और जनाधार से बौखलाकर कभी न्यायपालिका, अधिकारियों तो कभी जनप्रतिनिधियों पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। भाजपा विधायक चंद्रशेखर देशमुख प्रदेश के सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं। समूचे बैतूल जिले के सभी समाज वर्ग के लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। समूचा बैतूल जिला विधायक देशमुख के प्रति आदर का भाव रखता है। विधायक देशमुख अपना पूरा जीवन, दलितों, वंचितों और पिछड़े वर्ग के साथ समाज के हर वर्ग की सेवा को समर्पित किया है। जनता की सेवा के तत्पर देशमुख जैसे जनप्रतिनिधि का अपमान कर कांग्रेस मध्यप्रदेश के समूचे पिछड़ा वर्ग समाज को अपमानित कर रही है।

पिछड़े वर्ग का आगे बढ़ना कांग्रेस के नेताओं को रास नहीं आ रहा

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से पिछड़ा वर्ग को अपमानित करने का कार्य किया है। कांग्रेस पार्टी अपनी लगातार हार और जनसमर्थन खोने की हताशा में अब व्यक्तिगत कटाक्ष और अपमानजनक शब्दों का सहारा लेने लगी है। मध्यप्रदेश में कांग्रेस शासनकाल के दौरान हमेशा पिछड़े वर्ग की आवाज दबाई जाती रही है। कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग को हमेशा हाशिये पर रखा है। भाजपा ने मध्यप्रदेश में चार-चार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से बनाए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है, पिछड़ा वर्ग को सम्मान दिया जा रहा है, उससे कांग्रेस पार्टी और उसके नेता बौखलाए हुए हैं। पिछड़ा वर्ग का अपमान कांग्रेस पार्टी की सोच और मानसिकता को स्पष्ट करता है। कांग्रेस के लिए पिछड़ा वर्ग सिर्फ वोट बैंक मात्र रह गए है। कांग्रेस द्वारा लगातार जिस तरह से पिछड़ा वर्ग को अपमानित किया जा रहा है, मध्यप्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को जरूर सबक सिखाएगी।

श्री लक्ष्मीकांता कॉलेज में वसुधैव कुटुम्बकम कार्यक्रम का किया आयोजन

लांजी (पद्मेश न्यूज)। उच्च शासन के निर्देशानुसार 21 अगस्त 2025 को भारतीय ज्ञान परम्परा प्रकोष्ठ के अन्तर्गत वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के छायाचित्र पर पूजा अर्चना, माल्यार्पण कर किया गया। उक्त कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी स्तरों पर प्राचीन भारतीय विज्ञान एवं कला के समावेशन पर जोर देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भारतीय ज्ञान परम्परा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा कार्यक्रम के संबंध में छात्र-छात्राओं को बताया गया की भारतीय ज्ञान परम्परा ज्ञान का विशाल और समृद्ध भण्डार हैं जो कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण हैं साथ ही वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से सम्पूर्ण विश्व को शान्ति, भाईचारा और प्रेम से भरपूर बना सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय संस्कृति के बारे में अवगत कराया गया।

''अयं निज:परोवेति गणना लघुचेतसाम्
उदारचरितानां तु वसुधैवकुटुम्बकम्।।

अर्थात - यह मेरा हैं, यह पराया हैं ऐसी गणना दुष्टों की (छोटे चित्त वालों की) होती हैं। जबकि उदार चित्त वाले (बडे दिल वाले) तो पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महाविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ तथा छात्र-छात्राओं का विशेष योगदान रहा।

वन विभाग के वाहन चालकों ने पीसीसीएफ को सौंपा ज्ञापन

भोपाल। मप्र कर्मचारी मंच वन विभाग वाहन चालक समिति ने पीसीसीएफ वन बल प्रमुख को औपचारिक बैठक में अपनी दो सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में घनश्याम कटारे, राजू सिंह, हीरा यादव, महेंद्र राव, ओम प्रकाश मिश्रा, राजकुमार सिंह, रामचरण अहिरवार, राजेश कुशवाहा, भगवान सिंह आदि शामिल थे। मप्र कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि वन विभाग के वन बल प्रमुख ने कर्मचारियों की औपचारिक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में वन विभाग के वाहन चालक भी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए तथा अपनी बात रखी। वन विभाग के वाहन चालक घनश्याम कटारे के साथ 14 अगस्त को लिपिक सुधीर नेमा ने मारपीट की थी तथा जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं वाहन चालकों को आजादी का उत्सव नहीं मानने दिया था। वाहन चालकों ने घटना के विरोध में दो सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया था। घनश्याम कटारे की मांग पर वन बल प्रमुख ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं थाना टीटी नगर ने भी शिकायत पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। घनश्याम कटारे के बयान भी थाने में दर्ज हो गए हैं। इसलिए वन विभाग के वाहन चालकों ने निर्णय लिया है एक सप्ताह के लिए आंदोलन स्थगित किया जाए। यदि एक सप्ताह के अंदर लिपिक सुधीर नेमा को निलंबित करके गिरफ्तार नहीं किया गया तो पुन- आंदोलन किया जाएगा।

शादी के छह साल बाद पत्नि को दिया तीन तलाक नवविवाहिता ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप

भोपाल। तलैया थाना इलाके में एक नव विवाहिता को पति द्वारा तीन तलाक दिये जाने का मामला सामने आया है। थाना पुलिस के अनुसार थाना इलाके में ही रहने वाली 26 वर्षीय पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया की उसकी शादी छह साल पहले पहले निशातपुरा स्थित करोद में रहने वाले आबिद से हुई थी। पति आबिद फेब्रिकेशन का काम करता है। पीडिता का आरोप है कि शदी के थोड़े समय बाद ही पति सहित सास नाजमा, जेठ जावेद और ननद का पति हबीब मायके से कम दहेज लाने का कहते हुए ताने मारकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताडित करते थे। तंग आकर वह मायके में आकर रहने लगी थी। बीती 19 मार्च को उसका पति उसके घर आया था, उस समय पीड़िता की बहन भी मौजूद थी। पति आबिद ने उससे बातचीत की और विवाद करते हुए बहन के सामने उसने तीन बार तलाक बोलकर चला गया था। बाद में नवविवाहिता थाने पहुचीं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुस्लिम महिला संरक्षण सहित अन्य धाराओ में प्रकरण दर्ज किया है, वहीं सास समेत अन्य आरोपियो के खिलाफ दहेज प्रताडना का प्रकरण दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जॉच कर रही है।

लांजी में ''पद्मेश''
इंटरनेट (ब्राडबेंड)
कनेक्शन के लिये संपर्क करें
Mo. 8319969927

34 विभाग नहीं बता पा रहे अधूरी परियोजनाएं

5 महीने से मांगी जा रही रिपोर्ट, बैंकों में जमा रुपए भी नहीं बता पाए

भोपाल। मप्र के 34 विभाग अब तक यह नहीं बता पाए हैं कि 31 मार्च 2025 की स्थिति में उनके विभाग के अधीन बजट नियंत्रण अधिकारियों ने बैंकों में कितनी राशि जमा कर रखी थी। साथ ही निर्माण विभागों की ओर से यह जानकारी भी नहीं दी गई है कि इस अवधि में कौन-कौन से बड़े कार्य और परियोजनाएं अधूरी रहीं। यह स्थिति तब है जब ऑडिटर जनरल कार्यालय की तरफ से हर महीने राज्य शासन को पत्र लिखा जा रहा है और वित्त विभाग ने बार-बार विभागों को जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं। वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारियों की इस लापरवाही का सीधा असर सरकार की वित्तीय रिपोर्टिंग पर पड़ रहा है। इससे राज्य के वित्तीय लेनदेन का ब्यौरा तैयार करने में मुश्किलें आ रही हैं। महालेखाकार कार्यालय इस बार सीधे मुख्य सचिव को पत्र लिख चुका है। इसके बाद गुरुवार तक सभी विभागों को जानकारी भेजने के निर्देश एक बार फिर जारी किए गए हैं। इससे पहले, महालेखाकार कार्यालय ने इसको लेकर इस वित्त वर्ष में सबसे पहले 29 अप्रैल को, फिर 20 मई और इसके बाद 24 जुलाई को पत्र लिखा था। इसके बाद भी जवाब नहीं मिला तो एक अगस्त को वित्त विभाग को अलग और मुख्य सचिव को अलग पत्र भेजकर जानकारी दिलाने को कहा है।

वित्त विभाग ने विभागों से 31 मार्च 2025 की स्थिति में तय बजट के अलावा अन्य खर्च, अनपेड बिलों से संबंधित देनदारियां, आउटसाइड फंड ऑपरेशन की स्थिति, बैंकों में जमा राशि, पंचायत राज संस्थाओं को दी जाने वाली बकाया ग्रांट, पीपीपी मोड और जनभागीदारी के तहत हुए निवेश की जानकारी, नई योजनाओं पर लिए गए नीतिगत निर्णयों का संभावित कैश फ्लो, संस्थाओं को दी गई ग्रांट की पूरी जानकारी, सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम, अब तक नहीं दी गई यह महत्वपूर्ण जानकारी, बिजली योजनाओं के वित्तीय परिणाम, अपूर्ण बड़े कार्यों की सूची, नए ऋण और अग्रिम (एडवांस) की जानकारी, ऋण की अदायगी और बकाया स्थिति, ऋण और अग्रिम का समेकित विवरण (समरी) और निगमों, सरकारी कंपनियों और सहकारी संस्थाओं को दी गई सहायता, ऋण व लाभांश की रिपोर्ट की जानकारी मांगी गई थी।

इन विभागों के अधिकारियों ने नहीं दी रिपोर्ट

अब तक 58 बजट नियंत्रण अधिकारियों ने वित्तीय जानकारी नहीं भेजी है। संबंधित विभाग हैं, राजस्व विभाग, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, एमएसएमई, जनजातीय कार्य विभाग, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा, अनुसूचित जाति कल्याण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, महिला एवं बाल विकास, वाणिज्यिक कर, संसदीय कार्य, विमानन, लोक सेवा प्रबंधन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, वित्त विभाग, उच्च शिक्षा, सामान्य प्रशासन, वन विभाग, खनिज साधन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, श्रम विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, नगरीय विकास एवं आवास, लोक निर्माण विभाग, गृह विभाग, स्कूल शिक्षा, विधि एवं विधायी कार्य, जनसंपर्क विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, संस्कृति विभाग और मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग।

झाबुआ : म.प्र. ग्रामीण बैंक में 85.46 लाख के गबन का मामला, ईओडब्ल्यू इंदौर में मामला दर्ज

भोपाल/इंदौर।आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) मुख्यालय भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, झाबुआ में करोड़ों के गबन के मामले में बड़ा खुलासा किया गया है। प्रकोष्ठ में पंजीबद्ध शिकायत क्रमांक 14/2024 के सत्यापन उपरांत, बैंक कर्मचारी मोहित गुप्ता द्वारा धोखाधड़ी एवं गबन की पुष्टि हुई है। आरोपी ने बैंक के डोरमेंट (निष्क्रिय) खातों से 85.46 लाख रुपये की राशि का अनाधिकृत लेन-देन कर बैंक एवं खाताधारकों के साथ गंभीर धोखाधड़ी की है।

आरोपी मोहित गुप्ता पिता नारायण दास गुप्ता, सौरभ सेंगर पिता नरेन्द्र सिंह सेंगर,नरेन्द्र सिंह सेंगर पिता सुर्जन सिंह,देवराज सिंह पिता जितेन्द्र सिंह,गजेन्द्र सिंह सेंगर पिता सुर्जन सिंह सेंगर,मुकेश कुमार सबनानी पिता स्व. चन्द्रलाल सबनानीव अन्य सहयोगी आरोपी

अपराध-मुख्य आरोपी मोहित गुप्ता, जो म.प्र. ग्रामीण बैंक, झाबुआ शाखा में लिपिक के पद पर पदस्थ था, ने अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अन्य 12 सहयोगियों के साथ मिलकर, शाखा सोण्डवा के 11 निष्क्रिय खातों से धोखाधड़ीपूर्वक 85.46 लाख रुपये की राशि निकालकर अपने और परिचितों के खातों में स्थानांतरित की। इस संगठित अपराध के तहत आरोपियों ने न केवल बैंक के खाताधारकों के विश्वास का उल्लंघन किया, बल्कि संस्था को भी आर्थिक क्षति पहुंचाई।

आरापियों पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा अपराध क्रमांक 126/25 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 409 (आपराधिक विश्वासघात), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी), 13(2) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई है।

भोपाल में हाईकोर्ट बेंच स्थापित होने से जनता का समय और धन की बर्बादी रूकेगी-आलोक शर्मा

सांसद आलोक शर्मा केन्द्रीय कानून मंत्री से भोपाल में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने को लेकर मिले

भोपाल। सांसद आलोक शर्मा ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से मुलाकात कर भोपाल में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग की है। सांसद शर्मा ने केंद्रीय कानून मंत्री को सौंपे पत्र में भोपाल जिले की जनता को अपने न्यायिक प्रकरणों के लिए जबलपुर हाईकोर्ट जाने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों का जिक्र किया है। सांसद शर्मा ने केंद्रीय मंत्री मेघवाल से आग्रह किया कि यदि हाइकोर्ट बेंच भोपाल लाने में कोई अड़चन है तो भोपाल जिले का न्यायिक क्षेत्राधिकार इंदौर से जोड़ दिया जाए, जिससे जनता को समय और अत्यधिक धन खर्च से राहत मिलेगी। केंद्रीय कानून मंत्री से चर्चा के दौरान सांसद आलोक शर्मा ने बताया कि भोपाल में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने को लेकर लंबे समय से प्रयास किये जा रहे हैं। लेकिन जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिलने के संकल्प को पूरा करने के लिए कोई ठोस प्रयास अब तक नहीं हो सके। जबकि देश में अधिकांश प्रदेशों की राजधानियों में हाइकोर्ट की मुख्य पीठ या बेंच स्थापित है।

इंदौर खंडपीठ से जोड़ने का दिया सुझाव

सांसद आलोक शर्मा ने केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को सुझाव दिया है कि यदि भोपाल में हाइकोर्ट की बेंच स्थापित करने में कोई अड़चन है तो भोपाल जिले का न्यायिक क्षेत्राधिकार (ज्यूरिडिक्शन) इंदौर से जोड़ दिया जाए। इंदौर की दूरी जबलपुर से कम है। जनता व सरकार के अधिकारी न्यायिक मामलों की सुनवाई के लिए सुबह जाकर शाम तक घर वापिस आ सकते हैं। ऐसे में जनता का समय और पैसे की बर्बादी तो रुकेगी ही साथ ही सरकारी खजाने पर पड़ने वाला अत्यधिक भार भी कम हो जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को अपनी पदोन्नति व अन्य प्रकरणों की सुनवाई के लिए जबलपुर जाना-आना करना मुश्किलें पैदा करता है।

वकीलों की है पुरानी मांग

भोपाल में हाईकोर्ट बेंच लाने के लिए वकील और बार एसोशिएशन भी लंबे समय से प्रयासरत हैं। वर्तमान में भोपाल का न्यायिक क्षेत्र जबलपुर है। भोपाल से जबलपुर जाने आने में लंबा समय और पैसे की बर्वादी होती है। यदि भोपाल का न्यायिक क्षेत्राधिकार इंदौर जोड़ दिया जाए तो भी जनता को काफी राहत मिल जाएगी। वकीलों को भी मामलों में पैरवी के लिए जबलपुर जाने आने में अपना अधिक समय खर्च करना पड़ता है। सांसद शर्मा ने आम जनता, वकील और सरकारी अधिकारियों की व्यवहारिक परेशानियों को तो अपने पत्र में लिखा ही है साथ ही इससे सरकारी खर्चों को रोकने का सुझाव भी दिया है।

जनता का समय और पैसा बचेगा

सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि भोपाल जिले का न्यायिक क्षेत्र इंदौर खंडपीठ से जुड़ने पर जनता का समय और पैसा दोनों बचेंगे। साथ ही सरकार के जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के संकल्प की भी पूर्ति होगी।

दिसंबर तक बनकर तैयार होगी भोपाल की सबसे बड़ी गोशाला

भोपाल। भोपाल के बरखेड़ी अब्दुल्ला में राजधानी की सबसे बड़ी गोशाला दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगी। इस गोशाला में 10 हजार गायों को एक ही छत के नीचे रहने की व्यवस्था रहेगी। गोशाला का काम अंतिम दौर में है। आयुक्त संजीव सिंह ने गोशाला को जल्द पूरा करने के निर्देश समीक्षा बैठक में दिए हैं।

आयुक्त संजीव सिंह ने समीक्षा बैठक में गोशाला के कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह इसका सारा काम दिसंबर तक पूरा कर लें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस गोशाला का भूमिपूजन किया था। यह उनकी प्राथमिकता वाले कार्यों में शामिल हैं। कार्य पूर्ण करने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाए।

14.48 करोड़ रुपए से बन रही गोशाला

समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रथम चरण में 14 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि से गोशाला का निर्माण कार्य दिसंबर माह तक पूरा किया जाएगा। गोशाला में गोशाला के संचालन के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली जाएं। गायों के भोजन की व्यवस्था के लिए टेंडर एवं अन्य कार्यों की पहले से तैयारी कर ली जाए।

कुल 10 हजार गायों को रखने की व्यवस्था की जाएगी। प्रथम चरण में 2 हजार गाय रखने के लिए 4 शेड तैयार होंगे। प्रत्येक शेड में 500 गाय रखी जाएंगी। हर शेड के सामने ओपन स्पेस रहेगा।

बीमार गायों का इलाज भी

गोशाला में बीमार गायों इलाज की समुचित व्यवस्था की जाएगी। बीमार गायों के लिए दो शेड तैयार होंगे। जिसमें एक आईसीयू एवं एक जनरल वार्ड होगा। इसके अतिरिक्त चारा शेड, एक बछड़ा शेड, पानी की टंकी और संपबेल बनाया जाएगा। गोशाला में ऑफिस और निवास भी बनाए जाएंगे। बैठक में संयुक्त आयुक्त विनोद यादव, स्वामी अच्युतानंद महाराज समेत संबंधित विभागों के अफसर मौजूद थे।

कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर मचे बवाल के बीच संगठन का फैसला

भोपाल। मध्यप्रदेश में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद मचे बवाल को लेकर संगठन डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। इसी कड़ी में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब मध्यप्रदेश कांग्रेस उनके कामकाज पर भी तकनीकी रूप से नजर रखेगी। उनकी निगरानी के लिए पार्टी ने एक रिपोर्टिंग एप तैयार किया है। जानकारी के अनुसार एप पर जिला अध्यक्ष प्रतिदिन अपने काम की जानकारी अपलोड करेंगे। कांग्रेस संगठन में यह प्रयोग पहली बार मध्यप्रदेश से शुरू हो रहा है। एप सफल रहा तो एआईसीसी (ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी) इसे अन्य राज्यों में भी लागू करेगी। 24 अगस्त को इसी विषय को लेकर दिल्ली में सभी 71 नए जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग रखी गई है।

सरकारी स्कूलों में अब 9वीं से 12वीं तक की त्रैमासिक परीक्षा भी बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर

भोपाल। पहले सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की त्रैमासिक और छमाही परीक्षा कब हो जाती थी, पता नहीं चलता था। इस बार भी ये परीक्षाएं होंगी। लेकिन इस बार इन परीक्षाओं को लगभग लगभग बोर्ड परीक्षाओं की तर्ज पर कराया जाएगा। इस बार परीक्षा में संयुक्त संचालक शिक्षा व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित दल न केवल परीक्षाओं का निरीक्षण करेंगे, बल्कि परीक्षा का रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। लोक शिक्षण विभाग ने परीक्षाओं की समय सारणी भी घोषित कर दी हैं। अब शिक्षा विभाग परीक्षाओं को सुचारू कराने के लिए दल गठित करने का काम शुरू कर दिया है।

पहले त्रैमासिक परीक्षा व छमाही परीक्षा की समय सारणी स्कूल अपने स्तर से बनाते थे और अपनी सुविधा अनुसार ही परीक्षा कराते थे। अब पूरे प्रदेश में एक साथ परीक्षा होगी। हालांकि बोर्ड 9वीं से 12वीं तक की परीक्षाओं की तिथि व समय सारणी जारी करता था। पहले त्रैमासिक व छमाही की परीक्षा स्कूल स्तर पर होती थी और प्रश्नपत्र भी स्कूल के शिक्षक ही बनाते थे। अब लोक शिक्षण विभाग ही प्रश्न पत्र बनाएगा और पोर्टल पर प्रश्नपत्र वाले दिन उपलब्ध होंगे। जिनकी प्रिंट लेकर फोटो कापी कराकर प्रश्नपत्र छात्रों को दिए जाएंगे। पहले शिक्षा विभाग के दल भी इन परीक्षाओं का निरीक्षण नहीं करते थे। लेकिन इस बाद संयुक्त संचालक व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित दल परीक्षाओं का निरीक्षण करेंगे। इन्हें भी एक दिन में कम से कम 10-10 स्कूलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले त्रैमासिक व छमाही परीक्षा का परिणाम व छात्रों के अंक पोर्टल पर अपलोड नहीं होते थे। अबकी बार परिणाम 20 सितंबर तक पोर्टल पर अपलोड करना है।

क्यों किया गया है ऐसा

विभाग के अफसरों का कहना है कि इससे छात्र व स्कूलों के शिक्षक परीक्षा की गंभीरता को समझेंगे। साथ ही प्रश्नपत्र भी बोर्ड स्तर के होंगे। इससे छात्रों को वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करने में भी आसानी होगी।

दस साल की मासूम से अशलीलता करने वाले को पॉच साल की जेल

भोपाल। राजधानी के शाहपुरा थाना इलाके में करीब साढ़े चार साल पहले दस साल की मासूम से ज्यादती और पॉक्सो एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने चार साल पहले दस साल की बच्ची से हुई ज्यादती के मामले में आरोपी को पॉच साल की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। प्रकरण में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट पुलिस द्वारा दर्ज दुष्कर्म की धाराओं को लेकर सहमत नहीं हो सका। हालांकि प्रकरण छेड़छाड़ का मानते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। जानकारी के अनुसार शाहपुरा थाना पुलिस ने 6 फरवरी, 2021 को दस साल की मासूम के साथ ज्यादती और पॉक्सो एक्ट की धाराओ में आरोपी सुनील त्रिरोले के खिलाफ मामला कायम किया था। काम के चलते बच्ची के माता-पिता के बाहर जाने पर आरोपी सुनील मासूम को बहलाकर अपनी गोद में बैठाकर उसके साथ अशलील हरकतें करता था। बाद में बच्ची ने माता-पिता को सुनील की करतूत बताई, जिसके बाद मां ने थाने जाकर प्रकरण दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने पाक्सो एक्ट के अलावा दुष्कर्म की धाराएं लगाते हुए आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष की और से ज्यादती की धाराएं लगाने पर अपनी दलील देते हुए पुलिस जॉच पर सवाल उठाये थे। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सुनील त्रिरोले को पॉक्सो एक्ट की धारा के अलावा छेड़छाड़ की धारा में दोषी करार दिया। सुनील को पॉक्सो एक्ट में पांच साल की जेल और छेड़छाड़ की धारा में एक साल की सजा सहित सौ-सौ रुपए के अर्थदंड की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया गया।

शिकायत के पांच साल बाद ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज

दो दिन के लिए भोज विश्वविद्यालय के कुलसचिव बने प्रवीण जैन ने की 66 अवैध नियुक्तियां

भोपाल। भोज मुक्त विश्वविद्यालय में वर्ष 2013-14 में 66 पदों पर अवैध नियुक्तियां और नियमितीकरण के आरोप में मप्र आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने एफआइआर कायम की है। इसमें तत्कालीन निदेशक प्रवीण जैन और अन्य अधिकारी-कर्मचारियों को आरोपित बनाया गया है। इन पर धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार के आरोप एफआईआर दर्ज की गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि तत्कालीन निदेशक प्रवीण जैन को दो दिन प्रभारी कुल सचिव बनाया गया था, तभी उन्होंने नियुक्तियां और नियमितीकरण कर डाला। सागर के रहने वाले सुधाकर सिंह राजपूत की शिकायत की जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने अब प्रकरण पंजीबद्ध किया है। उन्होंने 25 फरवरी 2020 को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में शिकायत की थी। यानी पांच वर्ष बाद मामला दर्ज किया गया है। शिकायत की जांच में सामने आया कि वर्ष 2013-14 में भोज मुक्त विश्वविद्यालय में कुलसचिव की अनुपस्थिति के दौरान निदेशक प्रवीण जैन को दो बार (एक अक्टूबर 2013 और 27 नवंबर 2014) एक-एक दिन के लिए कुलसचिव का अस्थायी प्रभार दिया गया।

शासन के आदेशानुसार इस प्रकार का प्रभार निदेशक जैसे शैक्षणिक पदाधिकारी को देना नियम विरुद्ध था। बावजूद इसके, प्रवीण जैन ने इस अल्पकालिक प्रभार का दुरुपयोग करते हुए कुल 66 कर्मचारियों की नियुक्ति व नियमितीकरण कर दिया। इनमें कंप्यूटर आपरेटर, लिपिक, भृत्य, वाहन चालक, तकनीकी स्टाफ, सहायक प्राध्यापक, स्टेनोग्राफर आदि शामिल हैं। जांच में पता चला है कि नियुक्तियां शासन की स्वीकृति, पद सृजन, रोस्टर पालन, आरक्षण नीति, तथा वैधानिक प्रक्रिया जैसे आवेदन, चयन, मूल्यांकन आदि के बिना की गईं। पांच अक्टूबर 2013 को उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर विश्वविद्यालय को स्पष्ट निर्देशित किया था कि यदि कोई नियमितीकरण किया गया हो तो उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। इसके बाद भी नियुक्तियां यथावत रहीं।

एमडी ड्रग्स मामले में बिजली विभाग के दो आउटसोर्स कर्मचारियों पर मामला दर्ज

भोपाल। डायरेक्टोरेट रेवेन्यु इंटेलीजेंस (डीआरआई) की एमडी ड्रग्स बनाने वाले मकान पर कार्रवाई के बाद अब ईटखेड़ी पुलिस ने यहॉ कनेक्शन देने वाले बिजली कंपनी के दो आउटसोर्स कर्मचारियों पर अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इसकी शिकायत मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के ईटखेड़ी वितरण केंद्र के सहायक प्रबंधक ने की थी। इस मामले में रज्जाक खॉन को भी आरोपी बनाया गया है। जॉच में सामने आया की ड्रग्स फैक्ट्री को आउटसोर्स कर्मचारियों ने मिलीभगत करते हुए फैक्ट्री का निरीक्षण किए बिना निर्धारित शुल्क अपनी जेब में रखकर बिजली का मीटर मुहैया करा दिया था। थाना पुलिस के अनुसार ईटखेड़ी वितरण केंद्र में नीरज भारती सब-स्टेशन ऑपरेटर और मनीष मीणा लाइन हेल्पर है। दोनों ही आउटसोर्स कर्मचारी हैं। अब्दुल रज्जाक द्वार ईटखेड़ी वितरण कंपनी में नए बिजली के लिए आवेदन दिया गया था। कर्मचारियों द्वारा 4 अगस्त को एचपीएल कंपनी का मीटर लगाकर बिजली की सप्लाई शुरू कर दी। नया बिजली कनेक्शन देने से पहले मौके का निरीक्षण नहीं किया गया। साथ ही निर्धारित शुल्क 6 हजार 21 रुपए भी कंपनी में जमा नहीं कराये गये। जबकि कंपनी के नियमानुसार कनेक्शन देने से पहले फैक्ट्री का निरीक्षण किया जाना था, और लिया गया शुल्क कंपनी में जमा करना था। शुल्क कंपनी में जमा नहीं करते हुए लाइन हेल्पर मनीष मीना के साथ मिलकर सब स्टेशन ऑपरेटर नीरज भारती ने कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाया। यह रज्जाक खान निवासी जगदीशपुर की मिलीभगत से हो सका। बिना शुल्क जमा किए बिजली की सप्लाई करने पर आवेदक रज्जाक खान द्वारा बिजली की चोरी की गई है। जिसके चलते मामले में उसे भी आरोपी बनाया गया है।

- 92 करोड़ की मेफेड्रोन हुई थी जप्त

गौरतलब है कि डीआरआई ने जगदीशपुर स्थित एक फैक्ट्री से 92 करोड़ की मेफेड्रोन पकड़ी गई है। शनिवार 16 अगस्त की देर रात टीम ने जगदीशपुरा (इस्लामनगर) में छापा मारते हुए यहां से 61.20 किलो लिक्विड मेफेड्रोन और 541 किलो से ज्यादा कच्चा माल जब्त किया। मौके से ड्रग्स के साथ रज्जाक खान को डीआरआई की टीम ने पकड़ा था। कार्रवाई में जो 541 किलो कच्चा माल मिल, उसमें मेथिलीन डाइक्लोराइड, एसीटोन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन और 2-ब्रोमो शामिल थे। ये वही केमिकल हैं, जिनसे एमडी ड्रग्स बनता है। रिमांड के दौरान आरोपियों से उनके अन्य शहरों में नेटवर्क का भी पता लगाया जा रहा है।

- जुलाई में खरीदा गया था मकान

आरोपी विदिशा निवासी रज्जाक ने जुलाई की दूसरे सप्ताह में एग्रीमेंट कराने के बाद यह 590 वर्गफीट का मकान खरीदा था। इसमें दो कमरे में आरोपी अब्दुल फैजल के साथ मिलकर मशीनरी और कच्चा माल इकट्ठा कर रहे थे। इस कच्चे माल से एमडी ड्रग्स बनाने का प्लान था।

टेंडर के दस्तावेज दिखाकर मप्र कांग्रेस ने लगाया आरोप

भोपाल। मप्र कांग्रेस ने जिला अस्पतालों में मेडिकल जांच के नाम पर 300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। 85 अस्पतालों में निजी कंपनियां सामान्य दाम की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक राशि वसूल रही हैं। कंपनियों को सरकार भुगतान करती है। इन लैब में हर दिन औसत 40 हजार जांचें हो रही हैं। मप कांग्रेस ने टेंडर के कागज जारी कर आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ खेल हो रहा है। दो कंपनियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। एक एनजीओ को भी इसमें लाभ पहुंचाया जा रहा है।

कांग्रेस का आरोप है कि 5 साल से सरकारी अस्पतालों में जांच का जिम्मा निजी कंपनी साइंस हाउस व पीओसीटी सर्विसेज के पास है। इन कंपनियों को एनएबीएल की दर से 25 फीसदी अधिक कीमत पर भुगतान किया जा रहा है। कंपनियां नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज यानी एनएबीएल की दरों के हिसाब से कीमत वसूल रही हैं। जबकि सरकारी अस्पतालों की लैब के पास एनएबीएल का सर्टिफिकेट है ही नहीं।

यह है मामला

दरअसल, स्वास्थ्य विभाग ने साल 2019 में टेंडर के माध्यम से जिला अस्पतालों में 70 से अधिक मेडिकल जांच की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी थी। एमएस साइंस हाउस मेडिकल्स प्रालि और एमएस पीओसीटी सर्विसेज प्रालि को ठेका मिला था। कंपनियों ने टेंडर दस्तावेज में सीजीएचएस की एनएबीएल दरें डालीं, जो कि गैर एनएबीएल सर्टिफिकेट वाले लैब की अपेक्षा 25 फीसदी अधिक होती हैं।

कंपनियों ने लगाया 800 करोड रुपए का बिल

साल 2020 से कंपनियों ने काम शुरू किया। करीब 85 जिला अस्पतालों में कंपनियों की ओर से जांच की जा रही है। एक हिसाब से कंपनियों ने 800 करोड रुपए का बिल लगाया। 25 प्रतिशत ज्यादा राशि के हिसाब से करीब 300 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगाया गया है। हाल ही में इस ठेके को फिर से बढ़ा दिया गया है, जबकि राज्य व देशभर में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेहद कम दरों पर उपलब्ध हैं।

भाजपा में सत्ता और संगठन में नियुक्ति का फॉर्मूला तय

भोपाल। मप्र में भाजपा में सत्ता और संगठन में नियुक्ति का फॉर्मूला तय किया गया है। अब पार्टी में एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूला लागू होगा। आगामी दिनों में एक पद फॉर्मूले पर ही नियुक्तियां होंगी। सत्ता और संगठन में किसी एक में पद मिलेगा। इस फॉर्मूले के तहत अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। इसी कड़ी में जिन्हें निगम, मंडल और प्राधिकरणों में जगह मिलेगी उन्हें पार्टी संगठन में कोई भी पद नहीं मिलेगा। पार्टी की ओर से ज्यादातर नए चेहरों को मौका देने की भी तैयारी है। इसे लेकर दिल्ली के बाद राजधानी भोपाल में बैठक हो चुकी है।

30 अगस्त तक जिला कार्यकारिणी घोषित

8 जिला मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष और 1 कार्यालय मंत्री नियुक्त होंगे। जिला मीडिया प्रभारी और प्रवक्ताओं की भी नियुक्ति होगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री भगवानदास सबनानी ने बताया कि मंथन का दौर जारी है। वरिष्ठ नेता विचार कर रहे हैं। जल्द कार्यकर्ताओं की सुनवाई होगी।

भारतीय टीम को एशिया कप में खेलने से नहीं रोकेगी सरकार

नई दिल्ली। भारतीय टीम को अगले महीने एशिया कप में हिस्सा लेना है। अब इसे लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से खेल मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सरकार भारत को एशिया कप में हिस्सा लेने से नहीं रोकेगी। भारत को इस टूर्नामेंट में 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला भी खेलना है जिसे लेकर काफी विवाद भी हो रहा है।

'बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलने से नहीं रोक सकते'

खेल मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान की टीमें द्विपक्षीय मुकाबला नहीं खेलती हैं, लेकिन टीम को एशिया कप जैसे बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलने से नहीं रोका जा सकता। मंत्रालय ने भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के संबंध में नई नीति का अनावरण किया जिसे पाकिस्तान पर विशेष ध्यान रखकर बनाया गया है। सूत्रों ने बताया कि यह नीति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए नई नीति का अनावरण

मंत्रालय की इस नीति में कहा गया है, पाकिस्तान से जुड़े खेल टूर्नामेंट के प्रति

भारत का दृष्टिकोण उस देश के साथ व्यवहार करने की उसकी समग्र नीति को दर्शाता है। जहां तक एक-दूसरे के देश में द्विपक्षीय खेल प्रतियोगिताओं का संबंध है तो भारत की टीमें पाकिस्तान में प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेंगी और ना ही हम पाकिस्तान की टीमों को भारत में खेलने की अनुमति देंगे। हालांकि, बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंट प्रभावित नहीं होंगे।

सूत्रों ने कहा, हम भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप में खेलने से नहीं रोकेंगे क्योंकि यह बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। लेकिन पाकिस्तान को भारतीय जमीन पर द्विपक्षीय मुकाबले के लिए मंजूरी नहीं दी जाएगी। लेकिन हम उन्हें बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलने से नहीं रोकेंगे क्योंकि हम ओलंपिक चार्टर से बंधे हुए हैं। सूत्र ने कहा, हम भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप में खेलने से नहीं रोक सकते क्योंकि यह कई देशों का टूर्नामेंट है। जब तक पाकिस्तान मेजबान नहीं है, हम टीम को खेलने से नहीं रोक सकते। वैसे भी हमारे नहीं खेलने से पाकिस्तान को ही फायदा होगा। हमें उसे हराना है सीमा पर भी और खेल के मैदान पर भी।

नीति से स्पष्ट है कि 2030 राष्ट्रमंडल खेल और 2036 ओलंपिक की मेजबानी का इच्छुक भारत ओलंपिक चार्टर का पालन करेगा ताकि बड़े टूर्नामेंटों के संभावित मेजबान के रूप में खुद को स्थापित कर सके। यही वजह है कि भारत सरकार ने अगले महीने बिहार में होने वाले एशिया कप के लिये पाकिस्तानी हॉकी खिलाड़ियों को वीजा देने पर मंजूरी जताई हालांकि पाकिस्तान ने सुरक्षा कारणों से आने से इनकार कर दिया।

सूर्यकुमार की अगुआई में खेलने उतरेगी टीम

भारत ने हाल ही में एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित की थी। भारत इस टूर्नामेंट में सूर्यकुमार यादव की अगुआई में खेलने उतरेगा। इस टीम के उपकप्तान शुभमन गिल होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले को लेकर रोष देखने मिला है। अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से सैन्य अभियान चलाया था जिसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ गए थे। इसी को देखते हुए हरभजन सिंह और केदार जाधव जैसे कई पूर्व क्रिकेटरों ने पाकिस्तान के साथ एशिया कप में नहीं खेलने की अपील की थी।

तीन बार हो सकती है दोनों टीमों की भिड़ंत

भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को दुबई में ग्रुप चरण का मैच खेलना है। यह पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार होगा जब दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी टीमें एक दूसरे के सामने होंगी। भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप में तीन बार भिड़ सकती हैं। ग्रुप चरण के बाद दोनों टीमें सुपर चार चरण और फाइनल में भी भिड़ सकती है।

यूएई के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा भारत

एशिया कप का आयोजन नौ से 28 सितंबर तक यूएई में होना है। भारतीय टीम एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगी। इसके बाद 14 सितंबर को उसका मैच पाकिस्तान के साथ होगा और फिर ग्रुप चरण में उसका आखिरी मुकाबला 19 सितंबर को ओमान से खेला जाएगा।

पाकिस्तान से मैच का फैसला बीसीसीआई के हाथ में, खिलाड़ियों को कुछ न कहें - गावस्कर

मुम्बई। अगले महीने एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच का विरोध होना शुरु हो गया है। प्रशंसकों के साथ ही कई पूर्व क्रिकेटर भी इस मैच के बहिष्कार की मांग कर रहे है। इनका कहना है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब पाक से किसी भी स्तर पर क्रिकेट नहीं खेलना चाहिये। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी इस मैच का कड़ा विरोध किया है। हाल में भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटरों ने पाकिस्तान के खिलाफ हुई विश्व क्रिकेटरर्स लीग में भी पाक के मैच का बहिष्कर किया था। इसी बीच कुछ लोगों ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों की चुप्पी पर भी सवाल उठाये हैं। इसी को देखते हुए महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर खिलाड़ियों के बचाव में सामने आये हैं। गावस्कर ने एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ियों की आलोचना नहीं करने को कहा है। उन्होंने कहा कि टीम के खिलाड़ी इस मामले में कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। इसका अधिककार केवल क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को है। खिलाड़ी केवल भारत सरकार के निर्देशों का ही पालन कर रहे हैं। गावस्कर ने कहा है, 'अगर सरकार ने कोई फैसला लिया है तो मुझे नहीं समझ आता कि कैसे खिलाड़ियों की आलोचना की जा सकती है या उन पर टिप्पणियां हो सकती हैं। खिलाड़ियों का तो बीसीसीआई से करार है और बोर्ड को भारत सरकार से निर्देश मिल रहे होंगे। इसलिए सबकुछ तो उन पर निर्भर कर रहा।' इस पूर्व कप्तान ने कहा, खिलाड़ी इस मामले में बेबस हैं। उन्हें एशिया कप में खेलने के लिए चुना गया है और अगर सरकार कहती है कि आपको खेलना है तो वे जाएंगे और खेलेंगे। अगर सरकार कहती है कि नहीं, तब बीसीसीआई उसके हिसाब से कदम उठाएगा, खिलाड़ी अपने से कोई फैसला नहीं कर सकते। गावस्कर का लगता है कि इस मुद्दे पर गेंद पूरी तरह सरकार के पाले में हैं। उन्होंने आगे कहा, 'जैसा कि मैनें कहा, यह पूरी तरह भारत सरकार पर है कि बीसीसीआई को कहे कि क्या करना है।' एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में शुरू हो रहा है, जिसका फाइनल 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। इसमें भारतीय टीम का पहला मुकाबला 10 तारीख को यूएई के खिलाफ है।

एशिया कप कप आते-आते टीम में हुए कई बदलाव, शमी और बिश्नोई हुए बाहर

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम अब एशिया कप 2025 में खेलती दिखेगी। इसके लिए चयनित टीम में अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और स्पिनर रवि बिश्नोई को शामिल नहीं किया गया है। एशिया कप 9 सितंबर से यूएई में खेला जाएगा। पिछली टी20 सीरीज से तुलना की जाये तो एशिया कप के लिए जो टीम बनायी गयी है। इसमें काफी बदलाव हुए हैं। भारत ने अंतिम बार कोई टी20 सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ इसी साल की शुरुआत में खेली और 4-1 से अपने नाम की, लेकिन उस टीम से एशिया कप के आते-आते कई बड़े बदलाव हुए हैं।

शमी ने पिछली सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैचों में 3 विकेट लिए थे। वहीं बिश्नोई ने 5 मैचों में 5 विकेट लिए थे। इसके बाद भी इन दोनो के नामों पर एशिया कप के लिए विचार नहीं हुआ। इससे साफ है कि ये दोनो टी20 विश्वकप की योजना का हिस्सा नहीं हैं हालांकि मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने टीम की घोषणा के दौरान कहा कि ये टी20 वर्ल्ड कप की फाइनल टीम नहीं है। अभी केवल संभातित खिलाड़ियों को आजमाया जा रहा है। शमी टीम की घोषणा के एक दिन बाद ही बुधवार को लेग स्पि?न गेंदबाजी करते हुए दिखे। इसका वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया है। शमी अंतिम बार एकदिवसीय में न्यूजीलैंड के खिलाफ चैम्पि?यंस ट्रॉफी के फाइनल में नजर आये थे। यह मुकाबला 9 मार्च 2025 को हुआ, वहीं बिश्नोई 2 फरवरी 2025 को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय खेलते दिखे थे, शमी भी उस मैच में थे।

श्रीकांत ने एशिया कप के लिए चयनित टीम पर उठाये सवाल

इस टीम से टी20 विश्वकप नहीं जीत सकते

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा है कि बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए जो टीम घोषित की है वह सही नहीं है। श्रीकांत के अनुसार इस टीम से एशिया कप तो जीता जा सकता है पर अगले साल 2026 में होने वाला विश्वकप नहीं। इस टूर्नामेंट के जरिए भारतीय टीम अगले साल होने वाली टी20 विश्व कप 2026 की तैयारियां भी शुरु करेगी। श्रीकांत के अलावा कई पूर्व क्रिकेटरों को भी ये टीम पसंद नहीं आयी है। बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को टीम में जगह ना मिलने से जहां कई दिग्गज नाराज हैं तो वहीं कई लोगों ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा के चयन पर सवाल उठाये हैं। इसी कारण श्रीकांत ने कहा, , हम इस टीम के साथ एशिया कप तो जीत सकते हैं पर इस टीम के साथ टी20 विश्व कप जीतने की कोई संभावना नहीं है। साथ ही सवाल किया कि क्या आप इस टीम को विश्व कप में ले जाएंगे? क्या यह टी20 विश्व कप की तैयारी है, जो केवल छह महीने बाद होना है? उन्होंने कहा कि अक्षर पटेल को उप-कप्तानी से हटा दिया गया है। वहीं कमजोर प्रदर्शन के बाद भी

रिंकू सिंह, शिवम दुबे और हर्षित राणा को टीम में कैसे जगह मिली ये समझ से परेश है। आईपीएल को चयन का मुख्य मानदंड माना जाता है पर लगता है चयनकर्ताओं ने उससे पहले के प्रदर्शन को ध्यान में रखा है। श्रीकांत ने टीम के बल्लेबाजी क्रम पर भी सवाल उठाते हुए कहा, पांचवें नंबर पर कौन बल्लेबाजी करेगा? पांचवें नंबर पर संजू सैमसन, जितेश शर्मा, शिवम दुबे या रिंकू सिंह में से कोई एक होना चाहिए। हार्दिक पांड्या आमतौर पर पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, इसलिए अब पटेल अक्षर छठे नंबर पर बल्लेबाजी नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने शिवम को कैसे शामिल किया। वहीं यशस्वी जायसवाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके बाद भी उसे बाहर कर दिया गया।

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से यूएई में होगी। टी20 प्रारुप में खेले जाने के कारण इस टूर्नामेंट के जरिए ही भारतीय टीम अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां करेगी।

बीसीसीआई ने चयन समिति के प्रमुख अगरकर का अनुबंध एक साल बढ़ाया

मुम्बई। एशिया कप के लिए भारतीय टीम के चयन के बाद ही बीसीसीआई ने मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर का अनुबंध जून 2026 तक बढ़ा दिया है। अगरकर के चयन समिति प्रमुख बनने के बाद भारतीय टीम ने भारत ने 2024 में टी20 विश्व कप और इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर आईसीसी ट्रॉफी जीती थी। अगरकर के कार्यकाल में ही भारतीय टेस्ट टीम भी बेहतर हुई है और उसने साल 2023 विश्व कप के फाइनल में स्थान बनाया था। इन सभी उपलब्धियों को देखते हुए ही अगरकर का अंनुबंध बढ़ाया गया है।

एक रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल 2025 से पहले ही अगरकर के अनुबंध को बढ़ाने की बात हो गई थी, जिसे मंजूर कर लिया है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा, अगरकर के कार्यकाल में भारतीय टीम को का टेस्ट और टी20 में प्रदर्शन अच्छा रहा। इसी कारण बोर्ड ने उनका अनुबंध एक साल के लिए बढ़ा दिया है। अगरकर ने भी ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। अगरकर के कार्यकाल में ही विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टी20 और टेस्ट से संन्यास लिया जिससे भारतीय टीम इन प्रारुपों में दो नये कप्तान मिले। टेस्ट में शुभमन गिल जबकि टी20 में सूर्यकुमार यादव को यह जिम्मेदारी मिली और ये दोनो ही सफल रहे। वहीं रोहित-विराट अब एकदिवसीय में ही खेल रहे हैं और आने वाले समय में यहां भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। देखना है कि इन दोनो को अगले विश्वकप तक के लिए जगह मिलती है या नहीं।

वर्तमान समय में चयन समिति में अगरकर के अलावा एसएस दास, सुब्रतो बनर्जी, अजय रात्रा और एस शरत जैसे खिलाड़ी शामिल हैं पर माना जा रहा है कि सितंबर में होने वाली वार्षिक आम सभा की बैठक के बाद चयन समिति में कुछ बदलाव होंगे। शरत के अब चार साल पूरे होने को है। ऐसे में उनकी जगह पर किसी नये व्यक्ति को ये जिम्मेदारी मिल सकती है। बीसीसीआई आगे चलकर नए सिरे से आवेदन आमंत्रित करेगा। तभी तय होगा कि कौर से सदस्य बदले जाते हैं।

कांबली को बोलने और चलने में परेशानी, भाई ने प्रशंसकों से दुआ करने की अपील की

मुम्बई। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली की हालत गंभीर बनी हुई है। कांबली के भाई ने प्रशंसकों से अपील की है कि वह उनके लिए दुआ करें। कांबली पिछले काफी समय से बीमार हैं। पिछले साल एक कार्यक्रम में वह बड़ी मुश्किल से चलते दिखे थे और तब सचिन तेंदुलकर से भी उनकी मुलाकात हुई थी। तब भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने उनका समर्थन करते हुए कहा था कि कांबली उनके बेटे की तरह हैं और वह उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद गावस्कर की सहायता से उनका इलाज भी होने लगा था। अब उनके छोटे भाई वीरेंद्र ने उनकी खराब हालत की जानकारी दी है। एक कार्यक्रम में कांबली के छोटे भाई ने कहा कि वह अभी अभी भी अपनी स्वास्थ्य समस्याओं से पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं और बांद्रा स्थित अपने घर में इलाज करार रहे हैं।

दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर प्रेनेलन के एक्शन पर सवाल उठे

नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीकी ऑफ स्पिनर प्रेनेलन सुब्रायन के एक्शन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान ही संदिग्ध पाया गया है। इससे उनकी गेंदबाजी पर भी सवाल उठे हैं। इसकी रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को भी की गयी है। आईसीसी ने इसी को लेकर एक बयान में कहा, ''मैच अधिकारियों की रिपोर्ट में सुब्रायन के गेंदबाजी एक्शन पर पर सवाल उठाये गये हैं। '' स्पिनर प्रेनेलन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले एकदिवसीय मैच में 46 रन देकर एक विकेट लिया था जिससे दक्षिण अफ्रीका ने 98 रन से जीत दर्ज करने के साथ ही तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।

शुभमन को भविष्य में टी20 कप्तान बनाया जाना तय - गावस्कर

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा है कि शुभमन गिल को एशिया कप के लिए उपकप्तान बनाये जाने से साफ हो गया है कि वह भविष्य में टी20 प्रारुप की भी कप्तान संभालेंगे। गावस्कर ने शुभमन को उपकप्तानी सौंपने को सही फैसला बताया और कहा कि ये गिल को एक संकेत भी है कि भविष्य में आपको टी20 टीम की भी कमान सौंपी जा सकती है, इसलिए वह तैयार रहें। वहीं गावस्कर ने यशस्वी जायसवाल को एशिया कप 2025 के लिए भारतीय दल में नहीं चुने जाने पर टिप्पणी नहीं की और कहा कि इस प्रकार की बातों से बेवजह विवाद होते हैं। गावस्कर ने कहा कि दल का ऐलान होने से पहले लोग अपनी राय रख सकते हैं पर एक बार जब उसकी घोषणा हो जाए तो किसी खिलाड़ी के नहीं चुने जाने पर राय देने का कोई मतलब

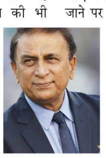

नहीं हैं। इससे केवल विवाद ही पैदा होता है जो कोई भी खिलाड़ी कभी नहीं चाहता। गावस्कर ने कहा, 'आप मैच में केवल 11 खिलाड़ियों को चुन सकते हैं और दल में 15 खिलाड़ी। ऐसे में कुछ को जगह नहीं मिलेगी। अब यह हमारी टीम है। हम सभी की चयन से पहले अपनी राय हो सकती है लेकिन एक बार जब चयन समिति टीम चुन लेती है तो हमें उनका पूरी तरह समर्थन करना चाहिए।'

गावस्कर टी20 में गिल की वापसी और उपकप्तान बनाए जाने से बिल्कुल भी हैरान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनके चयन का फैसला बहुत ही अच्छा है। गावस्कर ने कहा, उन्हें उपकप्तानी सौंपना भी एक तरह से उन्हें यह बताने का तरीका है कि भविष्य में आप टी20 टीम का भी नेतृत्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छाचुनाव है। टी20 विश्व विजेता टीम का हिस्सा होने के बावजूद जायसवाल को एशिया कप के लिए नहीं चुना गया है। दूसरी तरफ विश्व कप में रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में रहे शुभमन गिल को न सिर्फ स्क्वाड में रखा गया है बल्कि उन्हें उपकप्तान भी बनाया गया है, जिसपर भी सवाल उठे हैं।

युवा बोले, श्रेयस को मिलनी चाहिये थी टीम में जगह

नई दिल्ली। अगले माह होने वाले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को भारतीयय टीम मे अवसर नहीं देने पर युवाओं के के साथ ही पूर्व क्रिकेटरों ने भी नाराजगी जतायी हे। भारतीय टीम सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में एशिया कप में उतरेंगी। वहीं शुभमन गिल उपकप्तान होंगे। ये टूर्नामेंट 9 सितंबर को यूएई में में खेला जाएगा। इस बार कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार इस टूर्नामेंट में उतरेंगे, इसमें अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, जितेंद्र शर्मा, रिंकू सिंह आदि है। कई युवा क्रिकेटरों का मामना है कि यशस्वी जायसवाल को भी बाहर रख कर गलती की गयी है। उन्होंने कहा कि टीम में शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं।

एशिया कप में भाग लेने भारतीय टीम को नहीं रोकेंगे - खेल मंत्रालय

नई दिल्ली। खेल मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि पाकिस्तान से द्विपक्षीय खेल नहीं होंगे, मगर एशिया कप में भारतीय टीम को भाग लेने से रोका नहीं जा सकता है। खेल मंत्रालय ने भारत के अंतरराष्ट्रीय खेल संबंधों के संबंध में नई नीति जारी की है। सूत्रों के अनुसार यह नीति तुरंत प्रभावी हो गई है। , खेल मंत्रालय की नीति में कहा गया है, पाक से जुड़े खेल आयोजनों में भारत का रवैया उसी व्यापक नीति को दिखाता है जो उस देश के साथ भारत के संबंधों में अपनाई गई है। जहां तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय खेल आयोजनों का सवाल है, तो भारतीय टीम पाकिस्तान में होने वाले मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेगी। पाकिस्तान की टीम को भारत में द्विपक्षीय मैच खेलने की अनुमति नहीं पाएंगी।

हालांकि, बहुपक्षीय खेल आयोजनों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंत्रालय ने कहा, हम भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप में खेलने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि यह एक बहुदेशीय प्रतियोगिता है। उन्होंने आगे कहा, पाक को द्विपक्षीय मुकाबलों के लिए भारतीय धरती पर खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन बहुपक्षीय आयोजनों में उनकी भागीदारी पर रोक नहीं होगी क्योंकि हम ओलंपिक चार्टर का पालन करेंगे।

इससे एशिया कप में भारतीय टीम के खेलने को लेकर रहा सहा संशय भी समाप्त हो गया है क्योंकि एशिया कप के लिए टीम की घोषणा के बाद से ही इसका विरोध भी तेज हो गया था। प्रशंसकों का मानना था कि क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को होने वाले मैच से पीछे हट जाना चाहिए। प्रशंसकों के अनुसार आतंक वाद जारी रहने तक पाक के साथ किसी भी तरह का कोई खेल या कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए। वहीं खेल मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि पाक के साथ द्विपक्षीय खेल मुकाबले नहीं होंगे, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप में खेलने से नहीं रोका जाएगा।

हरमनप्रीत की कप्तानी में एशिया कप में उतरेगी भारतीय पुरुष हॉकी टीम

नई दिल्ली। ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम इस माह के अंत में बिहार के राजगीर में होने वाले एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में उतरेगी। इस टूर्नामेंट के लिए 18 सदस्यीय भारतीय पुष्ष टीम में फॉरवर्ड शिलानंद लाकड़ा और दिलप्रीत सिंह को भी शामिल किया गया है। एशिया कप 29 अगस्त से सात सितंबर तक खेला जाएगा। इसमें विजेता टीम को अगले साल नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले एफआईएच पुरुष वर्ल्ड कप में सीधे प्रवेश मिलेगा। टीम में राजिंदर सिंह, लाकड़ा और दिलप्रीत सिंह को भी शामिल किया गया है। इस टूर्नामेंट में गोलकीपिंग की जिम्मेदारी कृशन बी पाठक और सूरज करकेरा पर रहेगी। डिफेंस में हरमनप्रीत और अमित रोहिदास के साथ जरमनप्रीत सिंह, सुमित, संजय और जुगाज सिंह भी शामिल हैं। मिडफील्ड में मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद, राजिंदर, राज कुमार पाल और हार्दिक सिंह होंगे। फॉरवर्ड की जिम्मेदारी मनदीप सिंह, अभिषेक, सुखजीत सिंह, लाकड़ा और दिलप्रीत जिम्मा संभालेंगे। वहीं नीलम संजीप सेस और सेल्वम कार्ति को रिजर्व के तौर पर रखा गया है। भारतीय टीम को एशिया कप में जापान, चीन और कजाखस्तान के साथ पूल ए में रखा गया है। भारतीय टीम अपना पहला मैच 29 अगस्त को चीन से खेलेगी। इसके बाद उसे 31 अगस्त को जापान और एक सितंबर को कजाखस्तान से खेलना है।

टीम इस प्रकार है-

मिडफील्ड- मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद,राजिंदर, राज कुमार पाल और हार्दिक सिंह।

डिफेंडर- हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जरमनप्रीत सिंह, सुमित, संजय और जुगराज सिंह।

फॉरवर्ड- मनदीप सिंह, अभिषेक, सुखजीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा और दिलप्रीत सिंह।

गोलकीपर- सूरज करकेरा, कृशन बी पाठक।

रिजर्व खिलाड़ी- नीलम संजीप सेस और सेल्वम कार्ति।

धनश्री की इमोशनल पोस्ट के बाद चहल की प्रतिक्रिया आई

नई दिल्ली। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा के बीच तलाक के बाद भी सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। सबसे पहले चहल ने तलाक के समय पहनी अपनी टीशर्ट बी योर ओन शुगर डैडी से बिन कुछ कहे ही एक संदेश दिया था। चहल ने कुछ ऐसी तस्वीरें भी साझा की हैं, जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रही हैं। इसके बाद धनश्री ने कहा कि तलाके फैसले के बाद वह अदालत में जोर-जोर से रोने लगीं थीं। धनश्री ने चहल के साथ अपने पांच सालों की शादीशुदा जिंदगी को समाप्त करने के दर्दनाक पलों के बारे में भी बताया। धनश्री बताया कि जब फैसला सुनाया जाने वाला था, तो वह सबके सामने रोईं' थी। यह उनके लिए बहुत कठिन दौर था। तलाक की सुनवाई के दौरान उन्होंने चहल के टी-शर्ट वाले स्टंट पर भी प्रतिक्रिया दी। वहीं चहल ने सोशल मीडिया में पहाड़ों के बीच पोज देते हुए अपनी कई तस्वीरें

शेयर कीं। पहली तस्वीर में वे बाहें फैलाए हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीरों में वे पहाड़ों को निहारते हुए गहरी सोच में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं हालांकि, सबसे ज्यादा ध्यान उनके इस स्लोगन ने खींचा जिसमें उन्होंने लिखा, 'मिलियन वर्डस जीरो फीलिंग्स' धनश्री ने अपने पांच साल के रिश्ते के अंत की कहानी शेयर की। उन्होंने बताया कि कोर्ट में जब फैसले का समय आया, तब भी वे खुद को संभाल नहीं पाईं. उन्होंने कहा- 'मानसिक तौर पर पूरी तरह तैयार होने के बावजूद मैं जोर-जोर से रोने लगी थी। वो समय बेहद भारी था।' धनश्री ने यह भी कहा कि उस दिन मीडिया की भीड़ से बचने के लिए वे पिछले दरवाजे से बाहर निकलीं। उन्होंने चहल के टी-शर्ट पर भी लिखे स्लोगन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा- 'भाई, व्हाट्सऐप कर देते, कोर्ट में टी-शर्ट पहनने की क्या जरूरत थी?'

गौरतलब है कि चहल और धनश्री की मुलाकात साल 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन हुई थी। दिसंबर 2020 में दोनों ने गुड़गांव में धूमधाम से शादी की पर एक समय बाद ही दोनो में दूरियां आने लगीं। फरवरी 2025 में दोनों को मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट के बाहर देखा गया।

भारत के गिरीश ने एशियाई निशानेबाजी में स्वर्ण जीता

शिमकेन। भारतीय निशानेबाज गिरीश गुप्ता ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। गिरीश ने 10 मीटर एयर पिस्टल यूथ इवेंट में 241.3 अंक के साथ ही स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 17 साल के गिरीश ने ये उपलब्धि अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में ही हासिल की है। गिरीश ने फाइनल में 241.3 अंक हासिल कर नंबर एक स्थान हासिल किया। इस प्रदर्शन के बल पर इस खिलाड़ी ने भारत के लिए एक पदक जीता है। गिरीश ने व्यक्तिगत स्वर्ण के साथ-साथ 10 मीटर एयर पिस्टल यूथ टीम इवेंट में रजत पदक और मिश्रित युगल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक भी जीता।

मंत्रियों के समूह ने जीएसटी के 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के स्लैब को दी मंजूरी... आम आदमी को मिलेगी राहत!

जीएसटी में खत्म होंगे 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाले स्लैब

नई दिल्ली। जीएसटी रेट्स को युक्तिसंगत बनाने को लेकर मंत्रिसमूह की गुरुवार को हुई एक खास बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रस्ताव के तहत अब जीएसटी में दो स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर दिए जाएंगे। बाकी 12 प्रतिशत और 18 फीसदी को हटा दिया जाएगा।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय मंत्रिसमूह ने 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की मौजूदा चार दरों वाली स्ट्रक्चर को 2 स्लैब से बदलने की योजना को स्वीकार कर लिया है। 5 प्रतिशत अच्छी वस्तुओं और सेवाओं के लिए, 18 प्रतिशत टैक्स मानक वस्तुओं के लिए होगा। वहीं तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स पर 40 प्रतिशत हाई रेट लगेगा। यानी 12 और 18 प्रतिशत वाले टैक्स स्लैब खत्म हो सकते हैं। पैनल ने यह भी सिफारिश की है कि लक्जरी कारों पर 40 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाए, जो पहले 50 फीसदी से ज्यादा था। मंत्री समूह के सदस्यों में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा और केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल शामिल हैं।

आम आदमी को मिलेगी राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जीएसटी में इस बदलाव से मिडिल क्लास, किसानों और एमएसएमई को बड़ी राहत मिलेगी, साथ ही एक सरल, पारदर्शी टैक्स स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर जीएसटी काउंसिल इसकी मंजूरी देता है तो 12 फीसदी के तहत 99 प्रतिशत वस्तुओं को 5 फीसदी वाले टैक्स स्ट्रक्चर में डाला जाएगा। जबकि 28 प्रतिशत रेट्स वाले 90 फीसदी वस्तुओं की कैटेगरी चेंज करके 18 फीसदी वाले कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इससे वस्तुओं के दाम में कमी आएगी। केंद्र का तर्क है कि इस बदलाव से जीएसटी सरल होगा और नियम पालने करने वालों की संख्या बढ़ेगी।

बीमा और हेल्थ पर टैक्स छूट से 9700 करोड़ का बोझ

मंत्री समूह ने व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी छूट देने के केंद्र के प्रस्ताव की भी समीक्षा की, जिससे सालाना लगभग 9,700 करोड़ का राजस्व प्रभाव पड़ सकता है। अधिकांश राज्यों ने इस योजना का सपोर्ट किया है। लेकिन यह भी कहा है कि इसका लाभ सीधे पॉलिसी होल्डर्स को मिलना चाहिए, हालांकि अभी ये अंतिम फैसला नहीं है, यह सिर्फ सिफारिश है. जीएसटी काउंसिल द्वारा अपनी आगामी बैठक में अंतिम मंजूरी के लिए इन सिफारिशों पर विचार किए जाने की उम्मीद है।

रोजाना इस्तेमाल की चीजें सस्ती होंगी

सम्राट चौधरी ने कहा कि हम नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे, रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएगी, लोगों को बहुत फायदा होगा। एक्सपर्ट के मुताबिक सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, सामान्य एंटीबायोटिक्स, पेनकिलर दवाएं, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क, कुछ मोबाइल, कुछ कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर जैसी चीजें सस्ती होंगी। इनके अलावा बिना बिजली वाले पानी के फिल्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, 1000 रुपए से ज्यादा के रेडीमेड कपड़े, 500-1000 रुपए की रेंज वाले जूते, ज्यादातर वैक्सीन, एचआईवी/टीबी डायग्नोस्टिक किट, साइकिल, बर्तन पर भी कम टैक्स लगेगा। ज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे, ग्लोब, ग्लेज्ड टाइल्स, प्री-फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, वेंडिंग मशीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन, कृषि मशीनरी, सोलर वॉटर हीटर जैसे प्रोडक्ट भी 12 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में आते हैं। दो स्लैब की मंजूरी के बाद इन पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा। वहीं सीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट, चॉकलेट, रेडी-मिक्स कंक्रीट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, डिशवॉशर, निजी विमान, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, चीनी सिरप, कॉफी कॉन्सेंट्रेट, प्लास्टिक प्रोडक्ट, रबर टायर, एल्युमिनियम फॉयल, टेम्पर्ड ग्लास, प्रिंटर, रेजर, मैनिक्योर किट, डेंटल फ्लॉस भी सस्ते होंगे।

इंदिरा गांधी सरकार में हुए संशोधन ने राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प बना दिया

नई दिल्ली। दागी पीएम-सीएम और मंत्रियों को हटाने वाले बिल पर हो रहे हंगामे के बीच केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर हमला बोला है और 1976 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लाए गए 42वें संविधान संशोधन की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस संशोधन ने राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प बना दिया, जबकि अदालतों की शक्तियों को कम कर दिया गया और संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को शामिल करके बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान को नष्ट कर दिया गया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुबे ने एक्स पर लिखा- क्या पीएम, सीएम या मंत्री जेल जाने के बाद भी सरकार चला सकता है? कांग्रेस विपक्ष के साथ मिलकर नया खेल कर रही है। 1976 में इंदिरा गांधी का यह 42वां संविधान संशोधन विधेयक है, इसने बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे संविधान को खत्म कर दिया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के रबड़ स्टाम्प हो गए, सुप्रीम कोर्ट पंगु हो गया, संसद और संसद सदस्यों का अधिकार विदेश नीति, रक्षा नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर खत्म हो गया, ज़मीन, मकान पर गरीबों का अधिकार खत्म।

उन्होंने लिखा- राहुल गांधी के कुत्सित और घृणित मानसिकता का विश्लेषण का वक्त है। देश तोड़ने वाले ताकतों को सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन पैसा देकर यह कुटील चाल चल रहा है। दुबे ने इससे पहले, 29 जुलाई को संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने की अनुमति देने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की थी। एक दिन पहले लोकसभा में पेश विधेयक में प्रस्तावित किया गया है कि पांच साल या उससे जयादा की सजा वाले आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार किए गए और लगातार 30 दिन हिरासत में रखे गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को 31वें दिन पद से हटा दिया जाएगा।

बिल के प्रावधानों के मुताबिक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को हटाएंगे, राज्यपाल मुख्यमंत्रियों को हटाएंगे और उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को हटाएंगे। हालांकि, बुधवार को लोकसभा में पेश किए गए इस बिल को सदन ने अध्ययन के लिए जेपीसी को भेज दिया गया है। बिल में कहा गया है कि अगर 31वें दिन तक कोई इस्तीफा या हटाने की सलाह नहीं दी जाती है, तो 32वें दिन पद खुद ही पद से हटा जाएंगे। हिरासत से रिहाई के बाद पुनर्नियुक्ति की अनुमति भी है।

क्या राज्यपाल के विवेकाधिकार के भरोसे रहनी चाहिए चुनी हुई सरकार?

नई दिल्ली,। राष्ट्रपति की ओर से दाखिल रेफरेंस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यपालों की शक्तियों को लेकर अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि किसी भी राज्य की चुनी हुई सरकार को पूरी तरह से राज्यपाल के विवेकाधिकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि क्या चुनी हुई सरकार हमेशा राज्यपाल के भरोसे रहेगी? क्या राज्यपाल किसी बिल को अनिश्चितकाल तक रोककर रख सकते हैं? यह न तो विधानसभा के लिए सही है और न ही राज्यपाल के हित में। दरअसल, राष्ट्रपति की ओर से दाखिल रेफरेंस में सवाल उठाया गया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट यह आदेश दे सकता है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति तय समयसीमा में ही किसी बिल पर फैसला लें।

अमेरिका की फरार महिला भारत में गिरफ्तार, बेटे की हत्या कर भागी थी

एफबीआई की टॉप मोस्ट वांटेड सूची में थी शामिल, 2.17 करोड़ का था इनाम

नई दिल्ली। अमेरिका के मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक सिंडी रोड्रिग्ज सिंह को भारत में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी की पुष्टि खुद अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई (एफबीआई) ने की है। 40 साल की सिंडी पर हत्या, कानून से झूठ बोलकर बचने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फरार रहने जैसे गंभीर आरोप हैं।

बता दें सिंडी का जन्म 1985 में अमेरिका के टेक्सास में हुआ था। वह लंबे समय से एफबीआई की टॉप 10 मोस्ट वांटेड सूची में शामिल थी। उस पर आरोप है कि उसने 2022 में अपने 6 साल के बेटे नोएल की हत्या कर दी थी। नोएल को अक्टूबर 2022 में आखिरी बार देखा गया था, लेकिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मार्च 2023 में दर्ज की गई थी। जब टेक्सास के चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने नोएल की वेलफेयर चेक के लिए पुलिस से संपर्क किया, तो बच्चे की जानकारी नहीं मिली।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिंडी ने जांच एजेंसियों को गुमराह करते हुए कहा था कि नोएल अपने पिता के साथ मेक्सिको में है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को शक हुआ और जांच शुरू की। सिंडी की शादी एक भारतीय नागरिक अर्शदीप सिंह से हुई थी, जिससे उसके 7 बच्चे थे। जब उसने अमेरिका छोड़ने का प्लान बनाया, तो वह अपने पति और 6 बच्चों को लेकर भारत भाग गई नोएल को पीछे छोड़कर। 31 अक्टूबर 2023 को अमेरिका की एक अदालत ने सिंडी पर हत्या का आरोप लगाया और नवंबर 2023 में उसके खिलाफ फेडरल गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। शुरुआत में एफबीआई ने सिंडी की जानकारी देने पर 25,000 डॉलर यानी लगभग 21.75 लाख का इनाम रखा था। बाद में यह इनाम बढ़ाकर 250,000 डॉलर यानी करीब 2.17 करोड़ कर दिया गया।

शाह से कपिल सिब्बल ने पूछा सवाल....आपके कोई मंत्री के खिलाफ कभी कोई एफआईआर हुई?

नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार मंत्रियों को हटाने संबंधी तीन विधेयक पेश करने पर बड़ा बयान दिया है। सांसद सिब्बल ने कहा कि लोकतंत्र को बर्बाद करना इनका मूल मकसद है। सुप्रीम के वरिष्ठ वकील सिब्बल ने कहा कि इस बिल के लागू होने से मानक अधिकारों को वे छीनना चाहते हैं। लोकतंत्र को बर्बाद करना इनका मकसद है। बिहार में इन्होंने किस तरह से एसआईआर लागू किया और किस तरह से मतदाता सूची बन रही है..इससे मतदाता सूची को दीमक लग जाएगा। तब चुनाव होगा कैसे?

सिब्बल ने कहा कि आखिर इनकी मंशा क्या है? आपको पता है कि अगर किसी पर एफआईआर होती है, तब सीधे गिरफ्तार किया जाता है और ये जो नया कानून है अगर किसी को हिरासत में ले लिया जाए, तब सालों लग जाते हैं बेल लेने में।

सिब्बल ने आप नेताओं झारखंड के सीएम का जिक्र कर कहा कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन ये सब उदाहरण हैं। तब मैं गृह मंत्री शाह से पूछना चाहता हूं कि आपके कोई केंद्र के मंत्री के खिलाफ कभी कोई एफआईआर हुई? और जिस प्रदेश में आप सरकारें चला रहे हैं वहां पर किसी मंत्री के खिलाफ एफआईआर हुई ?.आप ये न समझना कि जनता समझती नहीं है।

बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया। इस बिल को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद विधेयक को एक संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 में प्रधानमंत्री, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को गंभीर अपराध के आरोपों में पद से हटाने का प्रावधान है।

विधेयक में कहा गया है कि कोई भी मंत्री जो किसी गंभीर अपराध के लिए, 30 दिनों तक जेल में रहा है, उस मंत्री को अपना पद खोना होगा। विधेयक के अनुसार, किसी मंत्री को जो तीन दिनों तक जेल में रहा हो और इसतरह के आरोप में गिरफ्तार हुआ हो जिसकी सजा पांच साल या उससे अधिक है, उस मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। संबंधित मंत्री को 31वें दिन तक मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटा दिया जाएगा। यदि इसतरह के मंत्री को हटाने के लिए मुख्यमंत्री की सलाह 31वें दिन तक राष्ट्रपति को नहीं दी जाती है, तब वह उसके बाद आने वाले दिन से मंत्री नहीं रहेगा।

ई-वॉलेट्स से चंदा वसूली करने में जुटा जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर

नई दिल्ली। भारत में बीते दो दशकों से ज्यादा समय से सीमा पार आतंकवाद फैलाने में जुटे जैश-ए-मोहम्मद ने अब फंडिंग जुटाने के नए तरीके खोज लिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने उसके ठिकानों पर हमले किए थे। उसका मुख्यालय तक तबाह किया था। अब यह आतंकी संगठन फिर से सिर उठा रहा है और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की नजर न पड़े, इसके लिए भी नए-नए पैंतरे अपना रहा है। इसी कड़ी में अब ई-वॉलेट्स से चंदा वसूली शुरू कर दी है। ऐसा इसलिए ताकि पेमेंट्स को ट्रैक न किया जा सके। पाकिस्तान में प्रचलित ई-वॉलेट्स के के माध्यम से यह रकम अजहर के परिवार के लोगों के खाते में जुटाए जा रहे हैं।

यही नहीं ई-वॉलेट्स पर नए-नए अकाउंट बनाए जा रहे हैं ताकि किसी में भी एक साथ ज्यादा पेमेंट ना आए। इसी के तहत पाकिस्तान में आतंकवाद का नया ढांचा खड़ा हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार आतंकी समूह एक समय में 7 से 8 ई-वॉलेट्स को सक्रिय रखता है। इसके बाद करीब 4 महीने में पुराने अकाउंट्स को बंद कर देता है और फिर हर महीने 30 नए खाते खोले जाते हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर इस बार 3.9 अरब रुपये जुटाने की तैयारी में है। इतना ही नहीं इस रकम से वह पूरे पाकिस्तान में 313 सेंटर बनाने की तैयारी में है।

आतंकी संगठन जैश की तैयारी है कि एक मुख्यालय बनाए, लेकिन उसके साथ तमाम सैटेलाइट सेंटर खोले जाएं। दरअसल इस बार जैश-ए-मोहम्मद भारत के हमलों से बचने के लिए एक ही बड़ा मुख्यालय बनाने की तैयारी में नहीं है। अब आतंकी को लगता है कि नेटवर्क को थोड़ा विस्तृत बनाया जाए। इसी के तहत के कुछ काम वह अंडरग्राउंड ही करेगा। खबर है कि जुटने वाली 3.9 अरब की फंडिंग में से जैश-ए-मोहम्मद 1.23 अरब पाकिस्तानी रुपये अपने ठिकाने तैयार करने के लिए इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा बाकी रकम को हथियारों की खरीद और अन्य ऑपरेशन के लिए करेगा।

मंदिर परिसर से मेडिकल छात्रा के लापता होने की जांच एसआईटी करेगी

-बीजेपी नेता ने कांग्रेस सांसद को बताया दुष्प्रचार करने का मास्टरमाइंड!

बैंग्लुरु। मंदिर परिसर से 2003 में मेडिकल छात्रा अनन्या भट्ट के रहस्यमय ढंग से लापता होने का मामला और सामूहिक दफनाने के मामले की जांच एसआईटी करेगी। अनन्या की मां ने 15 जुलाई, 2025 को धर्मस्थल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें अधिकारियों से दोबारा जांच करने का आग्रह किया था और आरोप लगाया गया था कि लंबे समय से न्याय नहीं मिल रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 19 अगस्त को कर्नाटक के पुलिस महानिरीक्षक ने एक आदेश जारी कर मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी थी। इस बीच पुलिस महानिदेशक और एसआईटी के प्रमुख ने बुधवार को चल रही जांच की समीक्षा के लिए बेलथांगडी का दौरा किया। सूत्रों ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी ने मामले से संबंधित दस्तावेजों की जांच की और अब तक हुई प्रगति का आकलन किया।

रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के बीजेपी विधायक जी जनार्दन रेड्डी ने तमिलनाडु के तिरुवल्लूर से कांग्रेस के सांसद शशिकांत सेंथिल पर हमला बोलते हुए उन पर दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित कस्बे धर्मस्थल के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी सेंथिल को चुनौती दी कि अगर सामूहिक रूप से लाशों को दफनाने से जुड़े दुष्प्रचार से कोई संबंध नहीं है, तो उन्हें जांच का सामना करना होगा।

कर्नाटक सरकार ने पिछले दो दशकों में धर्मस्थल में कई हत्याओं, बलात्कारों और अवैध तरीके से लाशों को दफनाने के आरोपों के बाद एसआईटी का गठन किया था। मामले में शिकायतकर्ता एक पूर्व सफाई कर्मचारी है, जिसकी पहचान उजागर नहीं की गई है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि वह 1995 से 2014 के बीच धर्मस्थल में कार्यरत था। उसने आरोप लगाया कि उसे कई शवों को दफनाने के लिए मजबूर किया गया था, जिनमें महिलाओं और नाबालिगों के शव भी शामिल थे।

रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता का दावा है कि इनमें से कुछ के शवों पर यौन उत्पीड़न के निशान थे। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर के मुताबिक दो स्थानों पर हड्डियां और कंकाल मिले हैं और पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रेड्डी ने दावा किया था कि सेंथिल धर्मस्थल को बदनाम करने के दुष्प्रचार के मास्टरमाइंड हैं। रेड्डी ने कहा कि मेरे आरोप लगाने के बाद सेंथिल ने नई दिल्ली में बयान दिया था कि जब वह बेल्लारी में सहायक आयुक्त के पद पर कार्यरत थे, तो उन्होंने मुझसे संबंधित कुछ मामलों में समर्थन में रिकॉर्ड उपलब्ध कराए थे।

सेंथिल पर एक बार फिर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए बीजेपी विधायक ने कहा कि जब खनन से संबंधित मामले में रेड्डी के खिलाफ मुकदमे शुरू हुए थे तब सेंथिल सहायक आयुक्त नहीं थे। रेड्डी ने कहा कि मुझे 5 सितंबर, 2011 को गिरफ्तार किया गया था। मेरी गिरफ्तारी के बाद सेंथिल को बेल्लारी में तैनात किया गया।

सांसदों से वसूला जाए संसद सत्र का खर्च

नई दिल्ली। संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहा। लोकसभा में चर्चा के लिए 120 घंटे का समय तय था, लेकिन चर्चा हुई महज 37 घंटे ही। इसमें भी बड़ा हिस्सा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का है। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन एक निर्दलीय सदस्य ने सदन में गतिरोध के लिए सांसदों के वेतन में कटौती की मांग करते हुए संसद भवन परिसर में प्रोटेस्ट किया।

केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के निर्दलीय सांसद उमेश पटेल ने गुरुवार को एक बैनर लेकर प्रोटेस्ट किया। उमेश पटेल ने मांग की है कि सदन की कार्यवाही नहीं चलने देने के लिए इस पर हुए खर्च का पैसा सांसदों की सैलरी से वसूला जाए। उमेश पटेल जो बैनर लेकर पहुंचे थे, उस पर माफी मांगो, सत्ता पक्ष और विपक्ष माफी मांगो लिखा था।

चीन की मीठी-मीठी बातों में नहीं फंसेगा भारत...वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेना की तैनाती हमेशा

नई दिल्ली। चीन के साथ भारत की कूटनीतिक और सैन्य बातचीत के बावजूद, भारत को वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसका कारण चीन की सेना (पीएलए) ने सीमा पर बड़े पैमाने पर अपने सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत किया है, जिससे वे बहुत तेज़ी से अपनी सेना को तैनात कर सकते हैं।

क्यों भारतीय सेना एलएसी पर अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकती-

दरअसल पिछले पाँच सालों में, चीन ने पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एलएससी के करीब सड़कें, पुल, सुरंगें और ठिकाने बना लिए हैं। इस मज़बूत नेटवर्क की मदद से पीएलए के सैनिक 100 से 150 किलोमीटर की दूरी भी सिर्फ 2-3 घंटों में तय कर सकते हैं, जबकि भारतीय सेना के पास ऐसी सुविधा नहीं है।

मई-जून 2020 में पूर्वी लद्दाख में हुई झड़पों के बाद से दोनों सेनाओं के बीच विश्वास की कमी बनी हुई है। उस घटना के बाद से, 3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर भारी मात्रा में हथियार और सेना की तैनाती की गई है। भले ही पीएलए की कुछ ब्रिगेड एलएसी से 100 किलोमीटर पीछे हट गई हैं, लेकिन उनकी बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट अभी भी फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात हैं। इन ब्रिगेड में लगभग 4,500 से 5,000 सैनिक, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, और मिसाइल सिस्टम जैसे आधुनिक हथियार शामिल हैं। सितंबर 2022 में, पूर्वी लद्दाख में कुछ इलाकों में नो पेट्रोलिंग बफर ज़ोन बनाए गए थे। इन क्षेत्रों में भारतीय सेना पहले गश्त करती थी, लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर सकती, जो भारत के लिए नुकसानदेह है। ये ज़ोन 3 से 10 किलोमीटर तक फैले हैं और भारत इन्हें अपना क्षेत्र मानता है।

भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भले ही तनाव कम करने के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन पीएलए की तैयारियों को देखते हुए भारत को अपनी सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए। सच्चाई ये है कि पीएलए के कुछ कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड (सीएबी) पिछले कुछ महीनों में एलएसी से करीब 100 किलो मीटर पीछे ज़रूर हटे हैं, लेकिन अभी भी कई फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात हैं, जिसमें उनकी बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट भी शामिल हैं। प्रत्येक सीएबी में टैंकों के साथ करीब 4,500-5,000 जवान, बख्तरबंद वाहन, आर्टिलरी के अलावा अन्य वेपन सिस्टम के साथ ही सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम भी शामिल रहते हैं। एलएसी पर जवानों की तैनाती कम करने और उनकी वापसी के लिए, सभी अतिरिक्त टुकड़ियों को उनके शांति काल वाले स्थायी ठिकानों पर वापसी करनी होगी। फिलहाल दोनों देश पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति कायम रखने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तरों पर बातचीत के लिए, मौजूदा बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस इरादे से दोनों ओर से अब एलएसी के पूर्वी (सिक्किम, अरुणाचल) और मध्य (उत्तराखंड, हिमाचल) इलाकों में जेनरल लेवल मैकेनिज्म स्थापित करने का भी फैसला लिया है, जो कि पश्चिम (लद्दाख) में भारत के 14वीं कोर कमांडर और साउथ शिनजियांग डिस्ट्रिक्ट चीफ के मौजूदा वार्ता तंत्र के अलावा होगा।

अमित शाह और राजनाथ सिंह को मिली ये अहम जिम्मेदारी...विजन 2047 को लेकर

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में सुधारों के सुझाव देने के लिए दो नए अनौपचारिक मंत्री समूह गठित किए हैं। शाह को आर्थिक सेक्टर की जवाबदारी दी गई है। इस समूह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सहित 13 सदस्य हैं, जबकि रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव इस समूह के संयोजक बने हैं। यह समूह वित्त, उद्योग, वाणिज्य अवसंरचना, रसद, संसाधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और शासन सहित प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षेत्रों में विधायी और नीतिगत सुधार एजेंडा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। वहीं, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा क्षेत्रों पर गठित दूसरे 18-सदस्यीय समूह का नेतृत्व रक्षा मंत्री सिंह करने वाले हैं। यह समूह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा, कौशल विकास, सामाजिक कल्याण, आवास, श्रम, जन स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में सुधारों की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करेगा। इस समूह में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और श्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया को संयोजक बनाया गया है।

इन समूहों का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के बाद हुआ है, जहां उन्होंने अपनी स्पीच में अगली पीढ़ी के सुधारों की आवश्यकता पर जोर देकर एक टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि मौजूदा नियमों, कानूनों, नीतियों और प्रक्रियाओं को 21वीं सदी के अनुसार वैश्विक परिवेश के अनुकूल और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप नए सिरे से तैयार किया जाना चाहिए।

पोस्टमार्टम करवाने के लिए जिला अस्पताल में परेशान होते रहे परिजन

थाने से ओटीपी आने के बाद ही होगा शव का पोस्टमार्टम, पुलिस विभाग ने जारी किए नए नियम

बालाघाट(पद्मेश न्यूज)। जिला चिकित्सालय में अब किसी भी व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए ओटीपी आने का इंतजार करना होगा। पोस्टमार्टम करवाने के लिए अब पुलिस विभाग ने नए नियम जारी किए हैं। इन नियम के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शव का पोस्टमार्टम तभी होगा, जब उस व्यक्ति के क्षेत्र से संबंधित थाने की पुलिस द्वारा ओटीपी अस्पताल चौकी पुलिस को भेजी जायेगीं । जिस कारण जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाने आए परिजनों को ओटीपी आने का इंतजार घंटों तक करना पड़ा। जिस कारण उन्हें काफी परेशानी हुई । संबंधित विभाग के अधिकारी भी बता रहे हैं कि यह नियम अभी नए आए हैं।

आपको बता दे की मध्यप्रदेश शासन ने 21 अगस्त से नया नियम लागू किया है। इस नियम के तहत अब पुलिस से संबंधित प्रकरण जिला अस्पताल में पहुंचने पर अस्पताल चौकी पुलिस के द्वारा प्रदेश स्तर के पोर्टल पर आन लाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और फिर संबंधित थाना आनलाइन ओटीपी भेजेगा , जिसके बाद संबंधित चिकित्सक एमएलसी की कार्रवाई को पूर्ण करेगा। इस प्रक्रिया के पहले दिन ही एक युवक के पोस्टमार्टम के दौरान परिजनों को ओटीपी के लिए सुबह से लेकर दोपहर करीब एक बजे तक इंतजार करना पड़ा। जिसके चलते परिजन न सिर्फ रोते-बिलखते रहे बल्कि शव को घर ले जाने के लिए परेशान भी होते रहे। मिली जानकारी के अनुसार नंदकिशोर पिता ब्रजलाल पटले 44 वर्ष ग्राम नगरवाड़ा थाना चांगोटोला निवासी है, जो कि खेती-किसानी का काम करता था। बुधवार की सुबह करीब 11 बजे वह खेत में लगी फसल में कीटनाशक का छिड़कांव करने गया था, यहां दोपहर करीब दो बजे वह घर आया, दोपहर करीब तीन बजे उसकी अचानक से तबियत खराब हो गई। जिस पर परिजन उसको शाम के

समय उपचार के लिए लामता अस्पताल लेकर गए, यहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसकी रात के समय अधिक तबियत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल परिजन लेकर पहुंचे, यहां पर जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई है। जिला अस्पताल में युवक की मौत होने के बाद अस्पताल चौकी पुलिस के स्टाफ ने नये नियम के तहत आनलाइन प्रक्रिया को पूर्ण किया और सुबह करीब 9 बजे युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम कक्ष लाया गया, लेकिन चांगोटोला थाना से आन लाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ओटीपी आना था लेकिन वह ओटीपी नहीं आई, जिसके चलते संबंधित चिकित्सक पोस्टमार्टम नहीं कर पाया। काफी मशक्त के बाद दोपहर करीब 12 बजे थाना से ओटीपी आई जिसके बाद पोस्ट मार्टम की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। इस तरह सुबह से लेकर दोपहर तक युवक के परिजन पोस्टमार्टम कराने और शव का अंतिम संस्कार किए जाने के लिए घर ले जाने को लेकर परेशान होते रहे।

अब यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है - निलय जैन

सिविल सर्जन डा. निलय जैन ने बताया की मध्यप्रदेश शासन के द्वारा 21 अगस्त से नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत जिस क्षेत्र के व्यक्ति की मौत होने या फिर पुलिस प्रकरण होने पर जिला अस्पताल की अस्पताल पुलिस चौकी से आन लाइन प्रक्रिया को पूर्ण कर उक्त क्षेत्र के थाना को पहुंचाया जाता है और वहां से ओटीपी आने पर संबंधित चिकित्सक एमएलसी या पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा। उन्होंने यह बताया कि पहले यह काम ऑफलाइन होता था ,किंतु अब यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। पुलिस कर्मचारी ऑनलाइन सीसीटीएनएस एप

के माध्यम से पूरी प्रक्रिया होगी ।अब पहले की तरह दूसरा डॉक्टर इस प्रक्रिया में हस्ताक्षर नहीं करेंगे। , निश्चित ही धीरे-धीरे चीज आसान होते जाएगी ।

मोटरसाइकिल सवार दो तस्कर 3 किलो 878 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार

दोनो तस्कर विमल कावड़े और रौनक गजभिए भेजे गए जिला जेल

बालाघाट(पद्मेश न्यूज)। जिले में मादक पदार्थ गांजा की तस्करी के चलते बहेला पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार दो तस्करों को 3 किलो 878 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों तस्कर विमल पिता अशोक कावड़े 21 वर्ष ग्राम हट्टाऔर रौनक पिता परमेश गजभिये 29 वर्ष ग्राम सालेटेका थाना हट्टा निवासी है। जिनके पास है जप्त 3 किलो 878 किलोग्राम गंजे की कीमत 40हजार रुपये बताई गई है। गिरफ्तार दोनों तस्करों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। बहेला पुलिस के मुताबिक 20 अगस्त की शाम मुखबिर जरिये सूचना मिली कि छत्तीसगढ़ राज्य से दो लोग मोटरसाइकिल में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा लेकर बिक्री करने के उद्देश्य से रिसेवाड़ा की ओर आने वाले हैं। मुखबिर की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उप निरीक्षक रामकुमार रघुवंशी के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा वारी जोड़ के पास नाकेबंदी की गई थी। जिसके कुछ देर बाद मुखबिर के बताए हुलिये के बताये अनुसार एक मोटरसाइकिल में दो लोग आते दिखे। जिन्हें इशारा करके मोटरसाइकिल रोकने कहा गया। किंतु मोटरसाइकिल सवार पुलिस टीम को देखकर भागने की फिराक में थे। किंतु पुलिस टीम के द्वारा घेराबंदी कर मोटरसाइकिल सवार को पकड़े। पूछताछ करने पर मोटर साइकिल चला रहेयुवक ने अपना नाम विमल कावड़े तथा मोटरसाइकिल के पीछे बैठे युवक ने अपना नाम रौनक गजभिये बताएं। जिनके पास रखे थैले की

विधिवत तलाशी लेने पर थैली में 3 किलो 878 किलोग्राम गांजा पाया गया । इस मादक पदार्थ गांजे को रखने के संबंध में वैध लाइसेंस अधिकृत दस्तावेज मांगे जाने पर दोनों युवक के पास इस गांजा को अपने आधिपत्य में रखकर परिवहन करने के संबंध में कोई भी अधिकृत वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। दोनों युवक इस मादक पदार्थ गांजा को अवैध रूप से अपने पास रखकर बेचने की नीयत से परिवहन कर ला रहे थे। जिनके विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दोनों को इस अपराध में गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम ने इन दोनों गांजा तस्करों के पास से 3 किलो 878 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा के अलावा इस तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एमपी 50 जेड सी 8085 के अलावा एक वीवो कंपनी का मोबाइल जप्त किये है। जप्त मोटरसाइकिल और मोबाइल की कीमत 90हजार रुपये बताई गई है। 21 अगस्त को बहेला पुलिस ने दोनों तस्कर को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिए जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है।मादक पदार्थ गांजा के दोनों तस्कर को पकड़ने कि इस कार्रवाई में उप निरीक्षक हेमंत शर्मा प्रधान आरक्षक सुरेश पांचे, आरक्षक राजकुमार सिसोदिया, आरक्षक संजयमकवाना, आरक्षक सुनील कुमार, आरक्षक सौरभ शर्मा एवं आरक्षक शुभम शर्मा की सराहनीय भूमिका रही।

पैसा ठीक होने के बाद देना
शादी से पहले एवं शादी के बाद
उम्र की अधिकता से कमजोर सेक्स, शीघ्रपतन, स्वप्नदोष, लिंग का छोटापन, टेडापन, निःसंतान, शुक्राणुओं की कमी, शुगर से आयी कमजोरी आदि सभी सेक्स समस्याओं का शर्तिया ईलाज किया जाता है।
पता-जगजीवन आयुर्वेदिक दवाखाना
गुरूनानक पेट्रोल पंप के सामने समाजवाड़ी रोड, बालाघाट, मो. 9243880464

एक लड़की को अपने मंगेतर का फोन रिसीव नहीं करना पड़ा महंगा

मंगेतर ने लड़की से की मारपीट ,दी जान से मारने की धमकी, मारपीट और धमकी देने के आरोप में लड़की का मंगेतर गिरफ्तार

बालाघाट(पद्मेश न्यूज)। एक लड़की को अपने मंगेतर से फोन मे बात नहीं करना और उसका फोन रिसीव नहीं करना उस समय महंगा पड़ गया जब इस लड़की को उसके मंगेतर ने बेरहमीपूर्वक हाथ बुक्के और लकड़ी से मारपीट कर दिया वहीं फोन रिसीव नहीं करने पर जान से मार डालने की धमकी दे दी। यह घटना जिले के बिरसा थाना क्षेत्र की है। इस 18 वर्षीय लड़की द्वारा की गई रिपोर्ट पर बिरसा पुलिस ने उसके मंगेतर विनोद पिता थॉमस खलको 21 वर्ष ग्राम कनिया निवासी के विरुद्ध इस लड़की को मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज कर उसे इस अपराध में गिरफ्तार कर लिये है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिरसा थाना क्षेत्र में आने वाले एक ग्राम में रहने वाली यह 18 वर्षीय लड़की घरेलू काम करती है। इस लड़की के माता-पिता ने विनोद खालको ग्राम कनिया निवासी से शादी के सम्बंध में बात किए थे। और बातें चल रही थी किंतु दोनों की शादी अभी तक नहीं हुई है। विनोद खालको इस लड़की के घर के मोबाइल नंबर में फोन लगाकर कभी कभी बात कर लिया करता था। कभी यह लड़की बात कर लिया करती थी। कई बार ऐसा होता था कि यह लड़की या उसके परिवार के लोग जब मोबाइल से अपने रिश्तेदारों से बात करते थे। उसी समय विनोद खालको का फोन लगाता था। जिससे यह लड़की और उसके परिवार के लोग फोन विनोद खलखो का फोन उठा नहीं पाते थे और वे विनोद खलखो से बात नहीं कर पाते थे। चार दिन पहले यह लड़की अपने रिश्तेदार के घर ग्राम देवगांव काम से गई थी। और शाम 6ः00 बजे यह लड़की अपने रिश्तेदार के घर ग्राम देवगांव से पगडंडी रास्ते से अपने घर आ रही थी। यह लड़की अपने घर के पास पहुंचने वाली ही थी की तभी इस लड़की को उसके मंगेतर विनोद खलखो ने रोका और विनोद खालको ने इस लड़की को अश्लील गालियां देते हुए बोलने लगा कि मेरे फोन को रिसीव नहीं करती, तेरे मां-बाप ने मेरे साथ तेरा रिश्ता तय किके है। यह कहकर विनोद खलखो पेड़ से कच्ची लकड़ी तोड़कर इस लड़की को लकड़ी से इस लड़की को बेरहमी पुर्वक मारपीट करने लगा। हाथ बुक्के से मारपीट कर विनोद खलखो ने इस लड़की के सिर के बाल को जोर से पकड़ कर खींचा जिससे इस लड़की के सर के बाल उखड़ गए। लड़की के चिल्लाने पर मोहल्ले के लोग दौड़े और बीच बचाव किये। इसके बाद विनोद खलको ने इस लड़की को दोबारा फोन रिसीव नहीं करने और किसी दूसरे लड़के से बात करने पर जान से मार डालने की धमकी दे दी।जिसके बाद यह लड़की अपने घर पहुंची । घटना के संबंध में अपने माता-पिता को बताई और रिपोर्ट करने के लिए बिरसा पुलिस थाना पहुंची। बिरसा पुलिस ने इस 18 वर्षीय लड़की द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके मंगेतर विनोद खालखो 21 वर्ष ग्राम कनिया निवासी के विरुद्ध इस लड़की को मारपीट और जान से मार डालने की धमकी देने के आरोप में धारा 296 115(2) 351(3) 126(2) भारतीय न्याय संहिता2023 के तहत अपराध दर्ज किया और इस अपराध में उसे गिरफ्तार कर लिया है।

AICTE भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं RGPV & DTE भोपाल से सम्बध्द
सतपुड़ा इंजीनियरिंग & पॉलिटेक्निक कॉलेज
प्रवेश प्रारंभ
B.Tech. & Polytechnic
- COMPUTER SCIENCE ENGINEERING
- MINING ENGINEERING
- CIVIL ENGINEERING
- MECHANICAL ENGINEERING
- ELECTRICAL ENGINEERING

Lateral Entry Admission NEP 2020 के तहत किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा/B.Sc. (Maths) उत्तीर्ण छात्रों का B.Tech. एवं ITI उत्तीर्ण छात्रों का पॉलिटेक्निक के
द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश
सतपुड़ा कैम्पस, लालबर्रा रोड, गर्रा, बालाघाट
6262604111, 9425836824

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक उमेश बागरेचा द्वारा पद्मेश पब्लिकेशन, वार्ड नं.9, गुजरी चौक, बालाघाट (म.प्र.) से मुद्रित कराकर काली पुतली चौक, बालाघाट से प्रकाशित, संपादक- उमेश बागरेचा, मो.नं. - ९४२५१३८७१० रजि. नं. एम.पी. एच. आई. एन. /२००९/३२३११, न्यायालयीन क्षेत्राधिकार बालाघाट